हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 1990

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

शुक्रवार 16 मार्च, 1990

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(5)1
तारांकित प्रश्न सं. 1100 पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देना	(5)25
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(5)27

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(5)32
विभिन्न विशयो को उठाया जाना	(5)36
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –	
तहसील नारनौल में 11.3.90 को ओलावृश्टि के कारण फसलें नश्ट होने संबंधी	(5)38
वक्तव्य –	
राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(5)38
वर्श 1990–91 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)40
वाक–आउट	(5)75
वर्श 1990–91 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)76
बैठक का समय बढ़ाना	(5)89
वर्श 1990–91 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)89

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 16 मार्च, 1990

विधान सभा की बैठक, हरियणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ मे प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चटठा) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Fair Price Shops

***1049. Sh. Kailash Chand Sharma**: Will the Minister of State for Food and Supplies be pleased to state –

(a) the total number of Fair Price Shops being run by the Government in the State togetherwith the number of employees working therein;

(b) whether the employees working in shops as referred to in part (a) above are being paid their salary regularly; if not, the reasons therefor; and

(c) the criteria adopted for the recruitment of these employees?

खाद्य तथा पूति राज्य मंत्री (श्री नर सिंह ढांडा):

(क) शून्य।

(ख)

तथा सवाल ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग)

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कान्फैड या और दूसरी एजेंसी है जिसके माध्यम से लोगों को सामान वितरित होता हो?

श्री नर सिंह ढ़ांडा: अध्यक्ष महोदय, स्वयं सरकार द्वारा तो उचित दर की दुकानों पर सामान वितरित नहीं किया जा रहा लेकिन प्राईवेट और सहकारी क्षेत्र की दुकानों के जरिए जरूर उचित दरों पर लोगों को सामान वितरित किया जाता है। प्राईवेट होल्डर्ज की और सहकारी क्षेत्र की कितनी–कितनी दुकानें हैं, यदि यह बात ये पूछना चाहेगे, तो वह भी मैं इन्हें बाद में बता दूंगा।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: क्या ये बताएंगे कि सहकारी क्षेत्र की दुकानों के माध्यम से जो सामान उचित दरों पर सप्लाई किया जा रहा है, उनमें काम करने वाले कर्मचारियौं की कितनी संख्या है?

श्री नर सिंह ढ़ांडा: हमारे यहां पर सहकारी क्षेत्र की जो दुकानें हैं, उनको फूड एण्ड सप्लाई डिपार्टमैंट की तरफ से लाईसैंस दे दिया जाता है। उस लाईसैंस के आधार पर ही

सहकारी क्षेत्र की दुकानों द्वारा उचित मूल्य पर लोगों को सामान उपलब्ध करवाया जाता है। इन दुकानों पर कितने कर्मचारी काम कर रहे है, यह फिगर्ज इस समय मेरे पास नहीं हैं।

डा. बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि देहातों में जो डिपू होल्डर्ज हैं, वे बहुत गड़बड़ करते हैं। वहां पर पार्टी–बाजी के नाते डिपू होल्डर्ज अपने विरोधी लोगों को चीनी आदि नहीं देते। मैं मंत्री जी ने जानना चाहूंगा कि यदि ऐसी जगहों से कोई ऐप्लीकेशन्ज आएं तो क्या वहां पर सहकारी क्षेत्र की दुकानें खोलने की बात पर विचार किया जाएगा?

श्री नर सिंह ढ़ांडा: अध्यक्ष महोदय, गांवों में जहां पर भी प्राईवेट होल्डर्ज की दुकानें है, उन पर चैक करने के लिए उस गांव की सरपंच, पटवारी, एक महिला पंच और गांव के एक टीचर को अख्तियार दिया है। वे समय–समय पर चैक करते रहते हैं। अगर फिर भी ये कोई दिक्कत कहीं की समझ रहे हों तो हमें लिख कर दे दें, हम उसकी इन्कवायरी करवा देंगे।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सहकारी क्षेत्र की दुकानों पर लोगों को क्या–क्या सामान दिया जाता है और वह इस साल में कितने रूपये तक का दिया जा चुका है?

श्री नर सिंह ढ़ांडा: सहकारी क्षेत्र की दुकानों के जरिए चावल, गेहूं, चीनी, नियंत्रित कपड़ा, साबुन और कापियां आदि दूसरा काफी सामान दिया जाता है।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं आया कि इन दुकानों के जरिए कितने रूपये का सामान दिया गया? (विघ्न) स्पीकर साहब मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि अब तक 5 हजार रूपये का सामान दिया गया या 5 लाख रूपये का सामान लोगों को दिया गया है।

श्री नर सिंह ढ़ांडा: अध्यक्ष महोदय, फिगर्ज तो इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि कितने रूपये का सामान दिया जा चुका है लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए यह बता देता हूं कि हमारे यहां पर चीनी, गेहूं और चावल की जो ऐलोकेशन होती है उसमें से हमने कितना–कितना सामन उठाया है। गेहूं 3 हजार मीट्रिक टन उठाने की बजाय 3070 मीट्रिक टन उठाया है और चावल 2400 मीट्रिक टन की बजाये 1249 मीट्रिक टन उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें यह भी बता देता हूं कि चालव और घाटा हरियाणा स्टेट से ही पूरा हो जाता है। किसानों या मजदूरों को जितना यह सामान चाहिए, वह यहां से पूरा कर दिया जाता है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि गांवों में जो राशन के डिपू हैं, उनमें चावल–चीनी आदि का सामान महीने के आखिरी सप्ताह में आता

है, जिससे लोग राशन का सामान नहीं खरीद पाते। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या वहां पर महीने के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में चावल–चीनी या आटा भिजवाने का प्रबन्ध करेंगे ताकि लोग आसानी से उचित दर पर यह सामान खरीद सके?

श्री नर सिंह ढ़ांडा: अध्यक्ष महोदय, हमने शुरू में ही उनको पैसा जमा करवाने के लिए हिदायतें दी हुई हैं कि वे पैसा जमा करवा कर चीनी और दूसरी चीजें उठा लें। इसके अलावा गांव के सरपंच, पंच, महिला पंच और टीचर्ज भी उनको चैक करते हैं और हर महीने हमारे इन्स्पैक्टर भी चैक करने के लिए जाते हैं। फिर भी यदि कोई शिकायत, स्पैसिफिक शिकायत इनके नोटिस में हो, तो यह लिख कर दे दें, हम दोशियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राज्य में उचित मूल्य की कितनी दुकानें हैं और इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी हैं और शहरी क्षेत्रों में कितनी हैं? इसके अतिरिक्त में यह भी जानना चाहता हूं कि चीनी का वितरण साल के 12 महीनों में ही किया जाता है या किसी महीने को छोड़ दिया जाता है? जो राशन दिया जाता है वह किन राशन कार्डो पर दिया जाता है?

श्री नर सिंह ढ़ांडा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राज्य 6546 उचित

मूल्य की दुकानें हैं जिनमें से 2038 दुकानें शहरी क्षेत्रों में और 4508 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। 1691 उचित मूल्य की दुकानें सहकारी क्षेत्र में हैं।

श्री रघुबीर सिंह: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से अपने साथी काबिल मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि को–आप्रेटिव सैक्टर के अन्दर कितनी दुकानें बन्द करके प्राईवेट डिपो होल्डरों को उनकी मैनेजमैंट के लिए दी गई है और इन दुकानों के बन्द होने से कितने लडके बेरोजगार हुए हैं? इन बेरोजगार लड़कें को वापिस लेने के बारे में क्या कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

श्री नर सिंह ढ़ांडा: स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी खुद को–आप्रेटिव मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह डिटेल को–आप्रेटिव डिपार्टमैंट से मिल सकती है लेकिन वे यह जानकारी डिपार्टमैंट को सैपरेट नोटिस देकर मांग सकते हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय को इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है कि स्थानीय डिपो होल्डर स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर चीनी और राशन के माल को हड़प कर जाते है? यदि ऐसी कोई शिकायत मिली है तो क्या दोशियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई हैं?

श्री नर सिंह ढ़ांडा: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कई शिकायतें डिपार्टमैंट में आती रहती हैं और डिपार्टमैंट हर महीने उन पर कार्यवाही भी करता है वाकायदा लिख कर विभाग के आदमी की डियूटी लगाई जाती है और कई बार किसी दूसरे महकमें के किसी आदमी या अफसर को भी भेजा जाता है।

श्री मनी राम: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोयद से यह जानना चाहता हूं कि क्या जिला हैडक्वार्टर पर डी.एफ.एस.ओ. या डी.एफ.एस.सी. 5 या 10 परसैंट डिपोज को चैक करने जाते हैं?

श्री नर सिंह ढ़ांडा: अध्यक्ष महोदय, अगर किसी स्पैसिफिक जगह की शिकायत होती है तो वहां पर इंसपैक्टर या सब–इन्सपैक्टर की डियूटी लगाई जाती है। जहां तक डी.एफ.एस. सी. या डी.एफ.एस.ओ. का ताल्लुक है, वे भी डिपो चैक करने जाते है।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य में कितने कन्जयूमर्ज दर्ज हैं और ये कन्जयूमर्ज दर्ज करने के लिए राशन कार्ड कितने समय में ईशू कर दिया जाता है।

श्री नर सिंह ढ़ांडा: अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का ताल्लुक है कि हरियाणा में कितने कन्जयूमर्ज हैं तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि

हरियाणा की आबादी 1 करोड़ 70 लाख है जिन लोगों को हम चीनी वगैरा दे रहे हैं, वे 1 करोड़ 49 लाख लोग हैं। इसका आधार यह है कि 1981 में सैंसज हुई थी उसके बाद अढ़ाई परसैंट के हिसाब से हर साल बढ़ाकर एफ.सी.आई. से चीनी या अन्य वस्तुएं मिल रही हैं। (विघ्न) चीनी का बंटवारा और कन्जयूमर्ज की संख्या मैंने बता दी है।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में प्रति व्यक्ति 400 ग्राम चीनी मिलती है, जबकि दिल्ली में 1 किलो मिलती हैं। क्या हमारी सरकार भी राशन की चीनी बढ़ाने के बारे में सोच रही है?

श्री नर सिंह ढ़ांडा: यह बात ठीक है कि हरियाणा में 400 ग्राम की बजाये सवा चार सौ ग्राम चीनी देते हैं, जबकि यू.टी. चंडीगढ़ और दिल्ली में 800 ग्राम चीनी दी जाती थी। अब दिल्ली और यू.टी. चंडीगढ़ मैं भी 700 ग्राम चीनी कर दी गई है। हमने मुख्यमंत्री जी के माध्यम के केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने इस मामले में अपनी असमर्थना दिखाते हुए यह कहा है कि क्यों नहीं दिल्ली और चण्डीगढ़ के लिए भी सवा चार सौ ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी कर दी जाए।

चौ. सतवीर सिंह कादयान: क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि गांवों में फेयर प्राइम शौपस खोलने का क्या समय है और महीने में कितने दिन खुलती है?

श्री नर सिंह ढ़ांडा: स्पीकर साहब, फेयर प्राईस शौप्स दो प्रकार की हैं – एक कोआप्रेटिव बेसिज पर चल रही हैं और दूसरे डिपो होल्डर्ज की है। प्राइवेट डिपो होल्डर्ज के पास मुख्यता चीनी बांटने का काम होता है। लेकिन थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरा बांटने का काम भी वे करते हैं। प्राइवेट डिपो होल्डर्ज से जब भी चाहें, चीनी ले सकते हैं। ये दुकान खुली ही रखते हैं। लेकिन गांवों में जो डिपो होल्डर्ज हैं, वे चीनी देते तो महीना भर रहते हैं परन्तु सारा दिन दुकान पर बैठकर उनका गुजारा नहीं हो सकता। दुकान के काम के साथ–साथ उनको खेती बाड़ी का और दूसरा काम भी करना होता है।

Recruitment of the drivers and conductors in Transport Department

***1069. Sh. Udai Bhan**: Will the Minister of State for Transport be pleased to state the number of drivers and conductors recruited in the Transport Department during the year 1989-90 togetherwith the number of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes amongst them?

Home Minister (Prof. Sampat Singh): The information is as under:-

Sr. No.	Category	Total No. of persons recruited	Number of persons belonging to S.C.	Number of persons belonging to B.C.

1	Drivers	936	83	90
2	Conductors	816	156	90

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह रिजर्वेशन का कोटा पूरा न होने का क्या कारण है? क्या कंडक्टर और ड्राईवर क्वालिफिकेशन पूरी न करने की वजह से नहीं लिए गये?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट एस.एस.एस. बोर्ड को रिक्वीजीशन भेजता है। हमने 1986–87 में दो बार रिक्ववीजीशन भेजी और दोनों ही बार पोंस्टे ऐडवरटाईज हुई थी। दो बार ऐडवरटाईजमैंट करने के पश्चात 1527 ड्राईवर और 1521 कंडक्टर्ज के नाम एस.एस.एस. बोर्ड ने सिलैक्ट करके गवर्नमैंट को भेजे है। मैम्बर साहब ने पूछा है कि क्या शल्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड कलासिज के कैंडीडेटस क्वालिफिकेशन पूरी न करने के कारण नहीं लिए गये? ऐसी बात नहीं है। जहां तक कंडक्टर्ज का सवाल है, शडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज का कोटा पूरा हो रहा है लेकिन ड्राईवर के लिए चूंकि 5 साल का हैवी व्हीकल चलाने का ऐक्सपीरिएंस होना चाहिए इसलिए शडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लोग पूरे नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन मैं हाउस की जानकारी के लिए यह बता दूं कि जो शौर्टफाल है, उसके बारे में दोबारा से रिक्वीजीशन भेज दी है। जब वहां से नाम सिलैक्ट होकर आ जाएंगे, तो उस कमी को पूरा कर लेंगे।

डा. बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एस.एस.एस. बोर्ड ने जो कंडक्टर्ज और ड्राईवर्ज की रिक्रूटमैंट की है, उसकी संख्या जिलेवार कितनी–कितनी है?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब औफ हैंड देना सम्भव नहीं है।

श्री राम बिलास शर्मा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो 936 ड्राईवर्ज और 816 कंडक्टर्ज लिए गए हैं, इनका मोड औफ रिक्रूटमैंट क्या है? क्या ये एस.एस.एस. बोर्ड के द्वारा लिए गए है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैट अपने लैवल पर भी भर्ती करता है?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, जब तक एस.एस.एस. बोर्ड से सिलैक्शन होकर नहीं आया था तब तक जी.एम. अपने लैवल पर डायरैक्ट भर्ती करते रहे हैं क्योंकि हम किसी भी हालत में बस को खड़ी नहीं कर सकते। जब एस.एस.एस. बोर्ड से कैडीडेटस स्पोसर्ड होकर आ गये तो उसके बाद एस.एस.एस. बोर्ड वालेां को ही लिया गया, दूसरों को नहीं लिया गया।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ सिलक्शन तो एस.एस.एस. बोर्ड के थ्रू हुआ था और कुछ डायरैक्ट रिक्रूटमेंट जी.एम. ने अपने लैवल पर की थी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब एस.एस.एस. बोर्ड से सिलैक्शन होकर आ गया तो क्या कुछ कंडक्टर्ज और

ड्राईवर्ज हटा दिए गए थे और कुछ अब भी कंटीन्यू कर रहे है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस सिलैक्शन के बाद भी क्या जी. एम. को कई जगहों पर ये हिदायतें थी कि डायरैक्ट कंडक्टर्ज और ड्राईवज लगाएं? यदि हैं तो ऐसे कितने ड्राईवर्ज और कंडक्टर्ज लगे हैं, इसकी पूरी डिटेल बतायें?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं फिर यह बात दोहरा रहा हूं कि एस.एस.एस. बोर्ड से जब कैंडीडेटस स्पौंसर होकर गवर्नमैंट के पास आ गये उसके बाद एक भी ड्राईवर या कंडक्टर हमने किसी और जरिए से भर्ती नहीं किया हैं।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से एक बात जानना चाहती हूं। उन्होंने अपने जवाब में यह बताया है कि जब तक एस.एस.एस. बोर्ड से आदमी सिलैक्ट होकर नहीं आ जाते तब तक हम बस को चूंकि खाली खड़ी नहीं कर सकते इसलिए हमें कुछ रिक्रूटमैंट करनी पड़ती है। मैं यह बात उनसे जानना चाहती हूं कि 936 ड्राईवर्ज में से कितने ऐसे ड्राईवर्ज हैं जो डायरैक्ट लिये और कितने ऐसे हैं जो एस.एस. बोर्ड के माध्यम से लिए गये हैं?

प्रो. सम्पत सिंह: टोटल ड्राईवरर्ज 936 हैं। इनमें से हमने एस.एस.एस. बोर्ड से 816 लिये हैं और अदर दैन एस.एस. एस. बोर्ड 120 लिये हैं। इसी तरह से कंडक्टर्ज टोटल 816 हैं।

इनमें से हमने एस.एस.एस. बोर्ड से 769 लिये हैं और अदर दैन एस.एस.एस. बोर्ड 47 लिये हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय ऐडहाक बेसिज पर कुछ कर्मचारी लगाये जाते हैं। क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि उन डायरैक्ट लगे हुए कर्मचारियों में से कुछ लोग तो निकाल दिये गये लेकिन कुछ लोग जिनकी अभी दो–दो महीने ही सर्विस हुई थी, उनको रख लिया गया है? (विघ्न) क्या इनके यह बात नोटिस में है कि दो महीने की सर्विस वाले कुछ कर्मचारियों को निकाला गया है और बिना किसी बात के निकाला गया है?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैम्बर साहब की तसल्ली के लिए मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो दो महीने की सर्विस वाले कर्मचारी थे उनको हमने बिल्कुल निकाला है। लेकिन जो 240 दिन पूरे कर चुके थे, उनको हमने नहीं निकाला हे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो तो चहेते आदमी थे, उनको तेा रख लिया गया और दूसरौं को निकाल दिया गया।

Mr. Speaker: Capt. Sahib, please listen to me. This is not the way as this is Question Hour.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो एस.एस.एस. बोर्ड के थ्रू लिए

गये 816 ड्राईवर्ज ओर 769 कंडक्टर्ज इन्होंने बताये हैं, इसमें से कितने लोगों ने ज्वायन कर लिया है और इनको पोस्टिंग दे दी गई है?

प्रो. सम्पत सिंह: जो ज्वायन कर गये हैं, मैंने उन्हीं का नम्बर बताया है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने यह कहा है कि दो महीन की सर्विस वाले कुछ लोग हटा दिये गये हैं और कुछ लोग जिन्होंने 240 दिन पूरे कर लिये थे, उनको हटाया नहीं गया है। क्या इनकी नौलेज में यह बात है कि कुछ लोगों को जानबूझ कर 240 दिन पूरे करवाये गये हैं जबकि दूसरों को निकाल दिया गया है? क्या इनके पास इस बारे में कोई शिकायत आयी है कि कुछ को तो दो महीने बाद ही हटा दिया गया लेकिन कुछ लोगों को जानबूझ कर 240 दिन पूरे करवाये गए तब पोस्टें ऐडवरटाइज की गयी हैं?

प्रो. सम्पत सिंह: ऐसी कोई शिकायत नहीं है। न ही किसी माननीय सदस्य ने यह कहा है कि 240 दिन से ज्यादा वाले किसी आदमी को हटा दिया है ओर कम वाले को रखा गया है। ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंह: सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछाा था कि क्या किसी आदमी को जान–बूझकर

240 दिन पूरे कराये गय हैं? उसको इन्होंने क्लैरीफाई नहीं किया है। मैं इस बारे में क्लैरीफिकेशन चाहता हूं।

Mr. Speaker: It is not the way. This is Question Hour. The answer is very clear and no further clarification is required.

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं कि यह जो 120 चालक और 47 परिचालक अन्य तरीकौं से लिए गए हैं, इनमें से कितने–कितने किस–किस डिपो के लिये गए हैं और उनके ऐड्रेसिज कया हैं?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सन, ऐड्रेसिज देना तो सम्भव नहीं हैं लेकिन डिपोज मैं बता देता हूं, ड्राईवर्ज अम्बाला डिपो में 10 करनाल डिपो में 38, जींद डिपों में 15, सिरसा में 9, फतेहाबाद में 10, सोनीपत में 1, दिल्ली में 2, हिसा में 7 और भिवानी में 28 लिए गए हैं। कंडक्टर्ज करनाल मैं 6 फरीदाबाद में 5 और हिसार में 36 लिए गए हैं।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद डिपो में 18 कंडक्टर्ज शडयूल्ड कास्टस के भर्ती हुए थे पहले उनको सात महीने की सर्विस के बाद निकाल दिया गया, फिर दोबारा सेवा में लिया गया। अब 6 महीने के पश्चात फिर हटा दिया गया। क्या उनको कोटा पूरा करने के लिए फिर से सर्विस में लेने की कृपा करेंगे?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पार्टस में सर्विस की होगी। केटिनुअस 240 दिन सर्विस करने का प्रोवीजन है। अब उनको नौकरी में लेना सम्भव नहीं है।

श्री रण सिंह मान: अध्यक्ष महोदय, आज गृह मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी सवालों के जवाब दे रहे हैं। क्या गृह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चण्डीगढ़ में नहीं हैं या कोई लीगल अड़चन की वजह से वे जवाब नहीं दे रहे हैं?

Mr. Speaker: That is not relevant.

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी श्री उदय भान जी ने हरियाणा रोडवेज के हालात के बारे में बताया हैं और मैं भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा रोडवेज में काफी इररैगुलैरिटीज हैं। कुछ लोगों को लगा यिला गया और कुछ लोगौं को हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा केरंगे कि एस.एस.एस. बोर्ड के द्वारा सिलैक्शन होने के बाद भी रोहतक, महेन्द्रगढ़ और भिवानी में बहुत से ड्राइवर्ज व कंडक्टर्ज लगाए गए हैं? क्या यह बात सही है?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना हूं कि इररैगुलैरिटी की बात सरासर निराधार है। इस डिपार्टमैंट में कोई धांधली नहीं हुई है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। जो मैंने स्टेटमैंट दी है वह बिल्कुल ठीक है।

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि पौलिसी का वायलेशन नहीं हुआ है। यह सरासर गल्त है।

Mr. Speaker: Please put the question. Do not give the conclusion.

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की पौलिसी के मुताबिक ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज के बिना ड्राईवर्ज और कंडक्टर्ज नहीं लिए जाते। पहली बार हरियाणा बनने के बाद इस पौलिसी का वायलेशन हुआ है और ड्राईवर्ज और कंडक्टर्ज बिना ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज के लिए गए हैं।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, कोई पोलिसी नहीं तोड़ी गई है बाकायदा जो लोग हैं, वे ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज से लिए है।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं वायलेशन की बात तो नहीं कहता लेकिन जो रिक्रूटमैंट की पौलिसी है उस बारे मैं जरूर कहूंगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्री

महोदय ने बताया कि फरीदाबाद में पांच कंडक्टर्ज लिए गए हैं। क्या वे बतायंगे कि फरीदाबाद में इतने कम आदमी लेने के क्या कारण हैं? क्या वहां पर जरूरत नहीं थी या कोई पोस्ट नहीं थी या किसी असरमंद मंत्री ने वहां के कोटे के अगेन्सट दूसरी जगह से आदमी रख लिए? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने दो महीने सर्विस की और और कुछ ने दो महीने से कम सर्विस की। उन्होंने महकमें में सर्विस तो की है और एस.एस.एस. बोर्ड के थ्रू महकमें में सर्विस के आधार पर वे सर्विस के लिए क्वालिफाईड थे। क्या मंत्री महोदय, उन लोगों के केसिज पर दुबारा विचार करेंगे जिन्होंने विभाग में दो महीने पूरे किए हैं? कहने का मतलब यह है कि उनको दुबारा नैतिक व बेरोजगारी दूर करने के आधार पर सर्विस मैं रखने पर विचार करेंगे या किसी अन्य महकमें में ऐडजस्ट करने पर विचार करेंगे।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, दो महीने की सर्विस वालों को नहीं लिया जा सकता।

Daryapur Incident

***1058. Comroade Harpal Singh**: Will the Minister for Home be please to state –

(a) whether any of the accused involved in the murder of bus passengers in Daryapur incident in the month of July 1987 has been arrested; if so, the number thereof togetherwith the persons arrested, in retaliation thereto;

(b) the number of persons, out of those referred to in part (a) above have been convicted; and

(c) the names of persons killed in the said incident togetherwith the details of financial help, if any, given in each case?

Home Minister (Prof. Sampat Singh):

(a) Yes sir.

(i) 7 accused involved in the murder of bus passengers were arrested.

(ii) 186 persons were arrested in retaliation of Daryapur bus massacre incident.

(b) (i) Case is under trial.

(ii) Two cases of retaliation ended in conviction in which 11 persons were convicted.

(c) Information is given in Annexure 'A' & 'B'.

ANNEXURE 'A'

Sr. No.	Name of the persons killed	Financial help given
1	Sh. Tejbhan S/o Sh. Deva Ram R/o Vill. Ratera Distt. Bhiwani.	Rs. 20000
2	Sh. Sham Lal S/o Sh. Wasawa Ram R/o	Rs. 20000

	Udepurain Distt. Hisar	
3	Sh. Inder S/o Khem Chand R/o H.No. 1024, Malia Colony, Fatehabad.	Rs. 20000
4	Sh. Subhash S/o Sh. Daya Ram R/o Partap Bazar Agent Panch Photo Naswar Hansi Distt. Hisar.	Rs. 20000
5	Sh. Amar Chanh S/o Sh. Man Singh Aggarwal, R/o Nihal Singhwala, Punjab.	Rs. 20000
6	Sh. Jassa Ram S/o Sh. Hukmi Ram R/o Hatol Jatan Teh. Hansi, Const. No. 481/Sisra.	Rs. 20000
7	Sh. Krishan Lal, Peon, Govt. High School, Daryapur Teh. Fatehabad.	Rs. 20000
8	Sh. Mohan Lal S/o Sh. Ram Ditta R/o Village Daryapur. Teh. Fatehabad.	Rs. 20000
9	Raghbir Singh S/o Kansi Ram r/o Gilla Khera, Teh. Fatehabad.	Rs. 20000
10	Sh. Shobha Ram S/o Sh.	Rs. 20000

	Ram Lal R/o Bighar Teh. Fatehabad.	
11	Sh. Mangat Ram S/o Sh. Hansa Ram Arora, Medical Hall, Jawahar Chowk, Fatehabad.	Rs. 20000
12	Sh. Amar Chand S/o Sh. Ram Kishan Sham Mandi, Fatehabad.	Rs. 20000
13	Sh. Baldev Raj S/o Sh. Ram Lal, G.B. Oil Mill, Fatehabad.	Rs. 20000
14	Sh. Gurmeet Kumar S/o Sh. Ram Chander near Girl High School, Fatehbad.	Rs. 20000
15	Sh. Nihal Singh S/o Sh. Chhotu Lal Vill. Nandhari, Distt. Hisar.	Rs. 20000
16	Sh. Roshan Lal S/o Sh. Telu Ram R/o Kasun, Distt. Jind.	Rs. 20000
17	Sh. Virender Kumar S/o Sh. Piare Lal, Green Park, Hisar.	Rs. 20000

18	Sh. Jagdish S/o Sh. Sheo Karan Vill. Gollagarh, Distt. Bhiwani.	Rs. 20000
19	Wazir Chand S/o Sh. Jagdish Vill. Urkiwala, Teh. Fatehabad.	Rs. 20000
20	Sh. Ram Dutt S/o Sh. Mukh Ram Vill. Hazrawan Kalan, Teh. Fatehabad.	Rs. 20000
21	Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Sita Ram Vill. Fajalpur Distt. Sonipat.	Rs. 20000
22	Sh. Satish Kumar S/o Sh. Ramji Lal Slaria, Mohalla Rohtak.	Rs. 20000
23	Sh. Om Parkash S/o Sh. Piare Lal Vill. gilla Khera Teh. Fatehabad.	Rs. 20000
24	Sh. Manphool Singh S/o Ganesh Ram, Dhani Majra Teh. Fatehabad.	Rs. 20000
25	Harbans Lal Grover S/o Gulab Rai, Kath Mandi Fatehabad.	Rs. 20000
26	Partap Singh Khati r/o	Rs. 20000

	Daulatpur an employee Co-operative Market Committee Uklana.	
27	Amar Singh S/o Sh. Makhan Singh. Bighar Teh. Fatehbad.	Rs. 20000
28	Sh. Dinesh Kumar S/o Amr Nath Aggarwal House No. 19, Chanderpuri, Saharanpur (U.P.)	Rs. 20000
29	Sh. Mangal Ram S/o Sh. Ganesh Ram Ward No. 1, Vill. Rawatsar Distt. Gangangar (Rajasthan).	Rs. 20000
30	Sh. Vijay Kumar S/o Sh. Hhar Narain H.No. 27 Police Colony Hanumangarh Distt. Ganganagar.	Rs. 20000
31	Sh. Sukhdev Singh S/o Sh. Mani Ram Sharma Vill. Naiwali Teh. Sirsa.	Rs. 20000
32	Nathi Ram S/o Sh. Modi Mal H.No. 212/B, New Mandi Muzaffar Nagar (UP).	Rs. 20000

33	Sh. Madan Sharma S/o Sh. Kanhiya Lal Rajpura Distt. Patiala.	Rs. 20000
34	Unidentified.	Rs. 20000

ANNEXURE 'B'

Sr. No.	Name of the persons killed in retaliation	Financial help given
1	Harbans Singh S/o Sh. Balwant Singh Brahman Sikh r/o Vill. Saidpur, PS Sadar Yamunanagar.	Rs. 20000
2	Malook Singh S/o Sh. Kanthara Singh Jat Sikh r/o Mahabir Colony, Hissar.	Rs. 20000
3	Daya Nand r/o Hisar (Hindu).	Rs. 20000
4	Balkar Singh S/o Kaka Singh, Jat sikh, Saidulgarh Distt. Bhatinda (Punjab).	Rs. 20000
5	Satinder Singh R/o near Hazur Masid, Hisar (Sikh).	Rs. 20000

(Sr. No. 2 to 5 were killed in Hisar district).

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, दरियापुर कांड के बाद जो कम्युनल वायलैंस हुई, उसमें लूटपाट की घटनाएं भी हुई थीं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितने अमाउन्ट की लूटपाट हुई थी और पुलिस ने उसमें से कितने का माल बरामद करके लोगों को वापिस कर दिया?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, टोटल जो प्रौपर्टी लूटी गई थी वह 42 लाख 34 हजार और 30 रूपये की थी। यह प्रौपर्टी हिसार और सिरसा में लूटी गई थी और इसमें से 26 लाख 65 हजार और 100 रूपये की प्रौपर्टी ओनर्ज को वापिस कर दी है।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने विकटम्ज के नाम बताए हैं। इस हाउस में बार–बार चर्चा होती रही है कि उस वायलैंस में हरियाणा के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। क्या यह बात सही है? क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस वायलैंस में और कितने लोग शामिल थे तथा उनके नाम क्या हैं?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, सकबा नाम बताना तो मुश्किल हैं लेकिन नम्बर बता सकता हूं कि इतने लोग उस वायलैंस में शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने बताया था कि लूटपाट का अकेला केस दर्ज किया गया था और हम कोर्ट में केस लेकर गए थे। भिवानी की स्पैशल कोर्ट ने गवर्नमेंट को

डायरैक्शन दी थी कि उनको ऐन्टी टैरोरिस्टस ऐक्ट के ततहत चालान किया जाए। उन लोगों मैं एक वर्तमान एम.पी. शामिल हैं और वे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके भाई और भतीजे के खिलाफ भी ऐन्टी टैरोरिस्टस ऐक्ट के अन्डर केस दर्ज किया गया और बाकायदा उन्हें गिरफतार किया गया।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार के पास उग्रवादियों ने निपटने के लिये आधुनिक हथियार उपलब्धहैं? अगर नहीं, तो क्या सरकार ने केन्द्र सरकार से इसके लिये मांग की है और केन्द्र सरकार का इस बारे में क्या रवैया है?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि उग्रवादियों से निपटने के लिये आधुनिक हथियारों की आवश्यकता है लेकिन जहां तक उग्रवादियों से आधुनिक हथियारों से निपटने का प्रश्न है, इसके लिये दिल और मन को मजबूत होना चाहिये। हमारे हरि हरियाणावासी का दिल और मन मजबूत है। बाकायदा लोगों का सहयोग सरकार के साथ है। पुलिस का मनोबल काफी ऊंचा है। वह पूरी तरह से सतर्क है। हथियारों के लिये हम बार–बार केन्द्र सरकार से मांग करते आ रहे हैं। कुछ हथियार आए भी हैं। बाकी का मामला अन्डर प्रोसैस है और कुछ असला आने वाला भी है लेकिन मैं इस सदन में यह बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई चिन्ता वाली बात नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अन्दर बाकायदा हर आदमी की जान और माल की रक्षा करने के

लिये सरकार के पास पूरा प्रबन्ध है और सरकार इस बारे में पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने अपने जवाब के part (b) (ii) में कहा है –

इस कंविक्शन की परिभाशा क्या है और जो केस अन्डर ट्रायल आपने बताया है, उसकी क्या स्टेज है?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, कुछ केसिज में कंविक्शन तो हो चुकी है। बाकी जो केस कोर्ट के अन्दर चल रहे हैं उनका फैसला होने के बाद ही उन के बारे में कुछ कहा जा सकता है।

डा. मंगल सेन: अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि भिवानी की कोर्ट ने यह आदेश दिये हैं कि फलां–फलां लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। मैं आपके द्वारा इनसे यह जानना चाहता हूं कि उन महानुभावों के शुभ नाम क्या–क्या हैं और उनके खिलाफ मामला किस स्टेज पर है? क्या वे लोग बेल पर बाहर आ गये हैं या अभी अन्दर ही हैं?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक का नाम मनफूल सिंह है जो कि भजनलाल का सगा भाई है और उसके लड़के व और भी परिवार के सदस्य हैं। सबके नाम तो मैं इस समय नहीं बता सकता लेकिन मुख्य दोशियौं के बारे में मैंने बता दिया है।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन 186 आदमियों के खिलाफ केसिज चल रहे हैं, वे केसिज जलाने, मारने, लूटने या किस–किस नेचर के हैं और जो 96 लाख में से 26 लाख रूपये का माल इन लोगौं से बरामद हुआ है क्या उस माल का मूल्य सरकार ने डलवा लिया था?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो माल रिटर्न हुआ है उसकी कीमत तो डाली ही गई है।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि हरियाणा के अन्दर लोगों का व पुलिस का मनोबल बड़ा ऊंचा है। हर हरियाणावासी का दिल और मन मजबूत है। किसी प्रकार का कोई भी नहीं है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वे बिना बौडी गार्ड के चल सकते हैं? जो बौर्डर ऐरियाज हैं, क्या ये वहां बिना बौडी गार्ड के व असले के आ जा सकते हैं?

10.00 बजे

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं भाई हरपाल सिंह जी को यह बता देना चाहता हूं कि मैं बाकायदा बिना बौडी गार्ड के, चाहे बस हो या पैदल, हर जगह आ जा सकता हूं। स्पीकर साहब, मैं इनकी और तसल्ली करवा दूं। क्योंकि भाई हरपाल सिंह का एरिया बौर्डर का एरिया है इसलिए ये भाई जरूर चिन्ति रहते

होंगे। हम भी इस बात से कंसर्ड हैं कि हर मैम्बर और हर सिटिजन की सिक्योरिटी हो। बौर्डर एरियाज में मैं मीटिंग्ज वगैरह के लिए एज होम मिनिस्टर तो जाता ही रहता हूं लेकिन सम्पत सिंह वहां पर बस में भी जा सकता है और पैदल भी जा सकता है।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, कल भी और आज भी कहा गया कि दरियापुर कांड में कांग्रेस का हाथ था और श्री भजन लाल का भी नाम लिया गया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या इस कांड में किसी जनता दल या बी.जे.पी. के मैम्बर के खिलाफ भी कोई केस दर्ज है?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने स्पैसिफिक जनता दल और बी.जे.पी. का नाम लेकर पूछा है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जनता दल और बी.जे.पी. का कोई भी सदस्य किसी केस में इनवालवड नहीं है। जो आग इन लोगों ने लगाई थी, ये तो उसको बुझाने में लगे हुए थे। (शोर)

श्री रघुबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि दरियापुर हादसे के बाद ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या स्टैपस लिए गए हैं और उस कांड के बाद कोई और टैरोरिस्ट कांड भी हुआ?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, उसके बाद 10 कांड और हुए। क्योंकि पंजाब का एरिया हरियाणा के साथ लगता है

और काफी जिले हमारे ऐसे है जो पंजाब के बौर्डर के साथ लगते हैं इसलिए पंजाब का फाल आउट हरियाणा के ऊपर हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन उसके लिए कार्यवाही हुई है। सबसे पहले तो हमने पुलिस की स्ट्रैन्थ को बढ़ाया। पिछले दो अढ़ाई सालों के अन्दर हमने आठ हजार की पुलिस में बढ़ौतनी की है और पिछले एक साल मैं साढ़े चार सौ गाड़ियां खरीदी गई ताकि पैट्रोलिंग और नाकाबन्दी की जा सके तथा इनफर्मेशन कलैक्ट की जा सके। इसके अलावा वायरलैस सैटस तथा अन्य इन्स्टूमैंटस लिए गए हैं ताकि बौर्डर एरिया के लोग सुरक्षा महसूस करें। इसके अलावा टैरोरिस्टम की इंटैलिजैंस वगैरह भी कलैक्ट करते रहते हैं। हरियाणा में सौभाग्य की यह बात है कि जनता का हमेशा हमारे साथ कोआप्रेशन रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम उग्रवादियों को रोक रहे हैं।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, दरियापुर कांड के बाद हरियाणा सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिग कमेटी बनाई थी। क्या सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट हाउस के अन्दर रखेगी? दूसरे, पिछले दिनों टोहाना के अन्दर जैसे अभी गृह मंत्री ने बताया कि बौर्डर एरियाज के अन्दर ऐक्टीविटीज होती रहती हैं –

Mr. Speaker: Do not elaborate. Please put a question. You will get another opportunity to put a second question, if you like.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा मतलब है .....

...

Mr. Speaker: Do not confuse the question. Since your supplementary is irrelevant, I do not allow it. (Interruptions)

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरी अर्ज है कि ...

.....

Mr. Speaker: You can put one question and I will give you another opportunity to put second question. Why are your then mixing up questions? Please take your seat.

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, पहले जब ऐसे कांड हरियाणा में हुए तो हरियाणा सरकार ने सैंटर के होम मिनिस्टर को कई बार लैटर लिखे कि हमें मदद दी जाए और बढ़िया वैपन दिए जाएं। उन दिनों में हमारे होम मिनिस्टर की स्टेटमैंट आया करती थी कि हमें एडिक्वेट वैपन नहीं मिलते। मैं जानना चाहता हं कि क्या सैंटर में नई गवर्नमैंट बनने के बाद आपको कोई वैपन मिले हैं या नहीं?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अभी तक कोई ऐसा वैपन नहीं आया है। जहां तक खतो–किताबत की बात है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला स्वयं केन्द्रीय गृह मंत्री से मिले हैं और उन्होंने यह विचार जाहिर किया है कि वैपन हमें जल्दी ही मिल जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, गृह मंत्री जी ने बताया कि पहले हत्या कांड के बाद हरियाणा सरकार ने 450 गाड़ियां खरीदी और कई वैपन्ज लिए। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस को इतनी सुविधाएं मिलने के बाद क्या उसने किसी आतंकवादी को, यानी जिस पर आतंकवादी होने का संदेह हो या जो सन्देह की स्थिति में पाया गया हो, पकड़ा है? अगर पकड़ा है तो कितने उग्रवादी पकड़े हैं?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मुझे टोटल नम्बर तो याद नहीं लेकिन लगभग 150 के करीब उग्रवादी पकड़े गए हैं।

Disney Land

***1100. Sh. Sita Ram Singla@Sh. Yogesh Chand Sharma, Capt. Ajay Singh Yadav, Comrade Harpal Singh, Sh. Surinder Kumar Madan, Ch. Mahender Partap Singh, Sh. Ram Bilas Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up an amusement park/Disney land at Sohna in District Gurgaon; if so, the details thereof; and

(b) whether the proposal as referred to in part (a) above has been initiated by this Govt. or the previous Govt.?

मुख्यमंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला):

(क) हां, सोहना जिला गुड़गांव मैं एक मनोरंजन पार्क बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दिनांक 9 जनवरी, 1990 की अधिसूचना जारी की गई है।

(ख) मनोरंजन पार्क की स्थापना का विचार वर्तमान सरकार का नहीं है। यह प्रस्ताव पिछली सरकार द्वारास दिया गया था।

Mr. Speaker: I would request the Hon. Members, who have given notice of this question, that they should put a supplementary one by one.

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेन सवाल के भाग ''क'' के जवाब में बताया है कि ''जिला गुड़गांव में एक मनोरंजन पार्क बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दिनांक 9 जनवरी, 1990 को अधिसूचना जारी की गई है।'' मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वहां पर जो 28342 एकड़ भूमि ऐक्वायर की जा रही है उसमें कितने गांवों की जमीन, आबादी देह को छोड़ कर, ऐक्वायर की जा रही है? इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने भाग ''ख'' के जवाब में बताया है कि ''मनोरंजन पार्क की स्थापना का विचार वर्तमान सरकार का नहीं हैं यह प्रस्ताव पिछली सरकार द्वारा दिया गया था।'' इसके बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या पिछली सरकार की 28342

एकड़ भूमि ऐक्वायर करने की योजना थी या उस योजना को बदल कर इस सरकार ने इतनी बड़ी योजना बनाई है?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए सर्वप्रथम मैं इस प्रश्न को साफ करना चाहूंगा। यह प्रश्न डिजनीलैंड के नाम से किया गया है जबकि डिजनीलैंड नाम की कोई चीज वहां पर नहीं बनने जा रही है। वह एक प्रकार से मनोरंजन पार्क बनाया जाएगा। डिजनीलैंड डिजनी नाम के किसी व्यक्ति ने अमेरिका में बनाया था इसलिए उसका नाम डिजनीलैंड है। हरियाणा सरकार ने उस मनोरंजन पार्क के लिए 28342 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की है। उसमें कुल 26 गांव और 4 बेचिराग गांव आते हैं। यह प्रोपोजल 1983–84 से चल रही थी लेकिन 1986 में भूमि ऐक्वायर करने के नोटिस देकर इस पर अमल शुरू किया गया है। मौजूदा सरकार ने इस मनोरंजन पार्क को बनाना इसलिए जरूरी समझा है ताकि सरकार को इसस आमदन हो सके और सरकार की आमदन बढ़ाई जा सके।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दूसरे पार्ट का जवाब नहीं आया। मैंने प्रश्न के दूसरे पार्ट में यह पूछा है कि पिछली सरकार की 28342 एकड़ भूमि ऐकवायर करने की योजना थी या इस सरकार ने उस योजना को बदल कर इतनी बड़ी योजना बनाई है?

Mr. Speaker: Mr. Singla, please listen to the Chief Minister first. You will then get an opportunity.

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दूसरे पार्ट का जवाब तो आना चाहिए।

Mr. Speaker: I will give you another opportunity.

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न पर यदि काफी खुलकर विचार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।

डा. मंगल सैन: हमने इस सवाल के बारे में आधे घंटे की डिस्कशन की मांग कर रखी है।

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। उसका तो स्पीकर साहब को पता होगा। वही आपको बताएंगे। जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक हैं, मैं यह चाहूंगा कि सभी सम्मानित सदस्य आराम से अपने–अपने स्थानों पर बैठ कर इस बारे में एक–एक क्वैश्चन पूछ सकते हैं और आपको बड़े विस्तार से उसकी जानकारी दी जाएगी। इस बारे में बड़ा कंफयूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। मैं चाहूंगा कि यदि इस बारे में सरकार की स्थिति स्पश्ट हो जाए, तो बहुत अच्छा है।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने खुद कहा है कि इस सवाल पर खुल कर डिस्कशन हो जाये। मैंने और 4 अन्य सदस्यों ने इस पर आधे घण्टे की डिस्कशन का

नोटिस दिया हुआ है because it is very important question, Sir. (Interruptions)

Mr. Speaker: Sharma Sahib, let the supplementaries be put and answers given. You can raise this point thereafter if you are not satisfied.

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, सदन के नेता ने कबूल किया है कि इस पर खुल कर डिस्कशन हो जाये। मैंने और दूसरे साथियों ने इस सवाल पर आधे घंटे की डिस्कशन का नोटिस दिया हुआ है। (शोर)

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): पहले यह सवाल पूरा हो लेने दें। यदि सवालों से आप लोगों की तसल्ली नहीं होती तो आधे घंटे की डिस्कशन की बात तो उसके बाद ही आएगी। (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, सदन के नेता ने चाहा है कि इस पर खुलकर डिस्कशन हो जाये। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष: अगर आप लोगों ने क्वैश्चन आवर में ही सारे क्वैश्चन पूछ लिए तो फिर आधे घंटे की डिस्कशन की क्या जरूरत रह जायेगी?

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि यह 28342 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की योजना पिछली सरकार की थी या इस सरकार की है?

Mr. Speaker: Singla ji, you will get another opportunity. Please take your seat now.

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, इस सवाल में सभी मैम्बर्ज इन्ट्रैस्टिड हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह ऐम्यूजमैंट पार्क 28342 एकड़ जमीन में बनाने का प्रस्ताव पिछली सरकार का था या इस सरकार का है? अगर यह प्रस्ताव पिछली सरकार का था तो पिछली सरकार ने कितनी जमीन में बनाने का प्रस्ताव किया था और उसके ऊश्पर उस समय कितने खर्चे का अनुमान लगाया गया था। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब सभी सदस्य इस डिजनीलैंड का विरोध कर रहे हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसे ड्रौप करने के बारे में सोचा जायेगा? यदि ऐसा विचार नहीं है तो क्या हर जिले में ऐसा पार्क और खासकर सिरसा जिले में ऐसा कोई पार्क बनाया जायेगा?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस पार्क को बनाने की पिछली सरकार की तरफ से प्रोपोजल चली रही थी और भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय मौजूदा सरकार ने लिया है।

कैप्टल अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह ऐम्यूजमेंट पार्क किसी विदेशी सहायता के जरिए बनाया जायेगा या हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमैंट इसको बनाने में सक्ष्म है?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: टूरिजम डिपार्टमैंट ही इसको बनायेगा। यह किसी विदेशी सरकार के सहयोग से नहीं बनाया जा रहा।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी इस ऐज्यूजमैंट पार्क जो गुड़गांव–सोहना एरिया में बनाया जा रहा है, के बारे में विस्तार से ब्यौरा दें कि इसके लिए कितने एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, इसको कैसे–कैसे पूरा किया जायेगा ओर इससे कितनी इंकम होगी। और इस चारागाह में कौन–कौन जाएंगे?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: यह कोई चारागाह नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा है कि यह कितने करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट है, कैसे–कैसे यह बन कर तैयार होगा। इससे इंकम क्या होगी, and what would be the expenditure on this?

Mr. Speaker: How can it be replied at this stage as to what would be the expenditure and income.

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस के सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस पार्क के विस्तार के बारे में पूरा विवरण सभी साथियों को दिया जायेगा। मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि यह कोई चारागाह नहीं है इसलिए चरने वालों की संख्या के बारे में नहीं बताया जा

सकता। यह ऐम्यूजमैंट पार्क सरकार की तरफ से 28342 एकड़ भूमि में बनाया जायेगा और इस जमीन को ऐक्वायर करने के लिए दफा–4 के नोटिस दे दिए गए हैं। इस भूमि में से कृशि योग्य भूमि 14381 एकड़ है। (शेम शेम की आवाजें) इसमें शेम शेम वाली कोई बात नहीं है। अप लो मेरी बात को ध्यान से सुनें। शेम शेम वाली बात का तो बाद में पता चलेगा। आप आराम से मेरी बात को सुनें। आपको सारी बात का जवाब मिल जाएगा। शेम लफज का फैसला तो अदालतों में हुआ करता है। कृशि योग्य भूमि 14381 एकड़, पहाड़ी जमीन 9320 एकड़, सरकार भूमि 554 एकड़ और झील का रकबा 574 एकड़ है। यह कुल भूमि है जिसके लिए सरकार ने अभी दफा–4 का नोटिस दिया है। जहां तक इससे होने वाली आमदनी का सम्बन्ध है, आमदनी की बात अभी से नहीं कही जा सकती। जहां तक खर्च का ताल्लुक है, टूरिज्म डिपार्टमैंट की प्रोपीजलहै और टूरिज्म डिपार्टमैंट की अपनी एक अथौरिटी बनाने की है। इस अथौरिटी के तहत टूरिज्म डिपार्टमैंट इस बात के लिए सक्षम होगा कि उसे जितनी धनराशि इसके लिए चाहिए, उतनी ही धनराशि उसके अपने सोर्सिज से मिल जाए।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के अन्दर वाल्अर डिजनी ने जो डिजनीलैंड बनाया था, वह केवल 200 एकड़ में बना था। हरियाणा में डिजनीलैंड बनाने की प्रोपोजल 1983–84 में तैयार की गई थी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रोपोजल 200 एकड़ भूमि पर

डिजनीलैंड बनाने की थी या इससे ज्यादा जमीन पर बनाने की थी? हमारी सरकार किसान का हित रखने वाली सरकार है। क्या सरकार इस प्रकार का विचार रखीती है कि किसानों का जो ऐग्रीकल्चर लैण्ड 14381 एकड़ है, वह छोड़ दी जाए और जो बाकी जमीन बचे, उससे ही काम चलाया जाए?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम सै सदन के सम्मानित सदस्यों को विस्तार से बताना चाहूंगा। अमेरिका का जिक्र कल श्री किरपा राम पुनिया जी ने भी किया था और वे बार–बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि वहां केवल 200 एकड़ जमनी पर यह है। अमेरिका के ओरलैण्डों शहर में वाल्टर डिजनी ने 27000 एकड़ में डिजनी वर्ल्ड स्थापित कियाहै। हरियाणा सरकार की तो केवल मन्शा यही है कि ऐसा डिजनीलैण्ड यहां भी बनाया जाए। यह सरकार किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। इसलिए हम अपनी तरफ से कृशि योग्य भूमि कम से कम लेने की कोशि करेंगे। विकास कार्यो में एकाध एकड़ भूमि इस प्रकार की अगर आ ही जाएगी तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता। उस जमीन के लिए सरकार पूरा कम्पनसेशन दैगी। (विघ्न) मैं यही बता रहा हूं कि किसानों की जो जमीन ली जाएगी सरकार उसके लिए उन्हें पूरा कमपनसेट करेगी और इसको कम से कम भूमि पर बनाने की कोशिश करेगी। इसके लिए ज्यादा भूमि अधिग्रहण का नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत वर्श और अमेरीका में बहुत

बड़ा अन्तर है। यहां पर किसी चीज को बनाने के लिए यदि भूमि अधिग्रहण की जाती हे तो उसके साथ लगती जमीन को लोग सस्ते दाम पर इसलिए खरीद लेते है ताकि बाद में इसको महगे दामों पर बेचा जा सके। इसलिए सरकार ने इतनी जमीन की ऐक्विजिशन का नोटिस दिया है। सरकार के सामने 3000 से अधिक लोगों के ऐतराजात आए हैं। सरकार बाकायदगी से और बारीकी से उनके एक–एक ऐतराज को सुनेगी। जैसे चर्चा भी हुई है और उस हल्के सम्मानित सदस्य ने इस बात की मांग भी की है कि गांवों को उजाड़ा न जाए उसके बारे में मैं हाउस में बताना चाहूंगा कि किसी भी गांव को उजाडने की योजना नहीं है, बल्कि इस मनोरंजन पार्क के बीच में यदि कोई गांव आएगा तो उसकी ज्यादा इम्पोर्टैंस बनेगी। जिस प्रकार दिल्ली में एक गांव नारायणा है। उसके एक–एक मकान की बहुत ज्यादा कीमत पड़ रही है। इसी प्रकार से वहां के जो किसान हैं, उनको भी पूरी तरह से फायदा मिलेगा। ये लोग जिन किसानों के हितैशी बनने की बात कर रहे हैं, उन किसानों की बहुत सी जमीनें तो पहले ही बहुत से प्रौपर्टी डीलर्ज ने खरीदी हुई हैं। ये बड़े–बड़े प्रौपर्टी डीलर्ज बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के हैं जिन्होंने किसानों से उनकी जमीन सस्ती खरीदी हुई है ओर हरियाणा सरकार की स्टाम्प डियूटी भी उन्होंने बचाई है क्योंकि रजिस्ट्रियां कम कीमत की करवाई हैं। उन्हीं प्रौपर्टी डीलर्ज को इस बात की पीड़ा है। यदि अब उस जमीन को सरकार ऐक्वायर करेगी तो उन्हें बहुत थोड़ी कीमत मिलेगी। कहां तो वे फार्म हाऊस बनाकर अरबों पति बनने

के ख्वाब ले रहे थे और कहां उनकी जमीन को बहुत कम कीमत में लेने की बात चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं हाऊस को इस बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसानों के हकूक की पूरी तरह से हिफाजत करेगी और हम कृशि भूमि कम से कम लेंगे और वह भी अगर मजबूरी हुई, तभी लेंगे। इस क्षेत्र के सैंकड़ों किसान इस सिलसिले में मुझसे मिले हैं। 25–30 सरपंचिज भी उन गांवों के मुझे मिले हैं। उन्हें मैंने बाकायदा आश्वासन दिया है और वे आश्वासन मान कर चले हैं। उनकी तसल्ली है, वरना इस बात को लेकर अखबारों में शोर मचता था, बड़े आंदोलन हो गये थे। इसके बारे में तों वही बात हुई जैसे कहते हैं कि–

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,

जब चीरा तो कतरा एक खून निकला।

इस बारे मैं अब किसी प्रकार का कोई आन्दोलन नहीं है। किसी किसान को इस बात की कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को तकलीफ जरूर है जो बहुत पैसा कमाने के ख्वाब ले रहे हैं, क्योंकि सरकार जब उनसे सस्ते दामों पर इस जमीन को ले लेगी तो उन्हें इसका नुक्सान होगा। (विघ्न)

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में अच्छी तरह से सरकार की पालिसी समझाने की कोशिश की है। अब उस पालिसी में कितनी सच्चाई

है, यह तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। जो प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर दिया है कि पिछली सरकार के द्वारा इसकी प्रपोजल बनी थी, उसका यह जवाब क्लीयर नहीं कर पाये हैं कि उसके अन्तर्गत कितनी जमीन लेनी थी, क्योंकि मैंने वहां के लोगों से मालूम किया है कि क्या पिछले पांच सालों में कोई नोटिफिकेशन हुई है? उन्होंने बताया है कि कोई नोटिफिकेशन वगैरा नहीं हुई। मुख्यमंत्री महोदय यह क्लीयर कर दें कि कितनी जमीन की नोटिफिकेशन हुई थी। दूसरी बात मुख्यमंत्री ने कहीं कि किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी का इस आश्वासन के लिए धन्यवाद करता हूं लेकिन इसके साथ–साथ में एक बात इनसे जानना चाहता हूं। इन्होंने बताया कि काश्त योग्य भूमि लगभग 14 हजार एकड़ और पहाड़ी जमीन 9 हजार एकड़ ली जाएगी। क्या इस बारे में कुछ ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ के उन लोगों को, जो सरकार के चहेते हैं फायदा पहुंचाने के लिए पहाड़ को खरीद रखा हो या उनके लिए यह प्रपोजल बनाई हो ताकि उनको ऊंचे दाम मिल सकें?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य के प्रश्न का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। पिछली सरकार की तरफ से इस प्रकार की प्रपोजल बनी थी और उसके लिए पिछली सरकार ने विज्ञापन दिया था। जहां तक भूमि अधिग्रहण

का सम्बन्ध है, इस बारे में मैंने पहले ही बताया है कि वह मौजूदा सरकार ने किया है।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, यह पहाड़ का एरिया उन लोगों के पास है जो सरकार का नाम लेते है, कहीं उस जमीन को खरीद कर और उन्हें अच्छे भाव देकर सरकार उन्हें फायदा तो पहुंचाना नहीं चाहती है?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा विस्तृत जवाब दिया है और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कहा है कि इस प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए ताकि हरियाणा के लोगौं को पता लगे कि सही पोजीशन क्या है। मेरा ख्याल है कि इस प्रश्न पर आप हाफ एन आवर डिस्कशन अलाऊ कर दें।

मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री (श्री मनफूल सिंह): स्पीकर साहब, इनके सवाल का जवाब तो आ गया है, अब और सवाल पूछने की क्या आवश्यकता है? (विघ्न)

Sh. Ram Bilas Sharma: Mr. Speaker, Sir, is it the way? He is an Hon'ble Minister. (Interruptions) चौ. मनफूल सिंह जी, आप मंत्री हैं। कम से कम आपको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। (विघ्न)

Mr. Speaker: Mr. Manphool Singh Ji, this is not the way. I will not allow you to speak like this. You always unnecessary try to interfere. Please take your seat. (विघ्न)

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, मैं तो यही कह रहा हूं कि इनके सवाल का जवाब आ गया है।

श्री राम बिलास शर्मा: मनफूल सिंह जी, यह हरियाणा की सर्वोच्च पंचायत है। आप क्या बात कर रहे हैं? बिना इजाजत के कैसे बोल रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देना चाह रहे हैं आप बीच में बोल रहे हैं।

Mr. Speaker: Mr. Manphool Singh, please take you seat.

Sh. Ram Bilas Sharma: Speaker, Sir, he is a Minister. He should not be allowed to interfere liek this.

Mr. Speaker: Mr. Manphool Singh, please take your seat. You always interfere unnecessarily. जब आपका सवाल आयेगा तो अ अंग्रेजी भंगड़ा करने लगेंगे।

श्री राम बिलास शर्मा: कया मुख्यमंत्री महोदय एक बात बताने की कृपा करेंगे? उन्होंने खुद फरमाया है कि उनसे सैकड़ों किसान और कई पंचायतों के सरपंच मिले हैं। उन की मांग को देखते हुए और हरियाणा सरकार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए क्या मुख्यमंत्री जी यह समझते हैं कि वहां एक एम्यूजमैंट पार्क की आवश्यकता है? अगर मुख्यमंत्री यह

समझते हैं कि इस एम्यूजमैंट पार्क की आवश्यकता नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री महोदय इस मामले पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि किसानों की भूमि कम से कम और जितनी निहायत जरूरी होगी, उतनी ही ली जायेगी। सरकार का इस बारे मैं इरादा स्पश्ट है। जहां तक एम्यूजमैंट पार्क का ताल्लुक है, सरकार की इस बात की पूरी कोशिश होगी कि यह उसी भूमि पर बनाया जाये जो जरखेज नहीं है, उपजाऊ नहीं है। मैं इसके लिए थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहूंगा क्योंकि अमेरीका में वह पार्क देखने का मुझे मौका मिला है। (विघ्न) दोनों ही मैंने देखें है। 25 डालर प्रति व्यक्ति उसकी टिकट हैं 25 डाजर का मतलब 500 रूपये है। उसमें जब से सृश्टि की रचना हुई हैं तक से लेकर आज तक यानी चन्द्र लोक तक की यात्रा के सारे हालात वहां पर दर्शाये गये हैं। जो भी आदमी अमेरिका में जाता है, उसकी इच्छा यह जरूर होती है कि वह उसको देखने जाये। हमारी यह जगह दिल्ली के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। यह इन्टरनैशनल पालम एयर पोर्ट से केवल 25 किलोमीटर के फासले पर हैं। हरियाणा के टूरिजम डिपार्टमैंट की यह सोच है कि अगर वहां पर इस प्रकार का मनोरंजन पार्क बन जाये तो जो भी आदमी दिली में आयेगा, वह उसे देखने की इच्छा जरूर रखेगा। मैं सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी बताना चाहूंगा कि एक दिन में वह पूरे दृश्य देखना मुश्किल होगा। एक दिन में भी वह पूरीतरह से उसे

नहीं देख पायेगा। हमीर सरकार का मन्शा केवल सरकार की आमदनी बढ़ाने का है। किसान का नुकसान करने का नहीं है। इसके अलावा हमारी सरकार की यह सोच होगी कि उस भूमि पर ही यह मनोरंजन पार्क बनाया जाये जो बंजर है, बेकार है और पहाड़ पर है। उसका एक फायदा और भी होगा। दिल्ली पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से हरियाणा सरकार को 138 करोड़ रूपया नये दरख्त लगाने के लिये दिया गया है। प्रदूशण को रोकने के लिये जो यह पैसा दिया जा रहा है, इसका फायदा भी पहुंचेगा। दिल्ली में आज दूसरे नम्बर पर सबसे ज्यादा प्रदूशण हो रहा है। इस नाते से भी वह जगह ठीक रहेगी ओर रैवेन्यू भी आयेगा। वहां पर हम यह भी देखेंगे कि उनके रहने के लिए भी कोई प्रबन्ध हो। इसलिए हमरी सोच यही होगी कि जो अमेरिका में बना हुआ हे, वह तो आर्टीफिशियल है लेकिन संयोग से जिस भूमि पर हरियाणा सरकार बनाने की योजना बना रही है, वह नैचुरल है, पहाड़ है, लेक है। इसमें भी बचल हो सकती हे। जो लोग आयेंगे, उनके देखने के लिए वहां पर दार्शनिक नजारा होगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकार इस प्रकार का ऐम्यूजमैंट पार्क ऐस्टेबलिश करने की सक्षम है या यूनियन गवर्नमैंट से कोई परमिशन लेनी पड़ती है? अगर परमिशन लेनी पड़ती है तो क्या इस बारे में प्रदेश और यूनियन गवर्नमैंट के बीच में खेतों–किताबत हुई है?

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं सम्बन्धित सम्मानित सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, टूरिजम डिपार्टमैंट की तरफ से यह प्रपोजल है। वह एक अथारिटी बना रहा है। उसके तहत उस एम्यूजमैंट पार्क बनाने के लिए जितना पैसा उन्हें दरकार होगा, वह मिल सकेगा और केन्द्रीय सरकार से इस परपज के लिए हम पैसा नहीं मांगने जा रहे हैं।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

तारांकित प्रश्न न. 1100 पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देना

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप क्वैश्चन आवर और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि हाफ एन आवर डिस्कशन वाली बात तो अभी आपने मानी नहीं है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद इस पर डिस्कशन की और आगे आवश्यकता होगी।

आवाजें: ठीक है, स्पीकर साहब, क्वैश्चन आवर का समय बढ़ा दीजिए।

Mr. Speaker: Please listen to me. I am very sorry to say that according to the Rules, I cannot extend the Question Hour.

Dr. Mangal Sein: It is all right, Sir.

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा एक सुझाव है अगर आप वह सुन लेते।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, तकरीबन चौबीस पच्चीस मिनट यह क्वैश्चन चला है। (शोर एवं व्यवधान) पिछले तीन सालों का मुझे तजुर्बा है कि इससे पहले कोई सवाल इतनी देर तक नहीं चला।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह सवाल बहुत अहम है इसलिए इसका समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए तो पच्चीस मिनट तक यह सवाल चला है।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने अच्छे ढंग से जवाब देने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से एक आग्रह करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि ऐम्यूजमैंट पार्क के लिए कम से कम जमीन किसानों की ली जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि सरकार को भी काफी फायदा होगा और पौल्यूशन में भी फर्क पड़ेगा। स्पीकर साहब, चूंकि इस जमीन को 1857 के गदर में अंग्रेजों ने जब्त किया था इसलिए इस जमीन के साथ वहां के लोगों का भावनात्मक रिश्ता जुडा हुआ है। इसलिए उन लोगों केा यह तकलीफ है। वे कहते हैं कि हमारी इस काश्त की जमीन को न लिया जाए। हमने यह जमीन आजादी के बााद खरीदी। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह

करूंगा कि उन लोगों की भावनाओं को देखकर उस जमीन को न लिया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इस जमीन की बजाए पहाड़ी एरिया में जो जमीन है, उसको ले लिया जाए। इससे किसानों का नुकसान भी नहीं होगा। इस प्रपोजल को पहाड़ी क्षेत्र में ले जाने की कृपा करें जिससे कि दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस विशय पर विस्तृत जानकारी सदन को दी जाए। यह सवाल छः माननीय सदस्यों का है। माननीय सदस्यों की ओर से इस विशय पर तीन काल अटैन्शन मोशंज दिए गए और उनके जवाब में आपने कहा कि क्वैश्चन नम्बर 1100 पर आपको बोलने का अवसर मिलेगा। जब सरकार जवाब देना चाहती है और चार सदस्यों ने आधा घंटे की डिस्कशन के लिए आपकी सेवा में प्रार्थना की है, तो आप इसकी इजाजत दे दीजिए। Under Rule 57 of the Rules of Procedure and Conduct of Business there is provision for half-an-hour discussion and the Govt. is also ready to give answer on this aspect. अध्यक्ष महोदय, यह एक अहम मसला है। बहुत सारे गांव इसमें इन्वौलवड हैं। वहां के लोग परेशान हैं। गांवों के सैकड़ों लोग इनसे मिल चुके हैं। पच्चीस सरपंच इनको मिल चुके हैं। वे इस बात की संतुश्टि चाहते हैं कि उनकी जमीन नहीं ली जाएगी मेररी हम्बल सबमीशन है है कि आधा घंटे की डिस्कशन आप

अलाउ कर दें। इस विशय पर डिस्कशन होने से सारी स्थिति स्पश्ट हो जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सूरजभान: रूलिंग देने से पहले आप सदस्यों के विचार सुन लीजिए।

Mr. Speaker: Please listen to me also.

चौ. ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जब इस हाउस के सम्मानित सदस्य बहुत उत्सुक हैं और इस बात के इच्छुक हैं कि आधा घंटा इस विशय पर विचार विमर्श होना चाहिए मेरा आपसे अनुरोध है है कि इनकी बात को मान लिया जाए लेकिन इनके साथ ही यह अर्ज जरूर करूंगा कि आज के दिन यह सम्भव नहीं होगा। किसी अगले दिन के लिए इसको रख लिया जाए।

Dr. Mangal Sein: In the light of my friends's suggestion and the Hon'ble Chief Minister' coming forward openly with an offer that half-an-hour discussion may be allowed. I would request you that you please accede to his request and honour our sentiments.

Mr. Speaker: Alright, Monday the 19th March, 1990, is the nex working day, Half-an-hour discussion on this issue is allowed on that day.

आवाजें: धन्यवाद जी।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

***1080. Shth Lachhman Dass Bajaj**: Will the Minister for Home be pleased to state the present stage of construction of Karnal Oil Refinery?

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): तेल शोधक कारखाना, करनाल का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

Construction of metalled Link Roads in Rewari Constituency

***1088. Capt. Ajay Singh Yadav**: Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following metalled Link roads in Rewari Constituency:-

Rewari to Ramgarh

(i) Lokri to Dakiya -2 Kms.

(ii) Gokulpur to Khumbawas.

(iii) Budani to Phadni

(iv) Nikhri to Rasgan via Dungarwas

(v) Assadpur to Malahera

(vi) Kalaka to Sangwari

(vii) Jadra to bodia Kamalpur

(ix) Bhudala to Sangwari; and

(b) if so, the time by which the above-said roads are likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज):

(क) रिवाड़ी से रामगढ़ सड़क को छोड़कर किसी अन्य लिंक सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) रिवाड़ी से रामगढ़ तक सड़क पूरी हो चुकी है, सिवाय पुल के जिसका 1990–91 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। दूसरी लिंक सड़कों के लिए कोई अवधि निर्धारित नही की जा सकती।

Profit/Loss to Haryana Roadways

***1077. Shri Parma Nand**: Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) the names of Haryana Roadways depots, if any, running in loss during the years 1988-89 and 1989-90 togetherwith the amount& reasons of losses in each depot year wise, separately; and

(b) the steps, if any, taken or proposed to be taken to check the said losses?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह):

(क) वर्श 1988–89 व 1989–90 में हरियाणा राज्य परिवहन के निम्न डिपो में हानि हुई। हानि की राशि प्रत्येक डिपो के आगे दिखाई गई है:–

क्र.स.	हरियाणा राच्य परिवहन के डिपो का नाम	हानि की राशि (लाख रूपये में)
	1988–89	
1	कैथल	45.52
2	भिवानी	73.31
3	फतेहाबाद	0.55
	1989–90 (अप्रैल–दिसम्बर, 1989)	
1	भिवानी	121.71
2	फरीदाबाद	50.94
3	रोहतक	38.73
4	हिसार	18.48

5	सिरसा	22.42
6	फतेहाबाद	8.12

उपरोक्त डिपो में वर्श 1988–89 व 1989–90 मैं हुई हानि के मुख्य कारण इस प्रकार से हैं:–

1. ग्रामीण क्षेत्र के छोटे मार्गो पर अधिक परिचालन जिससे प्रायः आय प्राप्पि कम और गाड़ियों की अधिक क्षति के कारण परिचालन व्यय अधिक उठाना पड़ता है।

2. निकटवर्ती पंजाब राज्य मैं परिचालन व्यवस्था ठीक न होने, निली परिचालकों के अवैध परिचालक, अधिक वर्शा, संसदीक/विधान सभा चुनाव के कारण हरियाणा राज्य परिवहन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

3. बस चैसिज की कीमतों, बस बौडी निर्माण पर अधिक व्यय, टायर टयूब, स्पेयर पार्टस की कीमतें बढ़ने से तथा अमले को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किश्तें देने से, नौर्म के बढ़ाने इत्यादि से हरियाणा राज्य परिवहन को अधिक वित्तीय भार उठाना पड़ा।

(ख) हरियाणा राज्य परिवहन के घाटे को कम करने के लिए उठाए गए पगों का विवरण नीचे दिया जाता है:–

1. हरियाणा राज्य परिवहन की आय की चोरी को रोकने तथा निजी परिचालकों द्वारा अवैध परिचालन को रोकने के लिए मार्गों पर कड़ी चैकिंग।

2. अग्रिम बुकिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना।

3. समय समय पर हरियाणा राज्य परिवहन के डिपो के कार्य परिणामों की समीक्षा तथा उनमें सुधार लाने के लिए भरसक प्रयत्न।

4. कर्मशालाओं की कार्य कुशलता और कर्मशाला व्यय को कम करने के लिए उन पर कारगर नियन्त्रण और निगरानी इत्यादि।

Mini Buses

***1086. Shri Yogesh Chand Sharma**: Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether any new Mini Buses have been purchased by the Transport Department during the period from 1st June, 1987 to date; if so, the number thereof alongwith the detail of cost and make of each said Buses?

परिवहन राज्य मंत्री: (श्री धर्मबीर सिंह):

क्र.स.	निर्माता का नाम	मिनी बसों की संख्या	कीमत

1	स्वराज माजदा लि.	20	एक मिनी बस की चैसिज की कीमत 177403.92 रूपए।
		1	एक मिनी बस जोकि बनी हुई है, जिसकी कीमत 260000 रूपए है।
2	डी.सी. एम. टोयोटा	20	एक मिनी बस की चैसिज की कीमत 175442 रूपए है।
3	आईशर मिततुबिसी	20	एक मिनी बस चैसिज की कीमत 178200 रूपये है।

निदेशक, पूर्ति एवं निपटान, हरियाणा द्वारा 500 मिनी बसें खरीदने के लिए निम्न प्रकार से सप्लाई के आदेश किए गए है:–

क्र.स.	निर्माता का नाम	मिनी बसों की संख्या	कीमत

1	टाटा इन्जीनियरिंग लोकोमोटिव लि.	20	215760 रू. प्रत्येक चैसिज।
2	अशोका लेलैण्ड लि.	20	211971.99 रू. प्रत्येक चैसिज 1 एक्स वर्क।
3	डी.सी.एम. टोयोटा	154	221240 रू. प्रत्येक चैसिज।
4	आईशर मितसुबिसी	153	225955 रू. प्रत्येक चैसिज।
5	स्वराज माजदा	153	228849.57 रू. प्रत्येक चैसिज।

Reservation to family Members of Freedom Fighters

***1084. Shri Surender**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give reservation in appointments to the dependents of the freedom fighters in the State; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला): भूतपूर्व सैनिकों अथवा पिछड़ी श्रेणियों के न भरे गये रिक्त स्थानों के स्थान पर

स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में सीधी भर्ती में 2 प्रतिशत आरक्षण है।

Exemption of Electricity duty

***1082. Shri Ved Singh Malik**: Will the Minister for Irrigations & Power be pleased to state-

(a) whether M/S Swastik Udyog Ltd., Hisar has been given exemption of Electricity duty; and

(b) if so, the reasons thereof togetherwith the action taken thereon?

मुख्यमंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला):

(क) मैसर्ज स्वास्तिक ऐन्टरप्राईजिज (अब मैसर्ज स्वास्तिक उद्योग लिमिटेड) तथा हिसार को वर्श 1980 में बिजली कर की अदायगी से छूट प्रदान (ख) की गई थी। किसी प्रकार इसके पश्चात् 1986 में जब यह पता चला कि यह इकाई छूट प्राप्त करने के योग्य नहीं थी, तब प्रदान की गई छूट मूल तिथि से वापिस ले ली गई।

Upgradation of Schools in Jagadhri Constituency

***1093. Brij Mohan**: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Higher Secondary School to 10+2 Upgradation of Schools in Jagadhri Constituency System School in Jagadhri Constituency during the year 1990-91, if so, the number thereof.

शिक्षा तथा विकास मंत्री (श्री हुकम सिंह): जी नहीं। इस समय कोई मामला विचारधीन नहीं है किन्तु जब भी कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर अन्य मामलों के साथ नौर्म अनुसार विचार किया जायेगा।

Settingup of 66 K.V. Station at Ambala City

***1094. Shri Shiv Parshad**: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a 66 KV Station at Ambala City, if so, the time by which the said Station is likely to be set up?

मुख्यमंत्री (चौ. औम प्रकाश चौटाला): हां। अम्बाला शहर में 66 के.वी. उप केन्द्र वर्श 1991–92 में पूर्ण होना निर्धारित है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Declaration of Haryana Area as Industrially Backward

183. Shri Udai Bhan: Will the Minister for Home be please to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to declare Hassanpur area in Faridabad district as an Industrially backward Area; and

(b) if so, the time by which the aforesaid area in likely to be decalred?

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह):

(क) नहीं।

फिर भी पलवल उपमण्डल को पिछड़ा औद्योगिक क्षेत्र घोशित करने बारे विचार हेतु आंकड़े एकत्रित किए गए है। हसनपुर क्षेत्र पलवल उपलमण्डल में आता है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

Cases filed by Municipal Committees

184. Shri Lachhman Dass Bajaj: Will the Minister for Local Govt. be pleased to state the total number of cases filed by or against the Municipal Committees in the State of Haryana pending in the High Court for the State of Punjab and Haryana up-to-date?

स्थानीय शासन मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल):

415. मामले नगर पालिकाओं द्वारा या नगरपालिकाओं के विरूद्ध पंजाब तथा हरियाणा, उच्च न्यायालय में लम्बिल हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

क्र.स.	जिले का नाम	उच्च न्यायालय में लम्बित नगरपालिकाओं द्वारा दायर	उच्च न्यायालय में लम्बिल नगरपालिकाओं के विरूद्ध	कुल

		किये गये केसों की संख्या	दायर किये गये केसों की संख्या	
1	2	3	4	5
1	अम्बाला	2	33	35
2	यमुनानगर	2	30	32
3	कुरूक्षेत्र	10	45	55
4	कैथल	2	20	22
5	करनाल	1	21	22
6	पानीपत		12	12
7	सोनीपत	2	17	19
8	फरीदाबाद	5	14	19
9	गुड़गांव	7	14	21
10	रेवाड़ी	3	25	28
11	नारनौल	3	6	9
12	रोहतक	2	25	27

13	हिसार	2	62	64
14	सिरसा	3	10	13
15	भिवानी	1	15	16
16	जीन्द	8	13	21
		53	362	415

Upgradation of Schools

185. Shri Shiv parshad: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Schools during the year 1990-91 in the State; and

(b) if so, the number there of?

शिक्षा तथा विकास मंत्री (श्री हुकम सिंह):

(क) जी हां।

(ख) वर्श 1990–91 राज्य में 100 प्राथमिक, 50 माध्यमिक तथा 25 उच्च स्कूलों को स्तारोन्नत किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Instructions for making amendment in Bye-laws

186. Shri Hira Nand Arya: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether the Govt. has issued any instructions to all affilliated Colleges in the State to amend their bye-laws in accordance with the recommendations of the High Powered Committee during the year 1978;

(b) if so, the names of Colleges out of those referred to in part (a) above, have refused to amend their bye-laws;

(c) whether the Government is aware of the fact that the payment of grant-is-aid any Colleges as referred to in part (b) above has also been made during the year 1979 to 1981 despite the fact that they have refused to amend the bye-wise; if so, the reasons therefor;

(d) whether it is also a fact that payment of grant-in-aid is not made to those Colleges which have amended their bye-laws subsequently as required by the Govt.; if so, the number of such Colleges together with the reasons for not giving the grant-in aid; and

(e) whether it is also a fact that Civil Proceedings in the Court at Chandigarh for claiming the damages; if so, the details thereof?

शिक्षा तथा विकास मंत्री (श्री हुक्म सिंह):

ए. जी नहीं। लेकिन सरकार ने वर्श 1977 में सर्वेक्षण कमेटी नियुक्त की थी न कि उच्च स्तरीय कमेटी और उसकी सिफारिशों के आधार पर सभी सम्बन्द्ध अराजकीय महाविद्यालयों को वर्श 1979 में अपने उपनियमों को संशोधित करने की हिदायतें जारी की गई थीं।

बी. 1 एस.ए. जैन कालेज, अम्बाला शहर।

इस महाविद्यालय ने इस आधार पर छूट मांगी थी कि उनकी अल्पसंख्यक संस्था है। जब उन्हें यह छूट नहीं दी गई तो प्रबन्धकों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई तथा उच्च न्यायालय ने उनके तर्क को मान लिया सरकार ने इस विशय में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में एल.पी.ए. दायर की है, जो अभी तक लम्बित है।

2. रूरल शिक्षण महाविद्यालय कैथल।

वर्श 1981 मे यह सूचित किया गया था कि सोसायटी ने सरकार के निर्देशों अनुसार अपने उप नियम संशोधित कर लिए हैं तथा गवर्निंग बौडी पुनर्गठित कर ली है। नियमों के संशोधन तथा गवर्निंग बौडी के पुनर्गठन को सोसायटी के मैनेजर द्वारा कानूनी अदालत में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि उप नियमों में संशोधन ठीक तरह से नहीं किया गया था। कालेज के प्राचार्य ने सूचित किया है कि अब सोसायटी ने 1.12. 1988 से उप नियम संशोधित कर लिए हैं।

सी. जी हां। सरकार ने संस्थाओं को अपने उप नियम संशोधित करने के लिए समय बढ़ा दिया था। अतः उन कालेजों को भी अनुदान दिया गया जिन्होंने अपने उप नियम संशोधित नहीं किए थे। रूरल शिक्षण महाविद्यालय कैथल को वर्श 1978–79 में अनुरक्षण अनुदान दिया गया था लेकिन वर्श 1979–80 तथा

1980–81 में अनुरक्षण अनुदान नहीं दिया गया। इन वर्शों में अनुरक्षण अनुदान पर रोक उप नियमों को संशोधन न करने के आधार पर नहीं अपितु अन्य कारणों से लगाई गई थी।

डी. जी नहीं। किसी भी कालेज को इसलिए अनुरक्षण अनुदान देना बन्द नहीं किया गया कि उन्होंने अपने उप नियम सरकारी हिदायतों के पश्चात संशोधित कर लिए हैं तथापि छः सम्बद्ध कालेजों को अब ग्रांट नहीं दी जा रही है। उनमें से तीन कालेज अपनी इच्छा से ग्रांट नहीं ले रहे हैं। दो नए स्थापित कालेजों ने सरकार द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार कालेज चलाने का खर्च स्वयं वहन करना है तथा शेश एक कालेज की ग्रांट कुछ अनियमितताओं एवं विभाग के निर्देशों की पालना न करने के कारण रोकी गई है।

ई. जी हां। रूरल ऐजूकेशन सोसायटी कैथल ने चण्डीगढ़ की अदालत में मुकदमें दायर किए हैं जिनमें उसने कालेज तथा स्कूल की सम्पति की हानि के कारण सरकार तथा सोसायटी के कई सदस्यों से हरजाने की मांग की है। यह केस अभी कोर्ट में लम्बित है।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर से बच्चे उठाए जाने के सम्बन्ध में जो कालिंग अटैन्शन मोशन मैंने दिया था उसका क्या हुआ?

डा. बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, बच्चे उठाने के बारे में बहिन जी के साथ मैंने भी कालिंग अटैन्शन मोशन दिया था।

श्री अध्यक्ष: यह चूंकि लेट मिला था इसलिए that is under consideration.

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, यह बड़ा गम्भीर मामला है।

Mr. Speaker: I agree that this is very serious matter and I am considering it.

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, दो बच्चों को उठा लिया गया है और वे अब उन्हें छोड़ने के लिए तीन लाख रूपये की मांग कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठिए।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुझे अफसोस है कि आप सब इकट्ठे बोल रहे हैं। जब आप बोलते हैं तो मैं ध्यान से सुनता हूं। इसलिए जब मैं बोलू तो कम से कम आप भी मेरी बात सुन लिया करें। मैंने बहिन जी को और डाक्टर साहब को पहले ही कह दिया है कि that is under consideration. (Interruption)

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, आप कृपया मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, आप ऊपर की ओर देखकर न बोलें। आप कृपया बैठिए।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, ये नए मैम्बर हैं। इन्हें कृपया रिब्यूक न कीजिएगा।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, मैंने इनको कह दिया था कि आप बैठिए, लेकिन इसके बावजूद ये बोल रहे थे। मैंने पहले ही इस बारे में आई काल अटैन्शन मोशन के बारे में कह दिया था कि वह अन्डर कंसीड्रेशन है लेकिन ये फिर भी बोलने रहे। Is it the way? मैं आप पर ही इसका फैसला छोड़ता हूं।

Dr. Mangal Sein: You can advise him.

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से हाउस में एक बात कहना चाहता हूं कि चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह जी जब बोल रहे थे तो इन्होंने 1857 के गदर का नाम लेकर के सम्बोधित किया था। मुझे उस गदर नाम पर बड़ा ऐतराज है। वह तो एक देश भक्तों की क्रान्ति थी जिसकों इन्होंने गदर का नाम दे दिया। इसलिए यह शब्द कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, वह शब्द गलती से निकल गया था। I stand corrected और उसे मैं विदड्रा करता हूं। मेरा मतलब स्वतन्त्रता संग्राम से था।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

तहसील नारनौल में 11–3–1990 की औलावृश्टि के कारण फसलें नश्ट होने सम्बन्धी।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received notices of calling attention motion Nos. 10 & 12 (bracketed with No. 1)) from Sarvshri Kailash Chand Sharma and Ram Bilas Sharma, M.L.As. respectively regarding crops damaged due to hail-storm on 11th March, 1990 in Tehsil Narnaul. I admit these. अब भी कैलाश चन्द शर्मा अपना नोटिस पढ़ दें। दूसरा नोअिस पढ़ा हुआ समझा जाएगा। उसके बाद यदि कंसर्न्ड मिनिस्टर साहब स्टेटमैंट देना चाहें तो दे दें।

@ **श्री कैलाश चन्द शर्मा**: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विशय की और दिलाना चाहता हूं कि 11.3.1990 को शाम के जब किसान खुशी से रंगों का त्योहार होली मना रहे थे तो ईश्वर की ओर से एक भयंकर संकट आया। नारनौल तहसील के रामवास, करोली, मरोली, हसनुपर, कंवारियावास, कमनियां, खतोली, नंगल शालु तथा भोजावास आदि गांवों में भयंकर ओलावृश्टि हुई तथा देखते

ही देखते सारी फसल, जिसके लिए वे खुशी मना रहे थे, तबाह हो गई। इन गांवों की 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक फसल बर्बाद हो गई है। दुःखी मन से बेचारे किसान चुपचाप देखते रह गए। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह किसानों के नुकसान का अंदाजा लगाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए प्रबंध करे तथा इस मामले पर सदन में एक वक्तव्य दे।

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि नारनौल से लगते क्षेत्र तथा हरियाणा के कुछ अन्य भागों में ओलावृश्टि से फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया है। प्राकृतिक आपदा के कारण सारे साल की मेहनत निश्फल हो गई है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह किसानों को इस संबंध में कुछ राहत प्रदान करे तथा इस मामले पर सदन में एक वक्तव्य दें।

वक्तव्य –

राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी

Revenue Minister (Rao Ram Narain): Speaker Sir, it is a fact that on day of Holi i.e. 11.3.90 there was hailstorm in Narnaul Tehsil in which 14 villages namely, Rambass, Karoli, Maroli, Hasanpur, Kanwriyaws, Kamanina, Khatoli Jat, Khatoli Ahir, Nangal Shaloo, Bhojawas, Nangal Pipa, Sirohi Bahali, Momanpur and Talot were affected. The revenue officials of the district immediately visited these villages to have an idea of

the loss to standing crops. It was found that premarily the loss was to matured standing crop of mustard. The Preliminary estimates indicate that overall loss in these affected villages was less than 25% as the total sown area during Rabi, 1990 in the villages was 8707 acres whereas the damage to crops occured in 1324 acres. The Deputy Commissioner, Mahendragarh has been directed to get the special girdawari conducted in all these affected villages immediately so that the exact extent of damage and loss to individual farmers could be ascertained. If as a result of special girdawari, the loss (Kharaba) to the standing crops of any farmer/tenant is found to be more than 25% he will be granted gratuitous relief as per criteria annd norms laid down by the State Government.

2. Gratuitious relief is granted to the affected farmers/tenants at a graded scale as per details given below :-

		Damage to standing crops (foodgains/oilseeds)	Damage to vegetable crops
(i)	Where the loss exceeds 75%	Rs. 400 per damaged acre.	Rs. 600 per damaged acre.
(ii)	Where the loss exceeds 50% but does not exceed 75%	Rs. 300 per damaged acre.	Rs. 500 per damaged acre.

(iii)	Where the loss exceeds 25% but does not exceed 50%	Rs. 200 per damaged acre.	Rs. 400 per damaged acre.

An amount equal to 5% of the total amount given as gratuitous relief for hailstorm damage to the farmers/tenants etc. in any village is also given in cash for distribution amongst agricultural workers (Harijans).

3. I would also like to apprise this August House that hailstorm had also occured in 20 villages on 4/5-189 and 5 villages on 10-2-90 and 4 villages on 27/28-2-90 in Hisar Distt. Similarly, there was hailstorm in one village of Gurgaon District on 17/18-2-90. Even in Narnual there was hailstorm in 13 villages on 25-2-90.

The reports received from district authorities in respect of these three districts indicated that the loss was insignificant and no gratuitous relief was warranted as per norms of the State Government.

4. 4 villages namely Mandhani, Hathlana, Manjura and Jundla of Karnal district were also hit by hailstarm on 13-2-90 and damage was caused to standing crops in 1147 acres in these 4 villages. The Deputy Commissioner had got a special girdawari conducted in all these villages and on assessing the actual 'kharaba' be requested for the allocation of Rs. 2.09 lacs for payment of gratuitous relief to the affected persons eligible for the grant of this relief. The amount was

placed at the disposal of Deputy Commissioner on 2-3-90 and it is now learnt from him that the relief has since been disbursed.

5. It will be seen that Government is fully aliveto the situated and very prompt action is taken to help the eligible persons affected by natural calamities like hailstorm etc. I would also take this opportunity to assure this august House once again that every effort is made and will be made by the State Goverment to mitigate the hardship of the affected farmers/tenants and agricultural workers (Harijans) in teh hailstorm hit areas as per criteria and norms prescribed by the Government.

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, जिस चौ. देवी लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस सयम ओलावृश्टि से फसलों को नुकसान होने पर सिकान को दी जाने वाली अनुदान रोहत की कुल राशि के 5 परसैंट के बराबर कृशक मजदूरों में बांटने की नकद राहत दी जाती थी। मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन गांवों में फसलों को नुक्सान हुआ है, उस नुकसीन के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में से क्या कृशक मजदूरों को भी हिस्सा दिया जाएगा?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, ऐसे केसिज में जो लैंडलैस लेबर हैं उसको भी टोटल रिलीफ का 5 परसैंट हिस्सा मिलता है।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, जब 1987 में इस प्रकार का संकट आया था, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चौ. देवी लाल जी ने स्वयं मौके पर जा करके किसानों को रिलीफ दिया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस समय कोई मंत्री या कोई उच्च नेता मौके पर जाकर किसानों को रिलीफ देंगे?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, ऐसी कोई नैचुरल कैलेमिटी नहीं आई है। मैं बताना चाहूंगा कि 25 परसैट से कम डैमेज है और वह भी करनाल जिले के चार गांवों में है। उन गांवों के किसानों को फौरन रिलीफ दिया गया और उसी समय बांट दिया गया।

वर्श 1990–91 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब 1990–91 के बजट पर डिस्कशन रिज्यूम होगी और श्री जय सिंह राणा बोलेंगे।

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी): स्पीकर साहब, आदरणीय उप–मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने सदन में जो 1990–91 का बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं बजट पर बोलते हुए अपने हल्के की और हरियाणा प्रदेश की कुछ बातें हाऊस के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सिंचाई के विशय में कहना चाहूंगा। स्पीकर साहब, हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदेश है

इसलिए इसमें सिंचाई के साधन अधिक से अधिक होने चाहिएं। पिछले दिनौं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने थानेसर के उप–चुनाव के कई उनसभाओं में घोशणाएं की थीं कि दादूपुर नलवी नहर और लाडवा सिंचाई योजना पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जिस तरह से एस.वाई.एल. कैनाल पर हरियाणा सरकार बहुत तेजी से काम करवा कर हरियाणा में पानी लाने की कोशिश कर रही है यह सराहनीय कदम है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि करनाल, कुरूक्षेत्र और अम्बाला जिलों में पानी का स्तर नीचे जा रहा है और वहां पर सिचाई के साधन भी बहुत कम हैं इसलिए इन दोनों योजनाओं की तरफ सरकार ध्यान दे और इन पर काम जल्दी शुरू करवाए। करनाल, कुरूक्षेत्र और अम्बाला जिलों के लोग यह इन्तजार कर रहे थे कि इस बजट में शायद इन दोनों योजनाओं के लिए कुछ धन राशि का प्रावधान किया जाएगा लेकिन जब बजट पेश हुआ तो पाया गया कि इसमें इन योजनाओौं के लिए पैसे का कोई प्रावधान नहीं है।

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): आप कौन सी योजनाओं की बात कर रहे हैं?

श्री जय सिंह राणा: मैं दादूपुर नलवी और लाडवा सिंचाई योजना की बात कर रहा हूं। एक बात मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि बिजली का भी कृशि से खास सम्बन्ध होता है। वैसे तो हमारी सरकार के अढ़ाई–पौने तीन साल के अर्से में किसानों कोा बिजली बहुत अच्छी मात्रा में मिली है, फिर

भी मैं एक ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता हूं जो धान उत्पीन क्षेत्र है और वहां पर बिजली की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैरे हल्के में आज से 10–12 साल पहले जो सब स्टेशंज बने थे आज भी वे उसी हलत में हैं, जबकि इन सालौं में बिजली की खपत कई गुणा बढ़ चुकी है ओर टयूबवैल्ज भी कई गुणा बढ़ चुके हैं। मैं उप–मुख्यमंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के के कई गुना बढ़ चुके हैं। मैं उप–मुख्यमंत्री जी की जनकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के के कई सब स्टेशंज जो 33 के.वी. के हैं, वे 66 के.वी. के और जो 66 के.वी. के सब स्टेशंज हैं वे 132 के.वी. के मन्जूर हो चुके हैं, लेनिक इन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मेरे हल्के मे जीरी की बहुत अधिक पैदावार होती है लेकिन वहां पर जीरी की फसल के सीजन में 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे बिजली मिलती है ओर यह भी शिफ्टों में मिलती है। वहां पर बिजली की बहुत कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सब स्टेशनों का जिक्र कर रहा था। मेरे हल्के के अमीन गांव में एक 33 के.वी. का सब–स्टेशन है उसकी मन्जूरी अब 132 के.वी. सब स्टेशन की हो चुकी है। इसी प्रकार से लाडवा में जो 66 के.वी. का सब स्टेशन है उसकी मन्जूरी भी 132 के.वी. की हो चुकी है। इसी प्रकार से एक सब स्टेशन और है उसकी क्षमता भी बढ़ाये जाने की मन्जूरी हो चुकी है। हमें दु:ख की बात है कि अभी तक जिन स्टेशनों की मन्जूरी हो चुकी है उन पर निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया। मेरी सरकार से मांग है कि

वहां पर जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य आरम्भ किया जाये ताकि लोगों को बिजली की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। आज के दिन मेरे हल्के में खासकर लड़कियों की शिक्षा की बहुत बुरी हालत है। मेरी सरकार से मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की तरफ विशेश ध्यान दिया जाये जिससे हमारे गांव की लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकें और पढ़ लिख सकें। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक कन्याओं के हाई स्कूल्ज को 10+2 के स्कूल्ज में अपग्रेड किया जाए। बजट में 2 नए कालेज खोलने का प्रस्ताव है। मेरी सरकार से मांग है कि इनमें से एक कालेज तरावड़ी में खोला जाये क्योंकि तरावड़ी के आसपास 30–30 किलोमीटर्ज के एरिया में कोई कालेज नहीं है। वहां पर ऐसे कालेज की बहुत अधिक मांग है। अगर यह कालेज वहां पर खोला जाता है तो बहुत बड़े ग्रामीण क्षेत्र का फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशय है। मेरे हल्के में प्राईमरी हैल्थ सेन्टरों की बहुत बड़ी कमी है और जो एक दो खुले हुए भी हैं उनकी बिल्डिंग बहुत खराब हालत में हैं। वहां पर मरीज तो बैठने दूर रहे, डाक्टर तक नहीं बैठ सकतें जब बारिश हो जाती है तो मरीजों को वहां से भागना पडत्रता है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जो प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज

नीलोखेड़ी ओर तरावड़ी में हैं उनकी अवश्य नई बिल्डिगें बनाई जायें।

अब मैं परिवहन के बारे में कहना चाहता हूं। करनाल डिपू में बसों की बहुत अधिक कमी है इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर बसों की संख्या बढाई जाये, क्योंकि बसों की कमी के कारण काफी–काफी देर तक लोगों को बस स्टैंडज पर खड़ा रहना पड़ता है। मैं उप मुख्यमंत्री जी ने नोटिस में यह भी लाया चाहता हूं कि तरावड़ी बिजनैस के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह है। वहां पर कोई बस नहीं रूकती। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि करनाल जिले मैं और अधिक बसें दी जाएं।

श्री अध्यक्ष: अब आप वाईड अप करिये।

श्री जय सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर अपने विचार रखना चाहता हूं। यह मसला न केवल हरियाणा के लिए बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर है। यह मसला है बेरोजगारी का। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने हालांकि बेरोजगारी के बेरोजगारी भत्ता देने की स्कीमें चलाई हैं जिसके तहत बेरोजगारों को 50 रूपये, 75 रूपये और 100 रूपये का भत्ता दिया जाता है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इतनी कम राशि से कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि इतनी कम राशि

से गुजारा नहीं हो सकता। यह समस्या बहुत ही जटिल है। इन बेरोजगारों को ऐसे साधन दिये जाने चाहिएं जिनसे रोजगार के साधन बढ़ें और इन बेरोजगारों को कुछ रोजगार के मामले में करनाल, कुरूक्षेत्र और अम्बाला जिले हमेश्ाा से उपेक्षित रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार आई रोजगार के मामले में, नौकरियों के मामले में इन तीनों जिलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज और एस.एस.एस. बोर्ड के पिछले आंकड़े देखें जाएं तो इस बात की पुश्टि होती है कि करनाल, कुरूक्षेत्र और अम्बाला के नौजवाबनें को पर्याप्त रोजगार नहीं मिला है। इन जिलों के मेरे दोस्त विधायक इस बात को जानते हैं कि इस बात को लेकर इन जिलों के लोगों में, बहुत रोश है कि हमारा हक कहीं और चला जाता है। प्रभावशाली लोग अपने क्षेत्रों के लोगों को सरकारी नौकरियां दिलवा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत ही गम्भीर है और इन लोगों में यह भावना पनपने लगी है कि यदि हमें हमारे हक नहीं दिये जा सकते तो हमें अलग कर दिया जाए या किसी अन्य स्टेट के साथ मिला दिया जाए। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार करे, कहीं ऐसा न हो कि लोगों यह भावना किसी आन्दोलन का रूप ले ले। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दौं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

11.00 बजे

श्री उदय भान (हसनपुर, अनुसूचित जाति): स्पीकर सर, परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लगातार तीसरी बार कर रहित बजट पेश करने के लिए यह सरकार बहुत ही बर्धा की पात्र है। इस बजअ से परम आदरणीय चौ. देवी लाल जी ने जनता से जो वायदे किये थे उनकी स्पश्ट झलक मिलती है। यह सरकार लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए कितनी प्रयत्नशील है इसकी झलक भी इस बजट से मिलती है। सरकार ने वायदा किया है कि दिसम्बर मास तक सारे हरियाणा प्रान्त में पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी न्यूनमत मजदूरी भी 800/– रूपये मासिक रखी गई है। सरकार का यह कदम भी सराहना के योग्य है।

स्पीकर सर, यहां पर हाऊस में महम के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। इस विशय में मैं इसकी पृश्ठभूमि की ओर जाना चाहता हूं। सन् 1987 में परम आदरणीय चौ. देवी लाल जी ने नेतृत्व में हरियाणा से हुए अन्याय के लिए न्याय युद्ध लड़ा गया था। सारे हरियाणा प्रान्त से कांग्रेस का जनाजा निकल गया थां परम आदरणीय चौ. देवी लाल के मजबूत कन्धों पर हरियाणा की जनता ने विश्वास व्यक्त किया था और उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात् उन्होंने जनता से भी वायदे किए थे उनमें से 70 फीसदी से भी ज्यादा

वायदे पूरे कर दिए थे। एक बार उनसे प्रश्न भी पूछा था कि जो वायदे आपने जनता से किये थे वह तो आपने पूरे कर दिये हैं तो अब आप क्या करेंगे? तब ताऊ ने जबावा दिया था कि अब मैं पूरे देश में जनजागरण अभियान चलाऊंगा। इस प्रकार चौ. देवी लाल जी का ध्यान पूरे देश में जनजागरण अभियान चलाऊंगा। इस प्रकार चौ. देवी लाल जी का ध्यान पूरे देश की तरफ लग गया और वे अपने प्रदेश यानी हरियाणा के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाये और पूरे देश से कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फैंकने के लिए जुट गए। उनका ध्यान उस तरफ बंट जाने के फलस्वरूप कुछ महात्वाकांक्षी व्यक्तियों ने कांग्रेस के साथ मिल कर, यहां सचिवालय में बैठकर राजनैतिक गाटियां बिठाई। चौ. देवी लाल की सरकार को कमजोर करने के लिए उनकी सरकार को गिराने के लिए एक भारी ाड़यन्त्र रचा गया जिसका नतीजा इस सरकार से अपना समर्थन वापिस लेने के रूप में सामने आया। लेकिन हरियाण की जागरूक जनता ने और इस सदन के जागरूक प्रतिनिधियों ने उप ाडयन्त्र को विफल कर दिया। उनका दूसरा चरण यह था कि लोक सभा के जब आम चुनाव हुए उस समय इस्तीफा देकर चौ. देवी लाल की सरकार को गिराने का ाडयन्त्र रखा गया, लेकिन उस समय भी हरियाणा की जनता और इस सदन के प्रतिनिधियों ने उस ाडयन्त्र को भी विफल कर दिया। स्पीकर सर, आपको मालूम है कि जिस तरह से चोट खाया हुआ सांप ज्यादा अधिक भयानक और जहरीला हो जाता है, उसी प्रकार से यह अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति चोट खाये हुए सांव की भांति

कांग्रेस के साथ मिलकर मेहम उप चुनाव के दौरान सारे इकट्ठे हो गये। इन्होंने एक ाडयन्त्र रचा जिसमें दो तीन पत्रकार भी शामिल हो गये। सभी को शामिल नहीं किया गया लेकिन दो तीन में से किसी को टिकट का लालच दिया, किसी को पैसे का लालच दिया। एक ऐसी भूमिका बना दी गई कि यह मेहम का चुनाव न्याय और अन्याय की लड़ाई है। स्पीकर सर, किन्हीं मुद्दों पर लड़ाई न लड़ कर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। चौबीसी की पगड़ी और मुख्यमंत्री की जिद की लड़ाई है। चौ. ओम प्रकाश चौटाला के समर्थकों को गुंडा वाहिनी और गुंडा ब्रिगेड कहकर सम्बोधित किया गया और उनको जेली ब्रिगेड कहकर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक भी कहा कि जहां भी जनता दल का विधायक मिले, उसको थप्पड़ मार कर स्वागत करो। जनता दल के दफतर को जला दिया, उनका झण्डा जला दिया। हमारे मुख्यमंत्री और उप–प्रधानमंत्री के काफले पर पथराव किया गया, कीचड़ फैंका गया लेकिन हमारे दल के किसी भी साथी ने उनके साथ उलझने की कोशिश नहीं की। लोगों में इस तरह का भय व्याप्त हो गया लोग डरने लगे कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरह से कर सकेंगे। मैं हरियाणा सरकार को इसके लिए ऐप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इन्होंने पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था कर के लोगों को इस लायक बनाया और उनके अन्दर से भय निकाला कि वे अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों का पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें और अने मत–पत्र मत पेंटियों में डाल सकें।

इस विशय में सरकार ने पूरी कामयाबी हासिल की और 27 तारीख को बहुत शान्ति प्रिय ढंग से पूरा चुनाव सम्पन्न हुआ। 8 बूथों पर चुनाव आयोग की सिफारिश पर 28 तारीरख का चुनाव हुआ। उस विशय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि 28 तारीख को क्या कुछ हुआ क्योंकि वह सबजुडिस मैटर है, लेकिन मैं सरकार की इस बारे में तारीफ करना चाहूंगा कि सरकार ने बिना विलम्ब किये 28 तारीख को हुई घटना के लिए न्यायिक जांच की घोशणा कर दी। 28 तारीख को श्री डांगी को यह पता चल गया था कि वे चुनाव हार रहे हैं और हमारे जो वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, वे अपने अपने स्थानों पर पहुंच चुके थे। उन्होंने जानबूझ कर वहां पर झगड़ा करने की कोशिश की जिसकी परिणति हिंसा के रूप में हुई। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर भी आकर्शित करना चाहूंगा कि अभी अभी बिहार में चुनाव के दौरान कुछ घटनाएं हुई। वहां पर जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया। वहां पर सैंकड़ों आदमी मारे गये। अब तो वहां की सरकार भी बदल गई है। उसमें किसी तरह की न्यायिक जांच नहीं करवाई गई। अमेठीक में सीधी गोली मार कर लोगों को उड़ा यिदा गया था। वहां पर भी किसी प्रकार की न्यायिक जांच नहीं हुई। मैं सरकार को ऐप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बिना बिलम्ब किए सरकार ने न्यायिक जांच की घोशित की। यह एक अभूतपूर्व कदम है।

इसके साथ ही मैं यह भी परामर्श देना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रैस से जो सम्बन्ध बिगड़ा रहे हैं, उन पर गम्भीरता से ध्यान दें। पब्लिक रिलेशंज डिपार्टमैंट जो इस बारे में पूरी तरह से सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने में अक्षम रहा है, उसका भी ओवरहाल करना चाहिये। अगर मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि मेरी लड़ाई प्रैस से है तो वह गलत कहा है और उस गलती को उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए। सभी प्रैस वालों से लड़ाई नहीं है, कुछ ही आदमी इस तरह के हो सकते हैं। मैं अपने सहयोगी दल के भाईयों से कहूंगा कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है वह भ्रमवश होकर की है। इस्तीफे की मांग करनी है तो इस ाडयन्त्र के करने वाले लागों को जनता के सामने लायें, जनता के सामने सच्चाई को लायें और अपनी नीतियों और तथ्यों से अवगत करायें। इन शब्दों के साथ मैं कुछ बातें बजट पर कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप टाईम का ख्याल रखें।

श्री उदय भान: स्पीकर सर, आरक्षण के बारे में, मैं यह कहूंगा कि कोई भीउ बैकलौग पूरा नहीं किया गया है। रिजर्वेशन के बारे में मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह इस मामले को गम्भीरता से ले और इस पर काम करे। कल जो फिगर्ज डा. किरपा राम पुनिया जी ने प्रस्तुत की थी, उनको गम्भीरता से लें। उनमें जो भी बैकलौग बताया गया है, उसको पूरा करने के लिये गम्भीर प्रयास करना चाहिये। यह ठीक है कि इस बारे में ज्यादातर

जिम्मेवारी कांग्रेस की है लेकिन जब से जनता दल की सरकार आयी है तब से इस बारे में कोई पर्याप्त प्रयास नहीं किये हैं ताकि यह बैकलौग पूरा किया जा सके जिससे कि हरिजनों में आत्मविश्वास बन सके और इस सरकार में उनका विश्वास कायम हो सके। इसके लिये पूरा प्रयास किया जाये। क्लास वन और क्लास टू की प्रोमोशन में रिजर्वेशन के मामले में भी कई बार बात आयी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवी लाल जी ने इनको यह आश्वासन दिया था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। पिछले सैशन में चौ. वीरेन्द्र सिंह जी ने भी कहा था कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन देने के बारे में भी हम सोच रहे हैं। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा है जबकि क्लास I और क्लास II में पंजाब में रिजवेंशन है, उत्तर प्रदेश में है, सेंटर में भी है और कितने ही दूसरे प्रदेशों में भी दी जा रही है। केवल हरियाणा में ही नहीं है। उस बारे में गम्भीरता से विचार करें। बी– I टैस्ट जो पुलिस में प्रोमोशन के लिये कांस्टेबल्ज को पास करना पड़ता है, पंजाब में वह भी नहीं है। पुलिस में शडयूल्ड कास्टस की बिनला टैस्ट पास किये ही प्रोमोशन दी जाती है। मेरा कहना यह है कि हरियाणा में शडयूल्ड कास्टस के लिये यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। एक बात और मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं। पिछले सदन में भी यहां पर आश्वासन दिया गया था। आदरणीय चौ. ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनने के बद 20 दिसम्बर की पहली बार जब फरीदाबाद जिले में गये थे तो पार्टी वर्कर्ज की मीटिंग में भी और

इस सदन में उन्होंने यह कहा था कि वहां पर गैस–बेस्ट थर्मल पावर स्टेशन बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिये में वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में स्थिति स्पश्ट करें कि यह गैस–बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन कब तक लगाने जा रहे हैं? इस बारे में सरकार का क्या विचार है?

इसके बाद मैं आगरा कैनाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आगरा कैनाल ऐसी कैनाल है जिसके ऊपर हामरे फरीदाबाद जिले के हरेक किसान की जीवन रेखा बंधी हुई। इस बारे में एक वाला भी आया था। 1962 से इस बारे में खतोकितावत चल रही है। मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि सरकार को उसमें सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। इस बारे में हरियाणा सरकार सही ढंग से अपना रवैया भी स्पश्ट नहीं कर पा रही है। मेरा यह अनुरोध है कि फरीदाबाद के किसानों को पूरा पानी दिलाने के लिये कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाये ताकि किसानों को खेतो के लिये पानी मिल सके।

अब मैं बस सर्विस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बस सर्विस के मामले में हमारा यह हाल है कि फरीदाबाद को खास तौर पर इग्नोर किया गया है। मैं इस बारे में तो सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा कि सरकार ने इस बार 500 नयी बसें लेने का निर्णय किया है लेकिन मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जहां पर जितनी बसों की आवश्यकता है, उसी आवश्यकतानुसार

बसें देनी चाहिये। फरीदाबाद जिले इस समय बहुत ज्यादा अवैध वाहन चले रहे हैं। वहां पर दो साल से कोई नयी बस नहीं मिल रही इसलिये में यह कहना चाहूंगा कि वहां के लिये पर्याप्त बसें देनी चाहिये ताकि वहां पर बस–सर्विस उपलब्ध हो सके। एक हमारे यहां उआवड़ में जो हथीन हल्के के पास है, पौलीटैक्निक खोलने की योजना छिले सरकार के समय से ही चली आ रही है। हमारे आदरणीय चौ. वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा था कि 1992 तक तो वह पूरा हो जायेगा लेकिन उटावड़ में जो सरकार ने इसके लिये डेढ़ दो लाख की व्यवसाि की थी, उससे वहां पर चार–दीवारी भी नहीं बन सकी। इस मामले में भी मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पौलीटैक्निक कालेज नहीं है। वहां पर जल्दी से जल्दी यदि पौलीटैक्निक बनाने का निर्णय यिका जाये तो बहुत मेहरबानी होगी। इसके अलावा मैं स्पीकर साहब, एक और बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। होडल में आई.टी.आई. के लिये पिछले 4–5 साल से जमीन ऐक्वायर करने के लिये सैक्शन 4 को नोटीफिकेशन हुआ पड़ा है। उससे आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एकदम पिछड़ा हुआ इलका है, वहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नही है कि वहां के बच्चे कहीं पर जाकर पढ़ सकें। इस बारे में भी कुछ न कुछ जरूर किया जाना चाहिये। तहसील का मामला मैं फिर उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, होडल हरियाणा में सबसे से बड़ी सब–तहसील है। वहां पर सबसे ज्यादा काम है और वहां पर सबसे ज्यादा पटवार सरकल्ज हैं। इसलिए वहां के लोगों की मांग है कि होडल को पूरी तहसील का दर्जा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, होडल कालेज में साईस क्लासिज खोलने का मंत्री महोदय आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन वह आश्वासन ही बना हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर साईस क्लासिज खोलने का शीघ्र प्रबन्ध करें। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती कमला वर्मा (यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट प्रस्ताव के लिए अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं। एक बात आमतौर पर से कहने में आती है कि जब सरकार अपना बजट बनाती है तो घर का बजट बिगाड़ देती है। आज हरियाणा की गृहणियां इस बात के लिए वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने घरों के बजट पर बोझ नहीं डाला। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अब तक जो कार्य किए हैं वे सराहनीय हैं और इस बजट के द्वारा आगे के लिये जो योजनाबद्ध तरीके से काम करने हैं उनको भी इसमें प्रतिबिम्बित किया गया है। उसके लिए मैं इन्हें बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि इन सारी योजनाओं को और ज्यादा अच्छे ढंग से कार्यान्वित करने के लिए काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय, का ध्यान पृश्ठ 9 की और दिलाना चाहती हूं। इस पृश्ठ पर उन्होंने नगरों के लिए 5

करोड़ 50 लाख रूपए जल सप्लाई तथा मल निकास व्यवस्था के लिए रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ 50 लाख रूपए इस व्यवस्था के लिए बहुत कम हैं। जिस वक्त आबादी कम थी उस वक्त गलियों में पाइपें बिछाई गई थीं। ये पाइपें सवा इंच या डेढ़ इंच की थीं। लेकिन अब आबादी बहुत बढ़ गई है। उन मोहल्लों के अन्दर पानी की बहुत अधिक तंगी होती है और गर्मियों के अन्दर तो लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। इतने कम पैसे रखने से शहरों का विकास असम्भव है। हरियाणा में आम आदमी यह कहता है कि सरकार का शहरों के प्रति रवैया अच्छा नहीं है। आपने सत्तर परसैंट बजट का पैसा गांवों के लिए रखा हैं, में इसकी प्रसंसा करती हूं। गांवों का भी विकास होना चाहिए लेकिन तीस प्रतिशत पैसा शहरों के विकास के लिए रखने से पानी की व्यवस्था और सिवरेज की व्यवस्था हो पाएगी यह सम्भव नहीं है। जब हम शहरों में जाते हैं तो देखते हैं कि स्लम एरियाज बढ़ रहे हैं क्योंकि शहरों की आबादी बढ़ रही है। प्रौपर्टी डीलर्ज अधिक रेट पर लोगों की जमीन बेच देते हैं लेकिन वहां पर न तो पानी का, न सिवरेज का और न बिजली का प्रबन्ध होता है। यमुनानगर में भी काफी स्लम एरियाज हैं और हरियाणा के दूसरे शहरों में भी स्लम एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। वहां की व्यवस्था ठीक नहीं हैं। (इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य, श्री आत्मा राम गोदारा, पदासीन हुए।) सभापति महोदय, इस दृश्टि से जल–सप्लाई तथा मल निकाल व्यवस्था के लिए जो धनराशि रखी

गई है वह थोड़ी है। मेरी प्रार्थना हैं कि अधिक धन का इस काम के लिए प्रावधान करना चाहिए।

सभापति महोदय, पृश्ठ 26 पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए 5 करोड़ 39 लाख रूपया का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, यह भी बहुत कम है। वित्त मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पूरे पैसे नहीं है तो वे नालियां व सड़कें कैसे बना सकते हैं और सिवरेज का काम कैसे कर सकते हैं? वर्शा अधिक होने से शहरों की सड़कें टूट गई थीं लेकिन आज दो वर्श होने को आए हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। सड़कों में खड्डे पड़े हुए हैं। रिक्शा में जब बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं तो खड्डों के कारण रिक्शा उलटने का डर बना रहता है और कई बार रिक्शा उलट भी जाती है। मेरी प्रार्थना है कि इस काम के लिए कम से कम पन्द्रह करोड़ रूपये रखा जाना चाहिए ताकि शहरों में सुधार हो सके और शहर के आम आदमी को सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहती हूं। इस मद में 182 करोड़ रूपया रखा गया है और यह रखना भी चाहिए। उद्योग व कृशि को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस मद में अधिक से अधिक रूपया रखना जरूरी है। मैं वित्त मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहती हूं कि जो बिजली के

तर लगे हुए हैं वे काफी पुराने हैं। किसी भी नगर में जिस वक्त ये तार लगाए गए थे उस वक्त मकान ज्यादा नहीं बने हुए थे। जगह खाली थी। अब मकान बन गए हैं और वह जगह कजस्टिड हो गई है। बिजली के तार लोगों के घरों के ऊपर से जाते हैं। उन तारों को बदलने की जरूरत है। तार छत के समीन होने की वजह से बच्चों द्वारा उनको हानि लगाने से उनके जीवन को खतरा रहता है। सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूं। गांवों के अन्दर जब नए कनैक्शन लेते हैं तब मीटर और तार आदि विभाग अपनी और से लगाता है लेकिन शहरों में जब कोई बिजली का कनैक्शन लेने के लिए ऐक्सीयन के पास जाता है तो उसको मीटर और तार आदि स्वयं लाने के लिए कहा जाता है। इस बार ने आम आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि गांव और शहर में सरकारी व्यवस्था का इतना भेदभाव क्यों है? सभापति महोदय, शहरों में भी गरीब लोग रहते हैं, रिक्शा चालक रहते हैं और मजदूर रहते हैं। एक–एक कमरा डालकर वे लोग अपना गुजारा करते हैं। उनको भी इस सुविधा यानी तार वे मीटर का फायदा होना चाहिए। नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं थर्मल प्लांटस के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। 1978 में यमुनानगर के अन्दर एक थर्मल प्लांट लगाने की स्वीकृति हुई थी और अब केन्द्रीय सरकार के एन.टी.पी. सी. को बनाने के लिए कह दिया है। दो हजार एकड़ भूमि उसके

लिये अभिग्रहण की गयी है। इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि एन.टी.पी.सी. वालों के ऊपर यह दबाव व शर्त लगाई जानी चाहिये कि जिन लोगों की इस थर्मल प्लाट के लिए जमीन ली गयी है उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को अवश्य ही वहां नौकरी दी जाए और यमुनानगर के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए ताकि लोग कुछ राहत महसूस कर सकें कम से कम 40 प्रतिशत तकनीकी व मजदूरी के लिए स्थानीय बच्चों को नौकरियां दी जानी चाहिये ऐसी मेरी प्रार्थना है।

सभापति जी, अब मैं बाढ़ नियन्त्रण से सम्बन्धित बात करने जा रही हूं। सरकार ने इसके लिये 9 लाख 50 हजार रूपये की राशि रखी है लेकिन यमुनानगर में कई गांव जैसे टापू कमालपुर व कलानौर का हिस्सा बाढ़ में आ जाते हैं। इसी तरह से रादौर क्षेत्र में सिंघाला, सिंघाली व जटलाना भी बाढ़ की लपेट में आ जाते हैं। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बाढ़ से इन इलाकों को बचाने के लिये वहां यमुना नदी पर स्टड लगाये जाने चाहिए ताकि बाढ़ की आफत से वहां के लोगों को बचाया जा सके।

समाज कल्याण के लिये हमारी सरकार ने काफी ध्यान रखा है और उसके लिये उचित पैसे की व्यवस्था भी की है। राज्य के वृद्ध नागरिकों को सुरक्षा तथा आत्म–सम्मान प्रदान करने के लिये पैंशन देकर काफी ठोस कदम उठाये हैं और पूरे राश्ट्र में इस उत्तम योजना के कारण हरियाणा को एक विशेश स्थान मिला

है। वृद्धावस्था पैन्शन के माध्यम से परिवारों का स्नेह और आदर बना हुआ है लेकिन इसके साथ–साथ मैं यह कहे बगैर भी नहीं रह सकती कि एक तरफ तो सरकार ने समाज कल्याण के लिये बड़े ही लाभप्रद कदम उठाये हैं वहां दूसरी ओर इस प्रदेश में शराब के बढ़ते हुए ठेकों ने हमारी युवा पीढ़ी के लिये गंभीर संकट पैदा कर दिया है। शराब हमारे बच्चों के चरित्र व स्वास्थ्य दोनों को खराब कर रहे हैं। आज पहले से कहीं अधिक ठेके हरियाणा राज्य में स्थापित हो गये हैं और यहां तक कि गांव की दुकानों के 12 बोतलों का रखने का सरकार ने जो प्रावधान किया है उससे हमारे बच्चों के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है। गांव के बच्चे स्कूल जाते समय एक किलो अनाज ले जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं कि इसके बदले हमें एक पैग पिला दो। सरकार को कम से कम इस बात को तो अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि यही बच्चे हमारे भावी राश्ट्र का निर्माण करने वाले हैं। अगर हम अपने बच्चों को इस समय न संभाल पाए तो आप ही अन्दाजा लगा सकते है कि राश्ट्र का भविश्य कैसा होगा? सभापति महोदय, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर इस तरह से बच्चे शराब की लत में पड़े रहे तेा कैसे वे अपने खेतों में, कल–कारखानों में काम कर सकेंगे? उनके स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे कर सकेंगे? सभापति महोदय, यह तो मैं मानती हूं कि सरकार को इससे काफी रैवन्यु मिलता हे इसी कारण ठेके बढ़े हैं। लेकिन कम से कम युवकों के भविश्य का भी तो सरकार का ध्यान रखना चाहिये। कोई सड़क आपको नहीं मिलेगी जहां पर कि

शराब का ठेका न हो। समाज कलयाण की दृश्टि से सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि शराब के ठेके ज्यादा न बढ़ाकर इसका अधिक प्रचलन रोका जाए और हरियाणा प्रदेश की समृद्धि में सहायक यानि युवा पीढ़ी की ओर विशेश ध्यान दिया जाए। बच्चों का भविश्य उज्जवल बने, वे इस बुरी आदत से छुटकारा पा सकें और ठेकों का प्रचलन कम हो ऐसी मेरी प्रार्थना है।

सभापति महोदय, रेल यात्रियों की जो नई सुविधाओं का केन्द्र सरकार ने ध्यान रखा, मैं उसके लिये केन्द्र सरकार की आभारी हूं। इसके साथ–साथ मैं अपनी सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को एक निवेदन करना चाहती हूं कि जगाधरी का जो स्टेशन है, उसका नाम बड़ा पुराना चला आ रहा है उसका नाम अब यमुनानगर जिला बनने के बाद यमुनानगर स्टेशन होना चाहिये। (घंटी)

सभापति महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं के सिलसिले में वित्त मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा कि पिछले वर्श की अपेक्षा इस वर्श कितनी अधिक राशि स्वास्थ्य सेवाओं के लिये रखी गयी है। चूंकि आये दिन दवाईयां काफी महंगी होती जा रही हैं, इसलिये अगर इस बात का साफा ब्योरा वित्त मंत्री महोदय दे देते तो अच्छी बात थी। भवन निर्माण पर भी महंगाई के कारण काफी ख्र्चा होता है लेकिन फिर भी अगर सरकार पूरा ब्यौरा दे देती तो इससे लोगों में एक आशा सी बन्ध जाती कि जन–स्ववास्थ्य के लिये सरकार

कितनी उत्सुक है और यह शिकायत भी न रहती कि अस्पतालों में औशधि कम मिलती है। अब यमुना नगर जिला बन गया है इसलिए वहां पर एक सौ बिस्तरों का हस्पताल होना चाहिए अगर जिले में 50 बिस्तरों का हस्पताल हो तो यह अच्छा नहीं लगता। अभी भी वहां चूंकि 70–80 रोगी दाखिल रहते हैं इसलिए इस वर्श अवश्य 100 विस्तरों के लिए राशि का प्रावधान कर दिया जाए। आयुवैदिक के लिए भी बहुत कम पैसा रखा गया है। जो पद्धति हमारी धरती के साथ जुड़ी हुई है उसके लिए बहुत ही कम पैसा रखा गया है, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। अब मैं कुछ बातें सड़कों के बारे में कहना चाहूंगी। दो वर्शो से नगरों में सड़कों की कोई मुरम्मत नही हुई। आज कल ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वर्शा आने के बाद सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसलिए सरकार को सड़कों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे तो सारे हरियाणा के नगरों की सड़कें खराब हैं पर वर्शा ऋतु व फ्लड आने के बाद यमुना नगर में सड़कों की मेंटीनैंस के लिए जो ऐडीशनल रकम दी जानी थी वह नहीं दी गई। यमुना नगर में एक सड़क फव्वारा चौक से अग्रसैन चौक तक जाती है। उस सड़क पर तीन हस्पताल भी है और बच्चों का स्कूल भी हैं वहां बहुत अधिक दुर्घटनाएं होती है। 32 लाख रूपए का ऐस्टिमेंट फोर लेनिंग के लिए भेजा जा चुका है, इसकी कृपया स्वीकृति दे दी जाए। वहां पर फोर लेनिंग होनी चाहिए ताकि रोज ऐक्सीडैटस न हो सकें। मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसने एक न एक

दिन अवश्य जाना है। आखिर में उसे शमशान घाअ ही ले जाया जाता है। शमशान घाट हमेशा बस्तियों से बाहर होती है और आम तोर पर बस्तियों को उससे जोड़ने के लिए पक्की सड़क नहीं होती है। यमुना नगर में तीन जगहें ऐसी हैं। एक तो कैम्प के लिए पक्की सड़क नहीं होती है। यमुनानगर में तीन जगहें ऐसी हैं। एक तो कैम्प से शमशाम घाट, दूसरे हमीदा से शमशान घाट और तीसरे रामपुरा से शमशान घाट तक जाने के लिए कच्चा रास्ता है। वह रास्ता इतना खराब है कि बरसात के दिनों में कई बार अरथी को नीचे उतारना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से पी. डब्लू.डी. मिनिस्टर से प्रार्थना है कि सारे हरियाणा में शमशान घाटों को बस्तियों के साथ पक्की सड़कों से जोड़ने का काम प्रायरिटी बेसिज पर किया जाए।

अब मैं शिक्षा के संबंध में कुछ कहना चाहती हूं। शिक्षा किसी भी राज्य की समृद्धि व विकास का आधार हुआ करती है। इस समय मैं पूरे हरियाणा का न बता कर केवल आपको यमुना नगर के बारे में ही बता रही हूं। वहां आज पाठशालाओं में ताजेवाला से नारायणगढ़ तक की पाठशालाओं में 36 पोस्टें खाली पड़ी हैं। सारे जिले में 60 पोस्टें जे.बी.टी. की खाली पड़ी हैं। बेरोजगार शिक्षक धक्के खा रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है जबकि स्कूलों के अन्दर जगहें खाली पड़ी हैं। शिक्षा मंत्री इस ओर अवश्य ध्यान दें और नियुक्तियां करें। अध्यापकों को शोशण भी हो रहा है। गवर्नमैंट एडिड प्राइवेट स्कूलों के अन्दर सैंक्शंड

पोस्टें नहीं दी जा रही हैं। किसी स्कूल के अन्दर अगर दो हजार बच्चे हैं ओर वह गवर्नमैंट एडिड प्राइवेट स्कूल है तेा वहां पर 10 पोस्टें तो सैंक्शंड हैं बाकी के लिये सरकार ने सैंकशन नहीं दी। ऐसा करने से बच्चो के साथ न्याय नहीं हो रहा है। कम वेतन देकर अध्यापक रखे जाते हैं जो मन लगा कर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसलिये इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार जे.बी.टी. ट्रेनिंग स्कूल खोल रही है। मैं चाहती हूं कि ऐसा एक स्कूल यमुना नगर में भी खोला जाए ताकि छछरौली, बिलासपुर, सढौरा और यमुनानगर के बच्चे वहां से ट्रेनिंग ले सकें और इन्हीं स्थानों पर उनकी नियुक्ति की जा सके। चार मास पहले कुछ स्कूल अपग्रेड हुए हैं लेकिन उनकी अपग्रेडेशन के बाद उनमें कोई नया विशय नहीं दिया गया है। जैसे मनोविज्ञान, ज्योग्राफी और दर्शन शास्त्र के विशय उन स्कूलों में नहीं दिए गए हैं। सारे अम्बाला जिला के अन्दर एक भी ज्योग्राफी का टीचर नहीं है। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि ये विशय स्कूलों में दिए जाएं। मैंने एक बात और कहनी है। सभापति महोदय, मैं मेहम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती चूंकि उसकी पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन इस बात को अवश्य कहूंगी कि जिस जनता के आज इतना बड़ा परिवर्तन करके हरियाणा और केन्द्र में हमें सत्ता दी है, उन लोगों की भावना का हमें आदर करना होगा। लोकतन्त्र में विश्वास हमारी पद्धति है। उसके प्रति हमें लोगों में विश्वास पैदा करना होगा कि हम लोकतन्त्र को जीवित रखेंगे। इन शब्दों के

साथ मैं बजट का समर्थन और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी): सभापति महोदय, जो 1990–91 का बजट पेश किया गया है मैं आपके द्वारा उस पर अपने विचार रखना चाहूंगा। यह जे बजट पेश कियाग या है यह कागजी, नीरस और दिशाहीन बजट है। सभापति महोदय, जो भी सरकार होती है उसके दो पहलू होते हैं। पहला डिवैल्पमैंट और दूसरा कानून और व्यवस्था। मेरे विचार में यह सरकार दोनों ही पहलुओं में असफल रही है। कानून और व्यवस्था के विशय में मैं मेहम का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा। मेहम में जो बाई इलैक्शन हुआ उसमें जिस प्रकार से प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र की हतया की गई उसी मिसाल कहीं पर भी देखने में नहीं आई और यह बात प्रैस में भी आई है कि वहां पर इस सरकार ने बहुत बड़ी पुलिस फोर्स तैनात की थी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मेहम बाई इलैक्शन में एक सुनियोजित तरीके से बूथ कैपचरिंग की और सारा काम इस सरकार ने वहां पर फुल प्रूफ तरीके से किया। (शोर) मैं कानून और व्यवस्था के विशय में बोल रहा हूं। क्या मेहम में कानून और व्यवस्था आपने ठीक रखी थी?

श्री सभापति: आप बजट पर बोलें। (शोर)

कैप्टल अजय सिंह यादव: सभापति महोदय, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं और बजट पर बोलते हुए ला एंड आर्डर की

सिचुएशन के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। जो इस सराकर ने मेहम में बाई इलैक्शन के दौरान काम किया है, उसके लिए इस सरकार को नौबल प्राइज मिलना चाहिए।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं डिजनीलैंड के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा। यह सरकार अपने अपको किसानों की सरकार कहती है। आज ही मुख्य मंत्री जी ने यह बताया था कि डिजनीलैंड में जाने के लिए हर आदमी को 500 रूपये की आवश्यकता पड़ेगी। सभापति महोदय, क्या कोई किसान मजदूर 500 रूपये देकर उसमें जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस मामले में हाउस को मिसलीड करने की कोशिश की है और साथ में कह दिया कि उस पार्क को टूरिज्म डिपार्टमैंट अपने बजट से बनाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस बारे में दोबारा विचार कर लें क्योंकि इस प्रदेश का पूरा बजट ही उस डिजनीलैंड को नहीं बना पाएगा, टूरिज्म डिपार्टमैंट अकेले तो उसको क्या बना देगा।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं एक बत यह भी पूछना चाहूंगा कि जो पोस्टर कम्पेन चलाई गई थी, उस कम्पेन से हिसार में जो काण्ड हुआ था उसमें इनवाल्वड कितने लोगों को पकड़ा गया? माननीय गृह मंत्री जी इस विशय में हमें बताएं। इसके बाद सभापति महोदय, मैं 2.–सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। इस बजट को पढ़ने से यह पता लगता है कि इस 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत चाहे जवाहर रोजगार योजना

है, चाहे फैमली–प्लानिंग की योजना का लक्ष था और चाहे प्लाटेशन का लक्ष्य था, सभी में यह सरकार फल हुई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस सरकार ने कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं किया। इसके साथ साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि इस 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस सरकार ने 1989–90 के दौरान 400 समस्याग्रस्त गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था लेकिन उस लक्ष्य के विरूद्ध यह सरकार जनवरी, 1990 तक केवल 260 गांवों को ही पेयजल की सुविधा दे पाई है। इस सरकार के लिए यह बड़े शर्म की बात है कि जो लक्ष्य इस सरकार ने निर्धारित किया था उसको ही पूरा कर पाई।

अब मैं सिचाई के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहूंगा। एस.वाई.एल. कैनाल के बारे में पहले ये लोग यह कहा करते थे कि हम दिल्ली की सरकार को घेरेंगे, उसका घेराव करेगें लेकिन अब इनकी खुद की पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठी है अब ये उसको एस.वाई.एल. कैनाल के विशय में घेरने की बात नहीं करते। अब सैंटर में भी आपकी सरकार है इसलिए आपको सैंटर की सरकार पर यह दबाव डालना चाहिए कि हमें एस.वाई.एल. से पूरे पानी का हिस्सा दिया जाए।

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): चेयरमैन साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने दिल्ली को तो बाकयदा घेरा हुआ है। राजस्थान में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी

सरकार है, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है और हरियाणा में हमारी सरकार है तो दिल्ली को तो हमने घेरा हुआ है।

श्री परमा नन्द: सभापति महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दिल्ली के चारों तरफ चार प्रान्तों में हमारी सरकार है और हमने दिल्ली को घेर रखा है। मे। उनसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार किसकी है? क्या ये अपनी सरकार को खुद ही घेरेंगें? (शोर)

श्री सभापति: यह कोई प्वायंअ औफ आर्डर नही है? आप कृपया बैठें।

कैप्टल अजय सिंह यादव: सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा इस सरकार से कहना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिले में कोई माईनर नहीं है और न ही कोई डिस्ट्रीब्यूटरी है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि नहर का टेल तक पानी जा सके। लेकिन सभापति महोदय, त्यागी साहब यहां हाउस में ही नहीं बैठे हैं तो मेरी इस बात को कौन नोट करेगा। कंसर्न्ड मंत्री को हाउस में मौजूद रहना चाहिए। (विघ्न) मैं यह कहना चाहता हूं कि एम. आई.टी.सी. ने महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिले में कोई भी कार्य नहीं किया है जिसके कारण पानी की सतह ऊपर आ सके। उन दोनों जिलों में पानी की बहुत भारी किल्लत है। मैं उप मुख्यमंत्री

महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस तरफ गम्भीरता से ध्यान दें ताकि वहां पर जल स्तर को ऊपर उठाया जा सके।

सभापति महोदय, अब मैं जन स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। इस काम के लिए सरकार ने रिवाड़ी शहर के लिए 3.47 करोड़ रूपये की एक स्कीम बनाई थी, पता नहीं अब किन कारणों से इस पर कार्य आरमी करने में विलम्ब किया जा रहा है। कमला बहन जी ने ठीक कहा है कि सारी स्टेट के लिए 5 करोड़ रूपये से कुछ होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मेरा सरकार को सुझाव है कि जिन गावों में पानी नहीं जाता वहां पर बूस्टर लगाने का प्रबन्ध किया जाये ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके।

सभापति महोदय, अब मैं को–आप्रेशन डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं। नेबार्ड द्वारा लैण्ड डिवैल्पमैंट के जरिए इंडस्ट्रियल एरिया साईड में 109 करोड़ रूपये मिलने की बजाये 33 परसैन्ट पैसा कम मिला है यानी 55 करोड़ रूपया मिला है। यह जो पैसा कम मिला है इसके बारे में मैं समझता हूं कि सरकार शायद अपना केस अच्छी तरह से उनके सामने नहीं रख पाई। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर कंज्यूमर्ज स्टोर्ज में ऐम्पलाईज काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। सरकार को उनको भी समय पर पे देने का प्रबन्ध करना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। रिवाड़ी में स्कूलों की नई बिल्डिगें नहीं बनाई गई हैं। मेरी सरकार से मांग है कि जिन–जिन स्कूलों की बिल्डिंगें खराब हो चुकी हैं वहां पर नई बिल्डिंगें बनाई जायें। मेरे हल्के में वैकटरमन जी द्वारा सैनिक स्कूल खोले जाने की घोशणा की गई थी लेकिन सरकार ने इस स्कूल को वहां परखोलने की बजाये मातनहेल में खोलने का निर्णय लिया है। मैं मातनहेल में इस स्कूल के खोले जाने का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि सारे हरियाणा में रिवाड़ी जिले में सबसे ज्यादा ऐक्स सर्विस मैन हैं और इस समय भी मिल्टरी में बहुत ज्यादा लोग हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि मेरे हल्के में सैनिक स्कूल अवश्य खोला जाये।

सभापति महोदय, सरकार ने एक मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया हुआ है। मेरी सरकार से मांग है कि भिवानी जिले का लोहारू, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिले को शामिल करके एक दक्षिण हरियाणा डिवैल्पमैंट बोर्ड बनायें। इस बोर्ड को बनाये जाने की पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन सरकार से इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस तरफ सरकार ध्यान दे।

सभापति महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। सरकार ने औ नई मिनी बसें खरीदने का निर्णय लिया है। मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि इन बसों

की चैसिज में डिफैक्ट है। ये बसें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इन बसों को खरीदने से सरकार को घाटा ही होगा इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि मिनी बसें न खरीदी जायें।

सभापति महोदय, अब मैं पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे हल्के में रिवाड़ी के अन्दर रिवाड़ी–जयपुर, रिवाड़ी–दिल्ली रोड और रिवाड़ी बाई पास बनाया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और शहर की आबादी भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इन रोडज को जल्दी से जल्दी बनाया जाये।

सभापति महोदय, मैं सरकार के ध्यान में यह भी बात लाना चाहता हूं कि जो कम से कम मजदूरी सरकार ने घोशित की हुई है वह भी धारूहेड़ा में लगी प्राईवेट इण्डस्ट्रीज के मालिकों द्वारा अपने कर्मचारियों को नहीं दी जाती है। इन कम्पनियों ने लोकल आदमी रखने की बजाये बिहार से आदमी लाकर रखे हुए हैं। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार उनको आदेश दे कि जब भी कोइ आदमी इनमें रखा जाना हो तो वह ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज के माध्यम से रखा जाये ताकि वहा के लोकल लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।

सभापति महोदय, अब मैं प्रौढ शिक्षा के बारे में और कान्फैड से निकाले गए कर्मचारियों के बारे में सरकार से कहना चाहता हूं। जिन कर्मचारियों की 10–10 साल की सर्विस हो गई

थी और जो पढ़े लिखे थे उनको अब नौकरी से हटा दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे निकाले गए कर्मचारियों को दुबारा से सर्विस में लिया जाना चाहिए। सभापति महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने अग्रोहा में एक मैडिकल कालेज खोलने का निर्णय लिया है। इस बारे में मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि दक्षिण हरियाणा के चार जिलों में न कोई मैडिकल कालेज है और न कोई इन्जीनियरिंग कालेज है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि यहां पर भी मैडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज खोला जाये। रिवाड़ी का जो हस्पताल है वहां पर कोई लेडी डाक्टर नहीं है, इसलिये सरकार को वहां पर भी कोई लेडी डाक्टर अवश्य भेजनी चाहिए। इस हस्पताल की हालत बहुत खराब है। वहां की ऐक्सरे मशीन भी काम नहीं कर रही है। इसी प्रकार से वहां पर कोई आई स्पैशलिस्ट डाक्टर भी नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर कोई आई स्पैशलिस्ट डाक्टर भी नहीं हे। मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर एक आई स्पैशलिस्ट डाक्टर भेजे। सिविल अस्पताल की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशय के बारे में कहना चाहता हूं। राईट टू वर्क के बारे में भी मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की इस बारे में क्या योजना है? राईट टू वर्क के सिलसिले में सरकार क्या करने जा रही है यह हमें बताया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही

सभापति महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा इस बजट का समर्थन नहीं करता।

श्री सरदूल सिंह (सफीदों): सभापति महोदय, इस महान सदन में जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस बजट में हरियाणा की तरक्की और बहबूदी की झलक मिलती है। उसके बाद वर्तमान सरकार ने जिस ढंग से अमनो–अमान को कायम रखा है मैं उसका भी समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, इसके बारे मैं अपने इलाके सफीदों की तरफ आता हूं। सफीदों एक तिजारती शहर है जिसकी खस्ता हालत के बारे में मैं पहले भी कई दफा इस हाऊस में कह चुका हूं लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहां की सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियों की हालत खस्ता हैं और जो सीवरेज बना है वह भी नाकारा है।

उसके बाद मैं सफीदों के स्कूल का जिक्र करना चाहूंगा। इस स्कूल को लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया था यह स्कूल बहुत अर्सा पहले बना था और अब इसकी छतों की हालत बहुत ही खस्ता है। यह भी भय है कि इस स्कूल को कोई छत गिर ही न पड़े जिससे बच्चों का नुकसान हो। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस स्कूल की तरफ ध्यान दिया जाए और इसकी बिल्डिंग नई बनवाई जाए।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं सफीदों के अस्पताल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सफीदों अस्पताल में कभी भी स्टाफ पूरा नहीं होता। स्टाफ पूरा न होने की वजह यह है कि सफीदों अस्पताल के साथ स्टाफ तथा डाक्टरों के रिहायश के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। न तो वहां पर कवार्टर्ज हैं और न ही कोई दूसरा इन्तजाम है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सफीदों शहर में जल्दी से जल्दी अस्पताल की बहबूदी के लिए क्वार्टर्ज बनाए जाएं। सभापति महोदय, सड़कों की हालत यह है कि वहां पर साईकलों का चलना भी मुश्किल है और मेरे जैसा बूढ़ा व्यक्ति तो पैदल चलते हुए भी वहां गिर जाता है। (विघ्न) इन सड़कों की मुरम्मत की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं बहादुरगढ़ से उरलाना की एक महत्वपूर्ण सड़क का जिक्र करना चाहूंगा। मार्किट कमेटी भी इस सड़क की रिपेयर नहीं करवाती है। इसलिए इस सड़क की रिपेयर अवश्य की जाए।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं अपने इलाके में बिजली की सप्लाई के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरे इलाके में डिडवाड़ा सब–स्टेशन और सिघना सब–स्टेशन बनने हैं। मेरे हल्के में बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों सब–स्टेशनों को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करवाने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मेरा इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। इस इलाके के बहुत से पढ़े–लिखे नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सफीदों में कोई बड़ी

फैक्टरी लगाई जाए ताकि इस इलाके के नौजवानों को पर्याप्त रोजगार मिल सके और वे अपना तथा अपने बाल–बच्चों को पालन–पोशण ठीक तरह से कर सकें। सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ में एक बार फिर इस बजट का समर्थन करता हूं और मुझे बोलने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हजार चन्द (सिरसा): चेयरमैन साहब, 14 तारीख को आदरणीय उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री महोदय ने हरियाणा प्रदेश के लिए 1990–91 का बजट पेश किया है। उस बजट को पढ़ने के बाद यह स्पश्ट झलक नजर आती हैं कि हरियाणा प्रदेश एक विकासशील प्रदेश बनने वाला हे। यह पहला बजअ है जो कर–रहित है, जिसमें कोई कर नहीं लगाया गया बल्कि इसमें कई टैक्सों में मुआफी दी गई है और राहत दी गई है। नये उद्योग जो तेजी से बढ़ रहे हैं, उनको भी कर–मुक्त रखा गया है। यह इस प्रदेश के लिए एक बड़ा सराहनीय कदम है। इसी तरह से सरकारी कर्मचारियों को काफी सहूलियतें दी गई हैं, जैसे कर्जे की लिमिट बढ़ाना, भत्ता वगैरा बढ़ाना इसमें शामिल है। कृशि और सिंचाइ के लिए पिछले बजट की निस्बत डयोढ़ा बजट रखा गया है। इसी तरह बिजली के लिए जहां पहले साल 148 करोड़ रूपया रखा गया था, इस साल 182 करोड़ रूपये की बजाये 108.70 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह से हम इस बजट को विकासशील बजट कह सकते हैं। इसके साथ ही हमारे

उप–मुख्यमंत्री ने हर छोर के लिए, हर रजबाहे के लिए और हर माईनर के लिए पानी पहुंचाने का प्रावधान किया है। इस पर्पज के लिए बजट में 90 करोड़ 20 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। आज हरियाणा को पानी की जितनी अहमियत है, उतनी किसी दूसरी चीज की नहीं और इस फैक्ट से कोई इन्कार नहीं कर सकता। खेती का सारा आधार पानी पर मुनस्सर है। इसलिए मैं आपकी मार्फत उप–मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि मेरे अपने क्षेत्र के अन्दर सराहनी माईनर, जिसकी लाइनिंग 10–15 साल पहले हुई थी, वह गलत हुई थी जिससे आज 15 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में टेल पर पानी नहीं पहुंचता। कई बार सरकार को लिखा गया है और महकमें ने भी कई बार इस विशय में रिपोर्ट भेजी है लेकिन उसमें अड़चन यह आ रही है कि वहां पर एक इरीगेशन सैक्शन है, जो यह कहता है कि लाइनिंग का काम लाईनिंग सैक्शन का है। उन्होंने ही यह गलत लाइनिंग की है और वही इसको दुरूस्त कर सकते हैं। उधर लाईनिंग सैक्शन वाले कहते हैं कि हमने लाइनिंग करके इरीगेशन डिपार्टमैंट के सुपुर्द कर दी है और आगे उनका काम है कि वह ठीक रकें या न करें। इन दोनों विग्ज की आपस की जिदद की वजह से 10 गांवों के किसानों को नुक्सान हो रहा है जिसके कारण टेल परपानी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए हमारे उप–मुख्यमंत्री को, सरकार को, इस ओर ध्यान देना चाहिए और लाईनिंग को दोबारा ठीक किया जाए। इसी तरह से लियूपुर लिफट इरीगेशन स्कीम मंजूर हो चुकी है। उसको मन्जूर हुए दो

साल हो चुके है जिसके लिए 16 लाख 82 हजार रूपया मंजूर हो चुकका है, लेनिक वह लिफट स्कीम अभी तक चालू नहीं की गई। इसके चालू होने से चूंकि सुखचैन माईनर और बबूल माईनर के शोर तक पानी पहुंचने में इमदाद मिलेगी, इसलिए इसको चालू करना निहायत जरूरी है। इस बात में बाढ़ से प्रदेश को बचाने के लिये प्रावधान किया गया है। इसके लिये खासतौर पर कुछ बजट रखा गया है। मैं इस बारे में यह अर्ज करना चाहूंगा कि सन् 1988 में जो घग्घर नदी में बाढ़ आयी थी, उसमें सिरसार जिले के अन्दर हजारों एकड़ रकबा तबाह हो गया था। न सिर्फ फसल ही तबाह हुई बल्कि गांव के गांवों के मकानात भी गिर कर तबाह हो गये थे। उस वक्त के हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री और आज के उप–प्रधान मंत्री चौ. देवी लालजी ने वहीं पब्लिक के सामने इस बात का एलान किया था कि यह बांध जहां से टूट गया है, सिरसा डबवाली रोड़ के पूर्व की ओर से इस बांध को 16 किलोमीटर तक हरियाणा की हद तक मुकम्मल कर दिया जाये। दोनों तरफ बांध बनाया जाये और आगे के लिये इस इलाके को महफूज कर दिया जाये। लेकिन अभी तक उस बांध को शुरू भी नहीं किया गया है। आगे आने वाली बरसात के समय में हमें खतरा है कि फिर उस तरह की कोई घटना न घट जाये। रंगोई नाले की चर्चा कई सालों से चल रही है। यह नाला घग्गर से फतेहाबाद होकर सिरसा की ओर जाता है। आज यह नाला तो नहीं है लेकिन उसका बहाव जरूर है जिसमें फलड का पानी जाता था। अगर वह रंगोई नाला सही मायनों में नाला बन जाये, उसको

खोद दिया जाये तो एक तो उसके घग्गर नदी में जो फ्लड आता है, कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और दूसरे उस नाले के पानी से उस इलाके को सैराब किया जा सकता है जिस इलाके में पानी की जरूरत है। उससे लाभ इस तरह से उठाया जा सकता है। इसलिये इस रंगोई नाले को जल्दी से जल्दी खोद करके इसको फतेहाबाद में, आगे सिरसा और सिरसा से आगे घग्गर नदी में डाला जा सकता है। वहां पर एक झील बनाकर उस बारानी इलाके को पानी मुहैया किया जा सकता है।

श्री सभापति: हजार चन्द जी, अब आप वाइन्ड अप करें।

श्री हजार चन्द: बहुत अच्छा जी, मैं बस खत्म ही कर रहा हूं। चलते–चलते मैं एक–आध बात और कह दूं। बिजली का जहां तक ताल्लुक है, उस बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। बिजली जिस तरीके से सारे प्रदेश के अन्दर मिल रही है, उसी से हम खेती के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल भी सवालों के समय में एक चर्चा चली कि पानी का स्तर नीचे जा रहा है। इस बारे में मैं आपको अपने जिले और साथ लगते हुए जिले हिसार के इलाके की बाबत बताना चाहूंगा। मेरे उस जिले के अन्दर इस वक्त पापी का लैवल 130 फुट नीचे चला गया है। एक कुआं बनाने के लिये और पानी हासिल करने के लिये 80000 रूपया खर्च करना पड़ता है। 80000 रूपया खर्च करके उस पर 20–25 हौर्स पावर की मोटर चलाते हैं तब कहीं जाकर उसमें तीन–साढे–तीन ईंच पानी निकाला जा सकता है।

इस वजह से वहां के किसानों को 24000 रूपया सालाना खर्च करना पड़ता है। इस तरह से उनका कुल मिलाकर 30000 रूपया सालाना खर्च हो रहा है। उसके मुकाबले में जहां पर केवल 5 होर्स पावर की मोटर लगती है, वहां पर सारे खर्चे डालकर 6–7 सौ रूपये प्रति मास का खर्च आता है। इस तरह से एक ही प्रान्त के अन्दर रहने वाले एक ही सरकार के अधीन रहने वाले किसानों के साथ इतना इम्तियाज बरता जा रहा है। इस इम्तियाज को दूर करना चाहिये। मेरा कहना यह है कि उन लोगों को इस बारे में कुछ इमदाद देनी चाहिये। उनको इस खर्चे पर सरकार द्वारा कुछ सबसिडी देनी चाहिये या उसके जो बिजली के रेटस हैं, वे कम करने चाहिये ताकि वह उससे पूरा फायदा उठा सकें। बिजली के कनैक्शन के बारे में आम चर्चा है कि किसानों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। मेरा कहना यह है कि किसानों को बिजली के मामले में पूरा महत्व मिलना चाहिये। 80000 रूपया खच्र करने के पश्चात भी अगर उसको छः महीने तक या एक साल तक कनैश्शन न मिले तो उसको उस 80000 रूपये का सूद ही लेकर बैठ जाता है। .....

श्री सभापति: हजार चन्द जी, अब आप बैठिये।

श्री हजार चन्द: बहु त अच्छा जी, धन्यवाद।

श्री हरनाम सिंह: चेयरमैन साहब, डेढ़ बजे तक हाउस चलना है और अभी तक मुझे बोलने का टाईम नहीं दिया गया है। कृपया मुझे भी टाईम दिया जाए।

श्री सभापति: आपको समय मिलेगा।

कामरेड हरपाल सिंह: चेयरमैन साहब, पोलिटिकल पार्टीज के हिसाब से आपको टाईम अलौट करना चाहिए।

श्री हरनाम सिंह: अगर आप ठीक समझें तो मुझे सिर्फ दो मिनट का टाईम दे दीजिए।

श्री सभापति: अभी नहीं।

इं. जगपाल सिंह चौधरी (नारायणगढ़): चेयरमैन साहब, वित्त मंत्री जी ने 14 मार्च को जो बजट इस सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन मैंने इस बारे में कुछ सुझाव भी देने हैं। मैं पेज वाइज बोलूंगा। चेयरमैन साहब, सफा एक पर कहा गया है कि चौ. देवी लाल भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में शोभायमान हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। मैं इसका समर्थन करता हूं। हरियाणा वालों के लिए इतनी बड़ी पदवी पर पहुंचना बहुत गर्व की बात है। इससे आगे चौ. ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कहा गया है कि वे एक बहुत ही अच्छे और्गेनाइजिंग स्किल रखते हैं। उन्होंने तीन महीने के अन्दर ही इतना अच्छा बजट सदन में पेश किया हैं तीन साढ़े तीन महीने का टाईम बहुत कम होता है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस थोड़े

समय में ही बहुत काम किए हैं। चेयरमैन साहब, मेहम के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। प्रैस में भी काफी बातें आई हैं। मेरे ख्याल में जब तक वन मैन कमीशन एक महीने तक कोई फैसला न कर ले तब तक इस बरे में चर्चा बन्द होनी चाहिए ताकि मुख्यमंत्री महोदय डिवैल्पमैंट की ओर अधिक ध्यान दे सकें। चेयरमैन साहब, पेज चार पर कहा गया है कि जो रूरल एरियाज हैं उनके लिए बजट का सत्तर फीसदी हिस्सा रखा गया है। 15.1. 90 को जब गवर्नर ऐड्रैस इस सदन में पढ़ा गया था तो उस वक्त यह ख्याल था कि 75 परसैन्ट रूरल एरियाज के लिए बजट का हिस्सा रखा जाएगा लेकिन अब सत्तर परसैन्ट ही रखा गया है। मैं चाहूंगा कि रूरल एरियाज के लिए अस्से परसैन्ट रखा जाना चाहिए। रूरल एरियाज में ड्रिकिंग वाटर की बड़ी भारी समस्या है। मेरा यह पुराना महकमा रहा है। मेरा कहना यह है कि गांवों के अन्दर पानी का अच्छा इन्तजाम होना चाहिए। दूसरे प्रदेशों में हैण्ड पम्प को वाटर सप्लाई का अच्छा साधन माना जाता है लेकिन हमारे यहां पाइप द्वारा ड्रिकिंग वाटर सप्लाई करने को अच्छा साधन माना जाता है। इससे आगे इरीगेशन का प्वायंट है। हमारे देश के लिए इरीगेशन बहुत जरूरी चीज है। हमारे यहां ताजेवाला हैड–वर्क्स है जिसकी उम्र सत्तर साल रखी गई थी लेकिन इसको सौ साल बने हो गए हैं और वह कभी भी गिर सकता है तथा हमारी इरीगेशन को धक्का लग सकता है। वहां पर जो हम हथनी कुंड बैराज बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यू.पी. सरकार से इस बारे में बातचीत करके

उसको बनाना शुरू करना चाहिए। समय पर इस बारे में फैसला कर लेना चाहिए। इसका बनाना बहुत जरूरी है। मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि टांगरी और मारकंडा पर डैम बनाए जाएं जिससे स्वायल इरोजन से बचा जा सके और डैम बनाने से जो पानी की सतह नीचे जा रही है वह भी ऊपर उठ जाएगी। चेयरमैन साहब, जहां तक फलड कन्ट्रोल का ताल्लुक है, अम्बाला क्षेत्र सब–मांउटेनियस एरिया है। इसमें बहुत जमीन फलड के कारण कट जाती है और जब तक इन छोटी–छोटी नदियों पर डैम नहीं बनाए जाएंगे तब तक स्वायल इरोजन चलती रहेगी। चेयरमैन साहब, अब मैं पावर के बारे में कहना चाहता हूं। शहजापुर में एक सब–स्टेशन मन्जूर हुआ है उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए। चेयरमैन साहब, रायपुर रानी में एक जे.ई. (वन) की पोस्ट थी उसको ऐबोलिश कर दिया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जे.ई. (वन) की पोस्ट रायपुर रानी में होनी चाहिए। नारायणगढ़ में सिवरेज का काम चल रहा है। नारायणगढ़ में सिवरेज का काम चल रहा है। मेरी प्रार्थना है कि उसको जल्दी ही पूरा किया जाए। चेयरमैन साहब, पेज नौ पर ऐग्रीकलचर के बारे में कहा गया है। मेरी प्रार्थना है कि कंडी एरिया का जो प्रोजैक्ट है वह जल्दी शुरू होना चाहिए। मुझे पता लगा है कि छछरौली और कालका फर्स्ट फेज में हैं और नारायणगढ़ बाद में है। मेरी प्रार्थना है कि नारायणगढ़ को पहले लिया जाए और छछरौली को बाद में लिया जाए।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं शूगर मिल के बारे में कहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने शहजादपुर में एक शूगर मिल लगाने का जो वायदा किया था उसके लिये कोई निश्चित तारीख फिक्स होनी चाहिये। मेरे विचार से 17.6.90 की तारीख इसके लिये ठीक होगी। अभी पिछले दिनों भारत की ऐनवायरनमैंट मिनिस्टर, श्रीमती मेनका गांधी जी ने अनाऊंसमैन्ट की थी कि हरियाणा में फोरैस्ट की डिवैल्पमैंट के लिये 138 करोड़ रूपया दिया जाएगा जिससे प्रदेश की फोरैस्ट व्यवस्था सुधरेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि फौरैस्ट विभाग इस पैसे से माउंटेनियस एरिया में छोटे छोटे डैम बनाए ताकि कृशि के लिये लोगौं को सहूलियत मिल सके।

सभापति महोदय, इससे अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने पिछली बार भी एक सुझाव दिया था कि जगाधरी से चण्डीगढ़ तक एक रेल लाईन होनी चाहिये ताकि लोगों को आवागमन में कुछ राहत मिल सके। इसके लिये मेरी सरकार भारत सरकार से यह मैटर टेक अप कर रही है, यह बड़ी अच्छी बात है। इसके लिये सरकार को प्रयत्नशील रहना चाहिये।

सभापति महोदय, हमारे मोरनी के इलाके में माइन्ज से कौपर व सीना बहुत उपलब्ध हो सकता है। अगर इसके लिये वहां पर डायरैक्टोरेट औफ ज्योलौजी एण्ड माइन्ज द्वारा सर्वे करवायें तो काफी लाभ हो सकता है। इस कार्य को अगर और ऐक्सप्लोर

किया जाए तो इससे हरियाणा की जनता व सरकार को काफी लाभ हो सकता है।

सभापति महोदय, मेरे हल्के में कोई टूरिस्ट कम्पलैक्स नहीं है। नारायणगढ़ एक सब–डिवीजन है। वहां पर लोगों की बड़ी देर से एक टूरिस्ट कम्पलैक्स की डिमांड है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर जल्द से जल्द टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाया जाए।

सभापति महोदय, इससे आगे मेरी सरकार से एक और प्रार्थना है कि सरकार जहां हरिजन विडोज के लिए 3 हजार रूपया दोबारा शादी करने के लिये देती है वहां नौन हरिजन विडोज को भी इसके लिये 3 हजार रूपये की राशि दी जानी चाहिये। उनको भी इस तरह की रियायत देने के लिये सरकार को विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, सरकारी कर्मचारियों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको फोर्थ पे कमीशन की रिकमैन्डेशंज के अनुसार वेतनमान दिये जाने चाहिये। अभी तक फोर्थ पे कमीशन की रिकमैन्डेशन्ज पूरी तरह से लागू नहीं की गयी हैं। डी.एस.पीज. और एच.सी.एस. इस बात की मांग कर रहे हैं। डी.एस.पीज. को तो 1.5.89 से ग्रेड मिल रहा है और जो एच.सी.एस. हैं उनको 1.1. 1986 से मिल रहा है। इस तरह का अन्तर नहीं होना चाहिये। सरकार इस ओर विशेश ध्यान दे, यह मेरी रिक्वैस्ट है।

सभापति महोदय, मेरे नारायणगढ़ के अन्दर कोई जुडिशियल कोर्ट नहीं है न ही कोई फायर ब्रिगेड का ही प्रबन्ध हैं इसलिये वहां पर जुडिशियल कोर्ट व फायर ब्रिगेड के साथ साथ बाई पास बनवाने का भी प्रबन्ध किया जाए। साथ ही मेरी एक और रिक्वैस्ट है कि उस इलाके के लिये स्वायल कंजर्वेशन के लिये भी पैसा मिलना चाहिये।

श्री सभापति: चौ. साहब आपने काफी समय ले लिया है। अब आप कृपया बैठिए।

इं. जगपात सिंह चौधरी: ठीक है जी। धन्यवाद।

12.00 बजे

श्री सीता राम सिंगला (गुड़गांव): चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। गुप्ता जी ने यह जो बजट पेश किया है, यह कर–रहित है। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी व जनता दल को इस हाउस में भारी बहुमत से चुनकर भेजा है। केवल पार्टी का राज बदलने से कुछ नहीं बनता जब तक कि व्यवस्था न बदली जाए। गुप्ता साहब ने यह जो बजट पेश किया है यह 31 करोड़ 19 लाख रूपये के घाटे का पूरा किये जाने की व्यवस्था हैं। वित्त मंत्री महोदय ने बिना कर लगाये यह बजट यहां पेश तो कर दिया लेकिन इसको शायद शक की निगाह से देखा जाएगा कि कहीं

कांग्रेस की तरह ये लोग भी साल के बीच में जाकर के टैक्स न लगा दें। अतः इस तरह का आश्वासन जनता को दिया जाना चाहिये कि साल के बची में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बजट में व्यापारियों और उद्योगपतियों को काफी रियायतें दी गयी हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार ने काफी रियायतें दी हैं लेकिन में कुछेक महत्वपूर्ण सुझाव यहां सदन में देना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हरियाणा प्रान्त दिल्ली के नजदीक पड़ता है। एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ चण्डीगढ़ है और इन दोनों जगहों पर टैक्स का बहुत भारी अन्तर है जिस कारण से व्यापारी लोग परेशान हैं और सरकार को टैक्स भी कम आता है और साथ ही साथ भ्रश्टाचार भी पनपता है। उदाहरण के तौर पर मैं फूड ग्रेन्ज की बात लेता हूं। इस पर हरियाणा के अन्दर 4 परसैन्ट टैक्स है जबकि दिल्ली में बिल्कुल नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि व्यापारी एंव छोटे किसान जो हैं, वे भी अपना माल हरयिाणा की मंडियों में नहीं ले जाते बल्कि दिल्ली की मंडियों में ले जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई टैक्स नहीं है। दिल्ली के नजदीक जैसे बहादुरगढ़, रोहतक और दूसरी मंडियां हैं वे बिल्कुल सुनसान पड़ी रहती हैं। अगर सरकार इस ओर विशेश ध्यान दे तो यह हरियाणा के लोगों के लिये और हरियाणा सरकार के लिये लाभदायक होगा। मैं प्रार्थन करूंगा कि फूड ग्रेन्ज पर दिल्ली की तरह से टैक्स खत्म कर दिया जाए। इसके आगे माचिस की बात है, यह बहुत छोटी सी चीज है। हर किसान मजदूर को इसकी जरूरत पड़ती है। इस पर दिल्ली के

अन्दर कोई टैक्स नहीं है लेकिन हरियाणा में इस पर 8–10 प्रतिशत टैक्स है। इतना भारी अन्तर है। ऐसा होने से सारा माल चोरी से आता है और सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता। हमें टैक्स के शेयर का भी नुकसान होता है क्योंकि बिना सेल्ज टैक्स के ये माचिसें बेची जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर टैक्स खत्म किया जाए ताकि टैक्स की चोरी बन्द हो। इसी तरह से वनस्पति घी पर हरियाणा में 8 प्रतिशत टैक्स है और दिल्ली में 5 प्रतिशत है। एक कनस्तर के पीछे 20/– रूपए का अन्तर पड़ता है। जो घी हरियाणा में बनता है वह दिल्ली जाता है और फिर वहां से नम्बर दो का बन कर हरियाणा में आता है। इस तरह से टैक्स की चोरी होती है। इसी तरह से जब बंगला देश में युद्ध हुआ था तो उस समय यहां पर शरणार्थी आए थे। उस समय उनकी सहायता के लिए सेल्ज टैक्स पर 2 प्रतिशत सरचार्ज लगाया गया था। अब वह सरचार्ज सभी स्टेटस में बन्द कर दिया गया है लेकिन हमारे यहां 2 प्रतिशत से बढ़ा कर उसे 10 प्रतिशत कर दिया गया है। क्योंकि अब वह समस्या खत्म हो चुकी है इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आवश्यकता है तो टैक्स एक परसैंट और बढ़ा दिया जाए लेकिन उस सरचाज्र को खत्म कर दिया जाए। हमारे यहां एक सेल्ज टैक्स ऐजवाइजरी कमेटी बनी हुई है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसी कमेटी नहीं बनाई थी जिसमें व्यापारियों के प्रतिनिधि शामिल हों। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सी बातें लीगल और टैक्नीकल होती हैं जिनको

व्यापारी नहीं जानते। मैं चाहता हूं कि हरियाणा की जो टैक्सेशन बार ऐसोसिएशन है उसके एक ऐसे वकील का इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो सारे कानून और कमियों को जानता हो, ताकि वह व्यापारियों को सही सलाह दे सके।

इसके बाद मैं शराब नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शराब नीति जिस तरीके से बनाई है वहा बिल्कुल ठीक नहीं है। आज कल नौजवान शराब पीने के आदी हो चुके हैं। पहले बच्चे अनाज के बदले जिस प्रकार से मिठाई की गोलियां लिया करते थे उसी तरह से आज अनाज के बदले छोटे छोटे दुकानदारों से दवातों में शराब लेते हैं। मैं चाहता हूं कि शराब बिल्कुल बन्द कर देनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। हमें इस लोभ के अन्दर नहीं आना चाहिए कि हमें शराब से रैवेन्यू ज्यादा मिलता है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। सेल्ज टैक्स विभाग के अन्दर एक औडिट ब्रांच खोल दी गई है। व्यापारी पहले अधिकारी से असैसमैंट करवाता है उसके बाद उसे फिर उस औडिट ब्रांच में बुलाया जाता है। उसके खाते दोबारा खुलवाए जाते हैं और उसे परेशान किया जाता है। वहां पर भ्रश्टाचार फैला हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि औडिट ब्रांच के अन्दर किसी व्यापारी के खाते न खुलवाए जाएं। अगर औडिट में किसी की असैसमैंट कम पाई जाती है तो असैसमैंट करने वाले अधिकारी को भी दंड दिया जाए। क्योंक यह जरूरी बात है कि अगर किसी की असैसमैंट कम पाई जाती है तो उस

अधिकारी ने उसको रिश्वत लेकर पूरा किया होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इस औडिट ब्रांच खोलने का कोई फायदा नहीं होगा। एक बात में कन्साइनमैंट टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। अब तो केन्द्र में अपनी ही सरकार है। कन्साइनमैंट टैक्स के बारे में हमें शीघ्र फैसला करवाया चाहिए इसके अलावा व्यापारियों पर फार्म न. 14 और 15 लगा रखे हैं। व्यापारियों को ये सेल्ज टैक्स के सिलसिले में लेने पड़ते हैं। इसका प्रोसीजर बहुत लम्बा है। पहले व्यापारी को ऐप्लीकेशन देनी पड़ती है उसके बाद इन्स्पैक्टर से रिपोर्ट लेनी पड़ती है और फिर अफसर के पास जाना पड़ता है। अगर कोई व्यापारी 20 फार्म मांगता है तो उसे केवल 5–7 फार्म ही मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रोसीजर को सरल कर दिया जाए। अगर व्यापारी कोई पुराना फार्म इस्तेमाल कर ले और उस बारे में इन्स्पैक्टर की तसल्ली हो जाए तो ठीक है। उस व्यापारी को अधिकारी के पास जाने की जरूरत न पड़े क्योंकि अधिकारी तो सारा साल उसके कागज चैक करता ही रहता है। सेल्ज टैकस के प्रोसीजर को सरल करने से दुकानदार और व्यापारी परेशान न होंगे।

इसके बाद मैं उद्योग के बारे में भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया था और यह घोशणा की थी कि जो आदमी बैकवर्ड एरियाज के अन्दर उद्योग लगाएगा उसको 25 परसैन्ट सबसिडी दी जाएगी। हमारी सरकार की यह घोशणा बहुत अच्छी घोशणा है। लोगों ने बैकवर्ड

एरियाज में फैक्टरीज लगा ली हैं और लोगों ने सबसिडी के लिए प्रार्थना पत्र भी दे दिए हैं लेकिन एक साल से ज्यादा समय हो गया है अब तक उनको सबसिडी नहीं रिलीज की गई है। बेरोजगारों को छोटे उद्योग लगाने के लिए जो 25 हजार और 35 हजार रूपए कर्जा देने ककी बात है यह राशि बहुत कम है क्योंकि आज के मंहगाई के जमाने में 25 हजार और 35 हजार में उद्योग नहीं लगाए जा सकते। इसके साथ साथ मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब बेरोजगार नवयुवक इन्टरव्यू के लिए जाते हैं तो अधिकारी लोग उनको 25 और 35 हजार की बजाय 10 या 15 हजार रूपये ही देते हैं जिनको वे इधर–उधर खर्च कर देते हैं और वे कर्जदार हो जाते है। (घंटी) सभापति महोदय, अभी तो मैं कुछ ही मिनट बोला हूं लेकिन आपने घंटी बजा दी। इसके अलावा अभी तो मैं केवल एक ही विशय पर बोला हूं।

श्री सभापति: आप जल्दी कीजिए।

श्री सीता राम सिंगला: सभापति महोदय, अब मैं फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमैंट से संबंधित अपनी बात कहना चाहूंगा। मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस के मामले में आज कल इतनी ज्यादा धांधली हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मिट्टी के तेल की खरीद में जनता दो प्रकार से लुट रही है। छोटे किसान व मजदूर जिनको मिट्टी के तेल की जरूरत होती है वे उसे बहुत महंगे रेट पर लेते हैं या ब्लैक में खरीदते हैं। जो मिट्टी का तेल बेचने वाले हैं उन्होंने फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमैंट के

अधिकारियों से मिल कर तेल का पैमाना भी छोटा बना रखा है। उसकी कोई चैकिंग नहीं की जाती है। मिट्टी के तेल के विक्रेता बाकयदा फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमैंट के अधिकारियों से मिले हुए हैं और उनको मंथली देते हैं। मिट्टी के तेल की खरीद में जतना लुट रही है। इस बारे में सरकार को चैंकिग करनी चाहिए। इसके अलावा जहां तक कुकिंग गैस का ताल्लुक है, वह ब्लैक में चाहे जितनी मर्जी ले लो उसकी कोई कमी नहीं होगी लेकिन वह आर्डर पर नहीं मिलती। इसलिए सरकार को ऐडमिनिस्ट्रेशन को हिदायतें देनी चाहिएं ताकि कुकिंग गैस की वितरण व्यवस्था ठीक हो सके और आम नागरिक को वह मिल सके। जहां तक फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमैंट के अधिकारियों द्वारा चैंकिग करने की बात है, इस बारे में मैं माननीय गुप्ता जी को कहना चाहता हूं कि एक पखवाड़े में चैकिंग होती है और फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमैंट के अधिकारी यहां चण्डीगढ़ से जाते हैं।

श्री सभापति: सिंगला साहब, अब आप वाईड अप करें, आपको 10 मिनट दिए जा चुके हैं।

श्री सीता राम सिंगला: ठीक है जी। वे अधिकारी किस प्रकार से चैंकिग करते हैं वह मैं आपको बताना चाहूंगा। सीमेंट ओपर मार्किट में है उसकी कोई किल्लत नहीं है। लेकिन जिन दुकानों का आपस में कंपिटिशन है उन दुकानों पर जा करके अधिकारी छापा मारते हैं। जहां पर चीनी ब्लैक में बिकती है, चावल ब्लैक में बिकते हैं और मिट्टी का तेल ब्लैक में बिकता है

अधिकारी उन राशन डिपोज पर नहीं जाते हैं। लेकिन जो सीमेंट के बड़े बड़े व्यापारी होते हैं और जो उनको कुछ पैसा देते हैं वहां पर वे जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरफ वहा ध्यान दे।

अब मैं शिक्षा के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे यहां 8वीं क्लास तक की पुस्तकें सरकार द्वारा छापी जाती हैं यानी शिक्षा विभाग उन किसानों को छापने के लिए प्रिटिंग एंड स्टेशनरी विभाग को आदेश देता है और वह छापता है। सभापति महोदय, 15–20 साल पहले से जब से सरकार ने इन पुस्तकों को छापने का काम अपने हाथ में लिया है तब से बच्चों को पुस्तकें समय पर नहीं मिल रही हैं और न ही पूरी पुस्तकें बच्चों को मिलती हैं। देहात के छोटे–छोटे बच्चे गांवों से परीक्षा पास करके बाजारों से किताबें खरीदने के लिए आते हैं लेकिन बाजारों में उनको किताबें नहीं मिलती हैं। जब दुकानदारों से बच्चे किताबें मांगते हैं तो किताबों के अभाव में लाभ उठाने के लिए दुकानदार उनको कुंजियां दे देते हैं या नोटस दे देते हैं या जो नकली किताबें छापी जाती हैं वह उनको दे दी जाती हैं।

श्री सभापति: सिंगला साहब, अब आप एक मिनट में वाईज–आप कर दें।

श्री सीता राम सिंगला: सभापति महोदय, मैं आज बोलने के लिए पूरी तैयारी करके आया हूं इसलिए मुझे आप 5 मिनट का समय और दे दें।

श्री सभापति: सिंगला साहब, बोलने के लिए टाईम तो सभी सदस्यों को देना है। अब आप वाईड अप करें।

श्री सीता राम सिंगला: सभापति महोदय, मिडल क्लासिज की पुस्तकें और हाई स्कूलों की पुस्तकें बोर्ड द्वारा छापी जाती हैं लेकिन 8वीं तक की सरकार द्वारा छपवाई जाती हैं। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार एक निगम बना दे जो मैट्रिक तक की सारी पुस्तकें छापे। ऐसा करने से खर्चा भी कम होगा और बच्चों को पुस्तकें भी समय पर मिल जाएंगी। इसके अलावा शिक्षा के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आजकल कुछ लोगों ने शिक्षा को उद्योग बना लिया है। घर–घर के अन्दर पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं। इंगलिश मीडियम के बहाने से वे लोगों को लूटते हैं। उन्होंने सरकार से मान्यता भी नहीं ले रखी है और उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनको पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। वे फीस पूरी लेते हैं। इसलिए मैं सरकर से निवेदन करूंगा कि ऐसी दुकानों को तुरन्त बंद करवाया जाना चाहिए। इस बारे में कोई न कोई कानून बना करके इस तरह की लूट को तुरन्त बंद करवाया जाए।

इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा। हर शहर के अन्दर ऐप्रूव्ड कालोनीज हैं लेकिन उनके बिजली के कनैक्शन बंद करवा रखे हैं। उनमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उनमें स्लम बने हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां आप 71 परसैंट पैसा देहात के लिए दे रहे हैं वहां आप नगरों की ओर भी ध्यान दें। यहां नगरों की वोटों से भी कुछ माननीय सदस्य चुन कर आए हैं। मेरा निवेदन है कि जो 5 करोड़ रूपए की राशि नगरपालिकाओं के लिए रखी गई है उसको बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जो सेल्ज टैक्स नगरपालिकाओं से आता है उसका आधा हिस्सा सम्बन्धित नगरपालिका को मिलना चाहिए ताकि वहां पर डिवैल्पमैंट के काम हो सकें।

सभापति महोदय एक और महत्वपूर्ण विशय की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार ने यह फैसला किया है कि नगरपालिकाओं की जमीन वहां के डी.सी. से इजाजत लेकर बेच दी जाये। इस जमीन बेचे जाने में बहुत अधिक धांधली मची हुई है। म्यूनिसिपल कमेटी वाले अब नाजायज कब्जे करवा रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि नगरपालिकाओं द्वारा जो जमीन बेची जा रही है, उस पर तुरन्त पांबदी लगाई जाये।

सभापति महोदय, अब मैं हुड्डा के बारे में कहना चाहता हूं। जो जमीन हुड्डा किसानों से ऐक्वायर करता है, उसका मुआवजा किसानों को बहुत कम दिया जाता है। जो आदमी

कोर्ट में चला जाता है उसको तो बढ़ा हुआ मुआवजा हुड्डा की तरफ से दे दिया जाता है लेकिन इसके बदले हुड्डा उस बढ़े हुए मुआवजे को खरीददारों से वसूल करता है। जब पहले ही हुड्डा वाले किसानों की 10–10 या 20–20 रूपये गज के भाव पर जमीन खरीद कर 400–400 या 500–500 रूपये के भाव पर लोगों को बेच देते हैं तो फिर बाद में उनसे बढ़ा हुआ मुआवजा क्यों वसूल किया जाता है? इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब हुड्डा की कोई पूरी कालोनी बन जाती है तो वहां की सड़कें टूट जाती हैं, प्रकाश का उचित प्रबन्ध नहीं होता और न पीने के पानी का उचित प्रबन्ध होता है, वे कालोनियां नगरपालिकाआ को ट्रांसफर कर दी जाती हैं या उनको ट्रांसफर करने की जिक्र रहता है। नगरपालिकाएं तो पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रही है। जमीनों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण हुड्डा ने जो जमीनें स्कूलों और पार्कों के लिए छोड़ी हुई थी, उनको भी बेचना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हुड्डा ने इस मंहगाई के समय सीवरेज और पानी के रेट भी बढ़ा दिए हैं। इसके साथ–साथ मैं आपको एक बड़े ही आश्चर्य की बात बताना चाहूंगा कि अम्बाला के सैक्टर–7 में हुड्डा की तरफ से 11 प्लौट काट दिए गए है और काटे गए प्लाटों की किस्तें भी संबंधित व्यक्तियों से ली गई। लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे तो वहां पर कोई प्लौट ही नहीं मिले। हुड्डा में यह बहुत अधिक धांधली हो रही है।

श्री सभापतिः अब आप बैठ जाएं, अपने पहले ही बहुत अधिक समय ले लिया है।

श्री सीता राम सिंगलाः मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त कर देता हूं।

श्री सभापतिः अब आप बैठ जाएं।

श्री सीता राम सिंगलाः ठीक है जी, यदि आप समय नहीं दे रहे तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री वेद सिंह मलिक (गन्नौर): सभापति महोदय, जो वर्श 1990–91 का बजट आदरणीय उप मुख्यमंत्री, श्री बनारसी दास गुप्ता जी, ने रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट में किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। इस बात के लिए हमारे सदन के नेता चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वर्श 1990 के दिसम्बर तक हरियाणा के सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया जायेगां इस काम के लिए भी सरकार बधाई की पात्र है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आज तक हिन्दुस्तान की किसी भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया है। आज तक हिन्दुतान की किसी भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया है। हमारे वित्त मंत्री जी इस बात के लिए भी बधाई के पात्र हैं कि कुल बजट का 70 परसैंट हिस्सा गांवों के विकास कार्यों पर खर्च होगा। यह भी एक ऐतिहासिक कदम

सरकार ने उठाया है। बिजली–पानी का प्रबन्ध करके चौ. देवी लाल जी ने और ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक अच्छी मिसाल कायम की है। आज तक कांग्रेस सरकार ने पहले कभी भी बिजली और पानी इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाया था जितनी अधिक मात्रा में आज के दिन लोगों को मिल रहा है। अब लोगों को 24 घंटे लगातार बिजली मिल रही है।

सभापति महोदय, कुछ साथियों ने मेहम की घटना का जिक्र यहां पर किया है। इस पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि 27 तारीख को बिल्कुल शान्ति से चुनाव सम्पन्न हो गया था और कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी लेकिन 8 बूथों पर दुबारा से चुनाव करने का फैसला लिया गया था। 27 तारीख को बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना नहीं हुई थी। जब 28 तारीख को 8 बूथों पर दुबारा से मतदान हुआ तो वहां पर कुछ लोग मारे गए। (विघ्न)

सभापति महोदय, मेहम के बारे में चूंकि काफी जिक्र आ चुका है इसलिए मैं थोड़ी सी बात ही कहूंगा। सभी को मालूम है कि वहां पर 28 तारीख को जैली ब्रिगेड ने पुलिस को चोटें पहुंचाई थी। लोग जैसे वहां जैलियां लेकर खड़े थे वह बहुत ही खतरनाक बात है। जैलियों से पुलिस को चोटें आई। रात को बैठकर प्रोग्राम बनाया गया कि कहां–कहां क्या करना है वहां के लोग यह बताते हैं कि उन्हें कैसे गांवों में पहुंचने के लिए कहा गया। बैंसी गांव में जितने भी लोग थे वे बाहर से आये थे। गांव

खड़क और निदाना में भी प्रि–प्लांड प्रोग्राम उन्होंने बना लिया था। (विघ्न)

श्री सभापतिः यह मामला चूंकि सब–जुडिस है इसलिए इस मामले पर आप बात न करें।

श्री वेद सिंह मलिकः सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ वहां पर हुआ वह जैली ब्रिगेड का काम था और उसके बारे में निन्दा की जानी चाहिए। जैली ब्रिगेड के लोगों ने गोहाना और रोहतक से लाखों जैलियां खरीदी क्योंकि उन्होंने गडबड़ करने का प्रोग्राम पहले ही बना लिया था और यह तय कर लिया था कि बूथ कैप्चरिंग करनी है। (विघ्न)

श्री सभापतिः इस मामले में चूंकि जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है इसलिए इस बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं होना चाहिए। आप बजट पर ही बोलें।

श्री वेद सिंह मलिकः सभापति महोदय, हमारी सरकार ने बुजुर्गो को पैंशन देने का जो महान कदम उठाया है सारे हिन्दुस्तान में इसकी सराहना हुई है। हमारे कुछ साथी अब बहुत पछता रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से उन्हें वापिस ले लिया जाए। हम कहते हैं कि वापिस लें लेंगे लेकिन पहले प्रायश्चित करो। (विघ्न)

सभापति महोदय, अब मैं अपने हल्के को 2–4 समस्याएं रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं शिक्षा के

विशय में कहना चाहता हूं कि गन्नौर में कोई भी कालिज नहीं है। गन्नोर के नजदीक जो कालिज पड़ता है वह 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गन्नौर में एक कालिज खोला जाए। इसके अतिरिक्त हमारे गन्नौर हल्के में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, जैसे बस–स्टैड और तहसील की बिल्डिंगे इत्यादि, उन्हें जल्दी–से–जल्दी पूरा किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं तथा आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर यिदा है। जय हिन्द।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं इस हाउस में निवेदन करना चाहता हूं कि बजट पर, जोकि राज्य की जनता की किस्मत का फैसला करने वाला है, बहस के लिए साढ़े चार घंटे का जो समय रखा गया है वह बहुत ही कम है। (विघ्न) मेरे विचार में जो ठीक है, और जो मैं ठीक समझता हूं, वही कहूंगा। मुझे मेरे हल्के की जनता ने इसलिए चुनकर यहां भेजा है कि मैं उनकी आवाज को इस महान सदन के सामने रखूं। सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि जिस विशय पर मैं बोलना चाहता हूं, उस बारे में मेरे साथी विधायक, जय सिंह राणा और श्रश्री जगपाल सिंह जी भी जिक्र कर चुके हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

मारकण्डा तथा अन्य नदियों को 18 लाख एकड़ फुट पानी हर साल व्यर्थ बह जाता है। उस पानी को प्रयोग करने के

लिए सरकार ने ऐलान भी किया था और इस बारे में दादूपुर नलवी स्कीम भी बनाई गई थी। जब हम वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाते थे तो विभिन्न मंचों से हमने इस बारे में कहा था और मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में आश्वासन दिया करते थे। इस बजअ में इस काम के लिए एक भी पैसा नहीं रखा गया है, जोकि बहुत ही गलत बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह हथनी कुण्ड बैराज या न्यू ताजेवाला बैराज के बारे में है। पिछले साल भी इसके लिए पैसे का प्रावधान नहीं रखा गया था। इस बैराज के लिए भी पैसा रखा जाना निहायत जरूरी है। अगर 1978 जैसी बारिश हो जाए और परमात्का न करें कि यह बैराज टूट जाए तो सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक आदि जिलों को पानी मिलना बन्द हो जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण सवाल की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस साल बिजली की पोजीशन ठीक नहीं है। पिछले साल बिजली की सप्लाई बहुत अच्छी रही, मैं इसको ऐप्रिशिएट करता हूं। लेकिन बिजली की वोल्टेज और टयूबवैल्ज की लम्बी लाईनों का सवाल उसी तरह कायम है। हम नए ट्रांसफार्मर लगाने, लाइनों को छोटा करने और वोल्टेज इम्प्रूव करने में असफल हैं। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इससे अपनी बात सड़कों के बारे में है। सड़कों की हालत बहुत खराब है। 1988–89 में या 1989–90 मे पी.डब्ल्यू.डी.

की तरफ से एक भी सड़क शाहबाद क्षेत्र में नहीं बनाई गई है। सड़कों की मुरम्मत के लिए जो पैसा रखा गया, वह भी ठीक ढंग से खर्च नहीं हुआ। इसलिए पी.डब्ल्यू.डी. महकमें को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आजकल पी.डब्ल्यू.डी. की जगह किसानों को सहूलियत देने के लिए, मार्किटिंग बोर्ड सड़कें बना रहा है। मेरे अपने हल्के में मार्किटिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर अपनी मर्जी से सड़कें बनाते हैं। जिस सड़क की जरूरत है, उसको नहीं बनाते हैं। मार्किटिंग बोर्ड का सड़क बनाने का एक मापदण्ड है। जहां किसानों की आबादी है, उस आबादी से मण्डी को सड़क से जोड़ना है या खेतों को मण्डी से जोड़ना है यह देखने की बात है। मैंने लिख कर भी दिया है कि फलां सड़क बननी चाहिए, लेकिन उस पर ऐतराज लगा दिया। एक सड़क हिसार रोड से ठोल–मण्डी तक बनाई है, इस पर कोई गांव नहीं है और किसान का कोई घर नहीं है, केवल दो शैलर हैं, उनके लिए यह सड़क बनाई है। मैंने इस बारे में लिखकर भी दिया था कि इस सड़क को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। हमारे चेयरमैन मार्किटिंग बोर्ड ने भी आदेश दिये कि यह नहीं बननी चाहिए परन्तु अब भी यह सड़क बन रही है। यह चीफ इंजीनियर के घर का सवाल नहीं है। यह मार्किटिंग बोर्ड, उसकी कोई प्राईवेट प्रौपर्टी नही है और न ही यह कोई प्राईवेट कारपोरेशन है कि जहां मर्जी आये, स्टेट का पैसा लगा दे। मैं समझता हूं कि इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए और जहां सड़कों की आवश्यकता है वहीं सड़कें बनानी चाहिएं।

अब मैं पुलिस महकमें के बारे में कहना चाहता हूं। मैं मेहम के बारे में तो नहीं कहना चाहता लेकिन मैं कल करनाल एक मीटिंग में गया थां मुझे कुछ साथियों ने ऐसे इश्तहार दिये हैं जो पानीपत में बांटे गये थे। में इस इश्तहार को होम मिनिस्टर साहब को दे दूंगा। यह इश्तहार पहले से बड़ा है। इसमें बहुत से योद्धाओं के नाम लिखे हुए हैं और इश्तहार में एक मांग भी है जो पहले की मांगों से भिन्न है। मैं समझता हूं कि यह हमारे पुलिस चौकसी विभाग की कमजोरी है कि वे पानीपत में इस तरह के इश्तहार बांट कर सुरक्षित चले गये। मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे चेले जाते हैं? जब हरियाणा में आग लग जायेगी क्या उस वक्त हमारी सी.आई.डी. चौकस होगी? हो सकता है कि हमारे यहां भी विदेशी साजिश हो रही हो और हरियाणा में भी वे आग लगाना चाहते हों। इसलिए हमारी सरकार को जागरूक होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही खास बात है।

अब मैं टूरिजम और डिजनी लैंड के बारे में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। यह डिजनी लैंड का मामाल बड़ा ही विवादास्पद है। इस स्कीम का मुअत्तल करना चाहिए क्योंकि हमारे टूरिजम डिपार्टमैंट ने पहले ही काफी टूरिजम स्पौटस बना रखे हैं। ये टूरिजम स्पौटस 10 प्रतिशत इस्तेमाल होते हैं लेकिन इनसे कोई विशेश आमदनी नहीं होती। यह कहा जाता है कि हम हरियाणा को नो–टैक्स स्टेट बना देंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर ये बड़ा बोझा डालेंगे क्योंकि अभी हमने

251 करोड़ रूपये का ब्याज देना है जो इसी बजट से देना है। अगर हम 2 अरब रूपया कर्जा और ले लेंगे तो हमारे सिर पर और ब्याज चढ़ेगा। डिजनी लैंड की स्कीम से चूंकि हरियाणा को कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस स्कीम को मुअतल किया जाए और दोबारा विचार किया जाए।

आखिर में मैं जनरल ऐडिमिनिस्ट्रेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मुलाजिमों के साथ हमने सरकार को चलाना है, सारे प्रबन्ध करने हैं। मैं समझता हूं कि उनकी समस्याओं का सरकार को समाधान करना चाहिए। पिछले साल जो बिजली की हडताल हुई थी, उसमें करीब 12000 लोगों की सजा के तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान को बदली कर दी गई थी। मैं समझता हूं कि यह एक परिवार का झगड़ा था और हमें इसको परिवार के तोर पर ही लेना चाहिए था। अब इसका समाधान होना चाहिए ताकि हमारे अन्दर कोई कड़वाहट न रहे। जो लोग बदले गये हैं, उकने उनके घरों के नजदीक रखना चाहिए और जो आदमी काम ने करें उन्हे सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ दूसरा पहलू यह भी है कि कुछ सरकारी कर्मचारी दफतरों में ठीक काम नहीं करते। मैं सबके बारे में नहीं कहता, लेकिन कुछ आदमी काम ही नहीं करते। इस बारे में हमारे जो चीफ सैक्रेटरी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस कमेटी को जल्दी काम करना चाहिये और हर टेबल का काम निर्धारित होना चाहिये कि इस टेबल पर इतना काम होना

चाहिये। इर फाईल का सफर निर्धारित होना चाहिए कि इस फाईल को इतनी देर से सफर तय कर लेना चाहिये। जो लोग काम नहीं करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

आखिर में मैं लोकल बौडिज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर लोकल बौडीज का काम किस तरह से चल रहा है। हमारे शाहबाद में लोकल बौडी को ही ले लीजिये। पैसा तो लोकल बौडीज के पास होता नहीं है। जो छोटे–छोटे लोग होते हैं, उनकी तहबाजारी बढ़ दैंगे। सात गुना टैक्स बढ़ाकर भेजेंगे। 2 से बढ़ाकर 20 रूपये टैक्स कर देंगे। वहां पर एक आदमी पहले म्यूनिस्पिल कमेटी का प्रैजीडैंट था। उसको लीज पर जमीन दी गयी थी। 4330 वर्ग गज का प्लौट 125 रूपये में लीज पर दिया गया। अब उस की चार–पांच सौ रूपये साल की लीज होती है। यह सन् 1968 की बात है। सरकार से उसकी मंजूरी लेनी होती है। 1974 में वह सरकार से लीज कैसिल हो गयी। जिस तरह से वह लीज दी गयी थी, आज भी वह उसी तरह से है। वहां पर पंजाब नैशनल बैंक है, कोल्ड स्टोरेज है और कई दुकानें बनी हुई हैं। हजारों रूपये वह आदमी ले रहा है। लेकिन यह कहते है कि उसको पांच साल का नोटिस दिया है। लीज अगर 9–10 साल के लिये दे दी जाये तो उसको कैंसिल करने के बाद 5 साल को नोटिस देने का प्रोवीजन है लेकिन जो अवैध कब्जा है, उसको भी लीगल चैनल में डाल दिया गया है। 1968 में लीज दी गयी, 1974 में वह कैंसिल कर दी गयी। अब उसको

नोटिस दिया गया है। मैं यह कहता हूं कि करप्शन की तरह से यह उसकी मदद करना है।

मैं अब शिक्षा के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि स्कूल हमारे स्कूल मास्टर्ज के बिना खाली पड़े हैं। उनमें मास्टर नहीं है। दूसरी तरफ मास्टर्ज बेरोजगार हैं। हमारे प्राईवेट स्कूलों के स्कूल टीचर्ज के साथ अन्याय हो रहा है। पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की काफी गिनती होते हुए भी, पढ़ाने के लिये स्कूलों में कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं अपनी बात को और ज्यादा लम्बा न करते हुए यहीं पर खत्म करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री भागी राम (ऐलनाबाद–अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया है। उपमुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने जो 1990–91 के बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की तारीफ किये बिना नहीं रह सकता कि बिना टैक्स के बजट सरकार की तरफ से पेश हुआ है। वाकइ में इस बात के लिए लोग इस सरकार को बधाई देते हैं कि बिना टैक्स का बजट पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अखबारों में इस बता की चर्चा आनी चाहिये थी कि बिना टैक्स के बजट पेश किया गया है। सैंटर में सांझा मोर्चे की सरकार आने के बाद यह जो विधान सभाओं के चुनाव हुए हुए, इन विधान सभाओं के चुनावों में हिन्दुस्तान के लोगों ने

परिवर्तन लाने का काम किया है। इस बात को भी अखबारों में चर्चा आनी चाहिये थी। यह चर्चा आनी चाहिये थे कि सत्ता की सब जगहों पर लोगों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यह बात तो कम से कम आनी ही चाहिये थी। इस सबकों छिपाने के लिये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मेहम के कांड को चर्चा का विशय बनाया गया। इस वजह से वह अखबारों में ज्यादा नहीं छपा। यदि यह कहा जाए कि शरारती तत्व, या जिस किसी किस्म से उनको कह लो, ही बार–बार मेहम–मेहम कह रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहने जा रहा था कि जहां इस किस्म की बात होनी चाहिए थी उसकी बजाए असली बात छिपाने के लिए मेहम की चर्चा अखबारों में, गली ओर गलियारों में शुरू कर दी। हमारे अपोजीशन के भाई, हमारे कांग्रेस के भाई जो सारे हिन्दुसतान में पिट चुके थे उन्होंने चौ. देवीलाल को बदनाम करने के लिए मेहम का सहारा लिया। सारे हिन्दुस्तान में और सभी अखबारौं मैं इस किस्म की चर्चा चल रही है। अध्यक्ष महोदय, 27 फरवरी को मेहम का चुनाव हुआ। सुबह चुनाव शुरू हुआ था और शाम को जब ढोलकें बन्द हुई तक तक मेहम कांस्टीचूऐंसी के किसी वोटर ने पोलिंग आफिसर के पास जाकर शिकायत नहीं की और न ही कोई दरखास्त दी और न डांगी ने और न ही उसके किसी पोलिंग एजेन्ट के कोई दरखास्त दी कि कहीं पर कोई धांधली हुई है। शाम के पांच बजे तक ठीक ढंग से पोलिग हुई है। मेहम के बहादुर लोगों ने अपने–अपने वोट ठीक ढंग से डालने का काम किया। शाम के पांच बजे सभी पोलिंग ऐजन्टस ने, तकरीबन सभी

ने, साइन किए कि सही ढंग से सारी जगह पोलिंग हो गई है। जब शाम को सब जगह के एजेन्टस इक्ट्ठे हुए तो एक दूसरे से पूछने लगे कि तुम्हारे यहां केसा रहा, तुम्हारे यहां कैसे रहा। सब अपने–अपने गांवों का जिक्र करने लगे। किसी ने कहा कि मेरे गांव में तो चौटाला को अस्सी परसैन्ट वोट डले, किसी ने कहा कि मेरे गांव में 75 परसैन्ट वोट डाले। अध्यक्ष महोदय, ऐसा भी हो सकता है कि किसी गांव में चौटाला साहब को कम वोट डले हों। जब उनको यह पता लगा कि चौटाला को काफी वोट डले हैं तो डांगी समर्थक और ** जो हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते थे, दिल्ली में इक्ट्ठे हुए।

श्री अध्यक्ष: दो नम्बर वाले आदमी के शब्द रिकार्ड पर न लाए जाएं।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मीटिंग करके एक स्कीम बनाई कि किस ढंग से चौ. देवी लाल को बदनाम किया जाए। उस समय मीटिंग में यह बात नहीं थी कि चौटाला साहब इस्तीफा दें बकि चौ. देवी लाल को बदनाम करने की साजिश रची गई। चौ. देवी लाली को बदनाम करने का ाडयन्त्र रचा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमोर कई साथी जो हमारे सांझे मोर्चे में थे, भी अपोजीशन पार्टीज के लोगों के साथ मिल गए। अगर मेरे वे साथी मेहम में जो साजिश हुई थी उसका पर्दाफाश करते और अगर चौटाला साहब की जरा भी गल्ती होती तो हम उनका साथ देते।

अध्यक्ष महोदय, हम वहां गए हैं और श्री हजार चन्द भी वहां गए थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस के साथ किन लोगों की मुठभेड़ हुई थी?

श्री बलवीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह मैटर सब–जुडिस हैं लेकिन * * * * कौन है यह जनता बताएगी।

श्री अध्यक्ष: चौ. बलबीर सिंह जी आप कृपया बैठें। भागी राम जी 28 तारीख का जिक्र नहीं करना है क्योंकि मामला सब–जुडिस है।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि 27 तारीख को जब चुनाव समाप्त हुआ तो किसी ने भी कोई दरखास्त नहीं दी कि चुनाव में कोई घपला हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपका टाईम समाप्त हो गया है। आप कृपया बैठिए। अब फाईनैंस मिनिस्टर साहब बोलेंगे।

श्री भागी राम: सिर्फ दो मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं आपका समय समाप्त हो गया है। आप कृपया बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मुझे बोलने की इजाजत दी जाए।

Mr. Speaker: I am sorry, I will not allow you to speak at this stage. ऐप्रोप्रिएशन बिल पर आपका नम्बर आएगा। आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लेना।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब .....

Mr. Speaker: Sh. Bhagi Ram Ji, you please take your seat. I will not allow you to speak now.

(इस समय कुछ सदस्यगण बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष: औनरेबल मैम्बर्ज, आपने बिजनैस ऐडवाजरी कमेटी की रिपोर्ट को ऐक्सैप्ट किया है। उसमें बजट डिसकशन के लिए दो दिन का टाईम दिया गया था। आज दूसरा दिन है और फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने भी अभी जवाब देना है। इसलिए आप कृपया बैठिए।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय .....

Mr. Speaker: Sh. Bhagi Ram Ji, I will not permit you to speak now. You please take your seat.

श्री भागी राम: * * * *

Mr. Speaker: Bhagi Ram Ji, you are now speaking without my permission and whatever you say will not be recorded.

श्री भागी राम: * * * *

Mr. Speaker: Bhagi Ram Ji, how are you speaking without permission? You please sit down.

श्री भागी राम: * * * *

Mr. Speaker: Bhagi Ram Ji, I would not allow you to speak without permission. I have already ordered that whatever you are saying without permission is not to be recorded. Please take your seat.

श्री भागी राम: * * * *

Mr. Speaker: Sh. Bhagi Ram, Please sit down and allow that House to proceed.

वाक आउट

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मुझे इस सैशन में बोलने का बिल्कुल ही समय नहीं दिया गया है। हमारा यहां पर बोलने का राईट बनता है लेकिन * * * * (शोर)

Mr. Speaker: Comrade Sahib, you will get opportunity on Monday.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं तो बजट पर ही बोलना चाहता हूं। (शोर)

Mr. Speaker: Comrade Sahib, it is not possible today. You will get opportunity on Monday.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, * * * * (शोर) मैं तो अपनी पार्टी का अकेला ही सदस्य हूं। (शोर)

Mr. Speaker: Comrade Sahib, you please sit down. I have already told you that you will get opportunity on Monday. (Interruptions).

कामरेड हरपाल सिंह: मैं चूंकि सरकार की निन्दा करता हूं, क्या इसलिये मुझे बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है?

Mr. Speaker: There is no such thing. You please take your seat and let the House proceed further.

कामरेड हरपाल सिंह: अगर मुझे बोलने के लिये समय नहीं दिया जाना है तो मैं वाक–आडट करता हूं (इस समय कामरेड हरपाल सिंह सदन से वाक–आउट कर गए)

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, कामरेड हरपाल सिंह जी ने अभी बोलते हुए यह कहा * * * * यह चेयर पर ऐसपर्शन है। ये शब्द कार्यवाही में से निकाल दिये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। ये शब्द रिकार्ड पर न लाए जाए।

वर्श 1990–91 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। यहां सदन में बजट पर बोलने के लिये समय न देकर मेहम के इशू पर ही ज्यादा डिस्कशन का टाईम दिया गया है, जिसके कारण कई मैम्बर साहेबान बजट पर बोलने से वंचित रह गये हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि बजट पर डिस्कशन का

समय और बढ़ा दिया जाए ताकि बोलने के इच्छुक सदस्यों को भी बजट पर बोलने का अवसर मिल सके।

श्री अध्यक्षः रावत साहब, आप बैठिये, अब गुप्ता जी बोलेंगे।

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरी अदब के साथ आपसे प्रार्थना है कि जिन साथियों को बजट की आम बहस पर बोलने का मौका नहीं मिला है उनको ग्रान्टस के ऊपर बोलने का मौका अवश्य दिया जाए। मैं चाहता हूं कि हरेक माननीय सदस्य को यहां पर बोलने का अवसर मिलना चाहिये, ताकि वह अपने विचार व्यक्त कर सकें। वे चुनकर आये हैं और उनको अपने–अपने क्षेत्र के बारे में यहां पर अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, मैंने यही कहा है कि जो लोग नहीं बोल सके उनको मन्डे को बोलने का टाईम मिलेगा। यह बात तो मैंने पहले ही कह दी थी लेकिन उन्होंने तो वाक आउठ करना था इसलिये कर गये।

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, दो दिन तक लगातार वर्श 1990–91 के बजट पर आम बहस हुई। बड़े अच्छे माहौल में बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है और मेरे कई साथियों ने बड़े अच्छे ढंग से अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा बड़े ही रचनात्मक सुझाव भी दिये हैं। जो हमारे में कमियां थीं, बजट में

कमियां थीं, किसी हैड में, किसी विभाग में कोई कम प्रावधान हुआ था उसके बारे में भी खास चर्चा की है। मैं इन सभी सुझावों का स्वागत करता हूं और सरकार की और से यकीन दिलाता हूं कि जो भी रचनात्मक सुझाव हैं उनके बारे में यथा सम्भव प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर अमल करने की पूरी पूरी चेश्टा की जायेगी।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मुझे आज फिर दुख और खेद के साथ कहनी पड़ती है कि यद्यपि इस बजट में, मेरी बजट स्पीच में किसी स्थान पर भी मेहम का कोई जिक्र नहीं है, कोई मांग नहीं है, बजट से उसका कोई संबंध नहीं है लेकिन मेरे कुछ साथियों ने बजट पर बोलते हुए भी मेहम की रट उसी प्रकार लगाई रखी जैसे पहले हर मौके पर लगाते थे। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा मालूम होता है कि कहीं डाक्टर गोयबल्ज का भूत हरियाणा में पहुच गया है और उसका साया कही उन पर पड़ा है। उसी बात को और उसी सिद्धान्त को कुछ साथी अपना रहे हैं कि एक झूठ और गलत बात को यदि सौ बार दोहरा दिया जाए तो वह बात सत्य हो जाती है। इस बात में वे किसी हद तक सफल भी हुए हैं। सारे देश में इसका चर्चा चला और आज भी चल रहा है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आज मेहम के दुखद विशय पर अधिक समय नहीं लूगा और अधिक बातें नहीं कहूंगा क्योंकि सरकार की तरफ से इस पर वक्तव्य आ चुका है जो समाचार पत्रों में बड़े अच्छे तरीके से छपा है। सप्लीमैंटरी ग्रांटस पर हुई बहस

के जवाब में भी मैंने बड़े विस्तार से मेहम के बारे में चर्चा की थी। बड़े विस्तार से सरकार का पक्ष यानी वर्शन यहां सदन में प्रस्तुत किया गया था। उसकी पब्लिसिटी भी समाचार पत्रों द्वारा हुई है। इसके बावजूद भी इन्होंने मेहम की रट लगाए रखी। इसमें, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, अधिक नहीं कहूंगा। पहला आरोप मेहम के उप–चुनाव को लेकर हम पर यह लगाया जाता है कि 27 तारीख को बड़े लार्ज स्कूल पर रिगिंगओर बूथ कैप्चरिंग हुई और बहुत गड़बड़ हुई। एक आरोप तो हम पर यह लगाया जाता है। इस संबंध में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बार–बार अपनी सफाई दी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई शिकायत किसी ने नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां तक निवेदन किया कि जहां गांव में मतदाता दो गुटों में बंट जाएं और उन गुटों के व्यक्ति सबल जाति के हों तो वहां किसी पक्ष या किसी उम्मीदवार के समर्थक के लिए रिगिंग करना, बूथ कैप्चरिंग करना या बोगस पोलिंग करना बहुत कठिन बात है। अध्यक्ष महोदय, आप ीाा जानते हैं कि मेहम के उप–चुनाव के अवसर पर उस क्षेत्र के कितना भारी तनाव था, कितनी भारी खिचावट हो चुकी थी ओर दोनों पक्ष पूरी तरह से अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए तैयार थे या सतर्क थे। आपने यह भी देखा होगा कि जहां इतना खिंचाव हो जाता है, कंटेस्ट इतना हार्ड हो जाता है, वहां परसैटेज औफ पोलिंग भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यदि एक कैडीडेट कमजोर होता है तो उसके समर्थक भी अधिक नहीं होते, उसके वर्कर्ज भी कम होते हैं और वहां पर

पोलिंग की परसैटेज भी कम होती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि यद्यपि उस दिन मौसम खराब था और बारिश हो रही थी, उसके बावजूदर भी लोगों ने डट कर वोट डाले, चाहे वह किसी के पक्ष में डाले। बाकायदा पोलिंग बंद हुई, बक्से बंद हुए सभी उम्मीदवारों के ऐजैंट वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बक्से बंद किये गए और उनके हस्ताक्षर करवाए गए। उस समय किसी ने कोई प्रोटैस्ट नहीं किया, सिकी ने कोई विरोध नहीं किया। ये सारी बातें सदन में कही जा चुकी हैं हालांकि आरोप लगाने वाली कोई बात नहीं है। मान लो आरोप लगाने की बात का कुछ अंश ठीक भी है तो अध्यक्ष महोदय इसका फैसला मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। जनता दल हाई कमांड की सिफारिश पर चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने, जो चुनावों के मामले में फाईनल अथौरिटी है, सुप्रीक बौडी है उसने यह निर्णय दे दिया कि मेहम हल्के का उप–चुनाव पुनः करवाया जाए। उसके बाद भी क्या कोई शिकायत बाकी रह जाती है? मुझे तो पता नहीं है कि उसके बाद भी कोई शिकायत बाकी रह जाती है। इसके बाद हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सरकार और चीफ इलैक्शन कमिश्नर को इतनी बड़ी औफर दी कि मेहम के उप–चुनाव को हम कंडक्ट नहीं करवाएगें बल्कि इसे कंडक्ट करवाने के लिये केन्द्रीय सरकार के और अपने भरोसे के 100 फीसदी अधिकारी लगा लें। इसके अलावा सुरक्षा के लिए भी यह कहा है कि आपके पास पैरा मिलिटरी फोर्स है, मिलिटरी फोर्स है उसको लगा दें। जब यह निर्णय हो चुका और हरियाणा सरकार ने यहां तक औफर दे दी

तो बाकी क्या रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, चाहे इस बारे में आप ही निर्णय दे दें कि क्या कोई गिला या बात रह जाती है जिसके कारण ये उसी बात की रट लगाएं रखें, क्योंकि आप ही इस सदन में सुप्रीम और सर्वोच्च हैं। अध्यक्ष महोदय, चाहे बजट हो, चाहे सप्लीमैंटरी ग्रांस्ट हों, चाहे किसी सामाजिक बात पर चर्चा चल रही हो और चाहे किसी और समस्या पर चर्चा चल रही हो इनको तो केवल मेहम ही नजर आ रहा है। हर बात में कह रहे हें मेहम–मेहम–मेहम। यह कोई उचित बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके इलावा हमारे खिलाफ इनको यह शिकायत भी है कि मेहम के उप चुनाव में बहुत दर्दनाक घटरना हिंसा की हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां पर दुर्भाग्यपूण्र घटना हुई है। लेकिन उसके जिम्मेदार कौन हैं, इस बात का निर्णय कौन दे? हम कहेंगे सारा दोश दांगी का है और दांगी कहेगा सारा दोश सरकार का है। इसका कौन निर्णय करेगा? अध्यक्ष महोदय, एक ही तो ऐसी संस्था है जो न्याय करेगी और वह है, जुडीशियरी। इस बारे में जुडीयिरी की जांच के लिए न किसी की मांग थी और न ही आन्दोलन हुआ फिर भी सरकार ने अपने आप ही यह आदेश दे दिया कि इस बारे में न्यायिक जाचं करवाई जाए। किसी रिटायर्ड जज सै नहीं बल्कि सीटिंग जज से करवाई जाए। उस माननीय जज को यह भी रिक्वैस्ट कर दी गई है कि एक महीने के अन्दर अन्दर न्याय मूर्ति महोदय अपने रिपोर्ट दे दैं। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए। इतना कुछ करने के बाद भी क्या शिकायत रह जाती है?

अध्यक्ष महोदय क्या हमारे साथियों का जुडिशियरी पर से भी विश्वास उठ गया है? क्या न्याय विभाग पर भी उनको भरोसा नहीं रहा? यदि ऐसा है तो फिर तो कोई ठिकाना नहीं है।

फिर कोई न्याय के लिए कहां जाएंगे? चुनावों के मामले में सर्वोच्च जो शक्ति है वह है मुख्य चुनाव आयोग। उसने भी अपना निर्णय दे दिया। जो हिंसात्मक घटनांए हुई या जो हमारे नौजवानों को खून बहा बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके लिए हाई कोर्ट के जज के जिम्मे इन्क्वायरी लगा दी गई है। फिर तो किसी को कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए? मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि ये दो बातें होने के बाद यानी ये निर्णय लिए जाने के बाद फिर भी यदि मेहम की बात की जाये तो उसका क्या औचित्य है। इसका साफ मतलब है कि हमारे जो विरोधी है भाई हैं और जो हमारे भाई हमारे से खिलाफ होकर चले गए हैं, किसी कारणवश हमसे नाराज हो गए हैं, वे अपना राजनीतिक स्वार्थ साधन करना चाहते हैं। उनके मन में किसी के खून बहने का दुख नहीं है, उन्हें कोई अफसोस नहीं है। इन लोगों को किसी बात का कोई दर्द नहीं है। वे तो सिर्फ इस दशू को बार बार उठाकर अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं।

डा. किरपा राम पुनिया: आन ए प्वायंट औफ आर्डर सर। गुप्ता जी ने मेहम के उप चुनाव के बारे में अब तक जो बैकग्राउंड बताई है वह इलैक्शन कमीशन की फाईडिंग आने के

बाद की बताई हैं। इलैक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि वहां पर औफिशियल मशीनरी का बड़ा भारी दुरूपयोग किया गया है। इस बारे में आप खुद निर्णय दें कि जो ये चर्चा कर रहे हैं, क्या वह उचित है?

Mr. Speaker: This is no point of order. Please take your seat.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ये दो बातें होने के पश्चात किसी भी साथी को कोई गिला नहीं रह जाना चाहिए था और न किसी को कोई शिकायत की गुंजाइश रहनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट की बात करूंगा। हमारा आज का असली विशय तो बजट ही है। अगर ये भाई बजट पर बोलते, जैसे बहन सुशमा जी बोली तो अच्छा होता। बहन सुशमा जी ने बोलते हुए अच्छे सुझाव दिए और काफी नुक्ताचीनी भी की। हमने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने हमारी कमियां भी बतलाई। जो बातें उन्होंने कही हैं मैं उनका जवाब भी दूंगा। बहन कमला जी भी बोली और सिंगला जी भी बहुत अच्छे बोले। इसी प्रकार से हमारी साइडज्ञ के भी कई साथी काफी अच्छा बोले हैं और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बातें कहीं हैं उन्होंने बहुत अच्छे–अच्छे सुझाव दिए हैं और अपने–अपने क्षेत्र की कमियों के बारे में हमें बताया है। इसकी हमें खुशी हैं कांग्रेस की तरफ से भी दो नौजवान साथी बोले हैं। एक बात की तो मैं महेन्द्र प्रताप

सिंह जी को और कैप्टन अजय सिंह यादव जी को दाद देता हूं और सराहना किए बगैर नहीं रह सकता कि वे सारा समय सदन में बैठे तो रहे। अब पता नहीं वे मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं। यह तो इनकी बड़ी भारी हिम्मत कहै। इनके दूसरे साथी तो आने का साहस ही नहीं करते। एक रोज बलबीरपाल शाह नजर आए थे। हमारे साथी चौ. वीरेन्द्र सिंह जी उन्हें बलबीर पाल शाह की बजाये बुल्लेशाह कहा करते थे। चौ. असलम जी भी एक दो बार तशरीफ लाये हैं। थोडे–थोडे समय के लिए महेन्द्र प्रताप सिंह जी और अजय हसंह भी बोले और अपने अपने हल्के की बातें कीं। उन्होंने बोलते हुए कहा कि यह बजट विकासशील नहीं है बल्कि नीरस है। अब विकास की परिभाशा इनके लिए क्या है, मैं तो समझ नहीं पाया। यह बजट किस हिसाब से नीरस है, इसमें कौन सा रस नहीं है यह मैं नहीं समझ पाया। 9 रस बतलाये जाते हैं उनमें से कौन सा नहीं है या सारे ही रस नहीं है, इस बारे में तो वे ही बता सकते हैं (विघ्न) डाक्टर साहब ने फरमाया था कि इनका तो एक ही रस है जैसे वीभत्स रस। वह तो हमारे बजट में होगा ही नहीं। यह रस तो कांग्रेस के ही बजट में हो सकता है।

चौ. वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आदरणीय उप–मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि मैं श्री बलबीर पाल शाह को बुल्ले शाह ''कहा करता था'' मैं अब भी कहता हूं as I am stillalive.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मुझे चौ. वीरेन्द्र सिंह जी माफ करें। क्योंकि मैं गलती से ''कहा करता था'' कह गया।

श्री अध्यक्ष: बुल्ले शाह तो बहुत बड़े आदमी थे। पंजाबी लिट्रेचर में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, दो साल यानी 1987–88 और 1988–89 के पूरे फिगर्ज मेरे पास है जिनका मैं जिक्र करनार चाहता हूं। 1989–90 का साल तो 31 मार्च को खत्म होगा। 1987–88 में भी कुछ महीने बाद यानी जून में हमने सत्ता सम्भाली थी। ये आंकड़े इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्य में हुए विकास को प्रदर्शित करते हैं। इन आंकड़ों से अन्दाला लगाया जा सकता है कि 2 साल में स्टेट का विकास हुआ या नहीं। मेरे वे साथी कहते हैं कि किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ और जो भी विकास हुआ और जैसे आज हरियाणा नजर आता है वह कांग्रेस शासन में ही विकास हुआ था उसकी बाबत मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने अर्ज करता हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश की खुशहाली और विकास को मापने का सबसे बड़ा पैमाना प्रति व्यक्ति आय हैं 1986–87 में जब तक कांग्रेस का रिजीम था प्रति व्यक्ति वार्शिक आय 3947 रूपये थी जो दो साल में बढ़ कर 5274 रूपये प्रति व्यक्ति हो गई है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर विकास नहीं हुआ तो फिर यह प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार बढ़ी? यह विकास खेती में, पानी में, बिजी में, उद्योग

आदि में ही तो हुआ है। यह तो साफ पैमाना है। दूसरी बात खाद्य उत्पादन की है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश एक कृशि प्रधान प्रदेश है। हमारे यहां की आर्थिक व्यवस्था, हमारे यहां की इकोनोमी खाद्य उत्पानी पर डिपैंड करती है, अगर किसान के खेत में अच्छी फसल पैदा होती है तो किसान खुशहाल होता है। किसान के खुशहाल होने सें गांव के लोगों को, भूमिहीन कृशि मजदूरों को काम मिलता है और दूसरे कामगरों को भी रोजगार मिलता है। अध्यक्ष महोदय, जब किसान अनी फसल लादकर मण्डी में आता है तो आढ़ती को मुनाफा होता है, मण्डी वालों को काम मिलता है। किसान जब अपनी फसल बेचकर नोट जेब में डालकर वापिस आता है तो कपड़ा खरीदता है बर्तन खरीदता है, बच्चों के लिए मिठाई खरीदता है और सब्जी खरीदता है मन करे तो रिक्शा में बैठता है और सिनेमा भी देखता है। (विघ्न) इस प्रकार सभी को काम मिलता है। अध्यक्ष महोदय, कृशि उत्पादन पर ही प्रदेश की खुशहाली निर्भर है। हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में जब किसान के खेत में पैदावार बढ़ती है तो हर व्यक्ति के घर में खुशहाली आती है। हर व्यक्ति के घर में खुशहाली तक आती है जब किसान के घर में खुशहाली आती है और किसान के घर में खुशहाली तब आती है जब उसके खेत में ज्यादा पैदावार हो। अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य उत्पादन के कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1986–87 में अनाज का कुल उत्पादन 76.28 लाख टन हुआ और 1988–89 में यह उत्पादन बढ़ कर लगभग 95. 05 लाख टन हुआ। अध्यक्ष महोदय, क्या यह विकास नहीं है?

इसको आप विकास नहीं तो और क्या कहेंगे? (व्यवधान)। 1989–90 की फिगर्ज अभी आई नहीं है लेकिन वे इससे बढ़ी ही हैं।

Sh. Parma Nand: To put thhe record straight, I want to have a clarification. In his budget speech the Deputy Chief Minister has mentioned that कुल उत्पादन 93.66 लाख टन होने की आशा है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर हमारी रबी की फसल शामिल नहीं है।

Sh. Parma Nand: That will come next year. You are misleading the House.

13.00 बजे

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि कार्तिक यानी नवम्बर के महीने में रबी की फसल की बिजाई हुआ करती है और उसकी कटाई अप्रैल में जाकर होती है, वह भी इसमें शामिल होगी। (विघ्न)

Mr. Speaker: Parma Nand Ji, you please take your seat and let the House proceed.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं सभी साथियों से प्रार्थना करूगा कि वे टोकाटाकी न करें। इस साल की जो फसल की फिगर्ज बजट स्पीच में छपी हैं, वह अनुमान हे।

अध्यक्ष महोदय आप ऐसे क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां फसलों की सिंचाई टूयबवैल्ज से होती है। आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां फसलों की सिंचाई टयूबवैल्ज से होती है। आपके क्षेत्र में टयूबवैल्ज पर सिंचाई का काफी दारोमदार है। हरियाणा में और भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां ग्राउंड वाटर पर डिपैंड करते हैं। सिंचाई के जितने अधिक साधन होंगें किसान की उतनी ही पैदावार बढ़ेगी ओर जितनी पैदावार बढ़ेगी, उतनी ही किसानों में खुशहाली बढ़ेगी। सन् 1986–87 में टयूबवैल्ज की संख्या 416703 थी लेकिन 1988–89 में यह बढ़कर 445881 हो गई। इस प्रकार से 7 परसैन्ट की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 37 परसैन्ट हुई है। इलैक्ट्रिक कनैक्शन्ज 1986–87 में 1864644 थे, लेकिन ये बढ़कर 1988–89 में 2170139 हो गये है। यह वृद्धि 16 परसैन्ट हुई है। लघु उद्योगों की संख्या 1986–87 में 74100 थी, यह बढ़कर 1988–89 में 86338 हो गई है। इसमें भी 17 परसैन्ट की बढ़ोतरी हुई है। बड़े और मध्यक्ष उ़द्योग 1986–87 में 366 थे, लेकिन अब 393 हो गये हैं। इसमें 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन उद्योगों से उत्पादन 1986–87 में 222300 लाख रूपये का हुआ था लेकिन 1988–89 में यह बढ़कर 259014 लाख रूपये का हो गया है इसमें 17 परसैन्ट की वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय, दूध उत्पादन किसानों का एक सहायक धंधा है जिस प्रकार से अन्न के उत्पादन में बढौतरी हुई है, उसी प्रकार से दूध के उत्पादन में भी बढौतरी हुई है। दूध उत्पादन से

किसानों के घर में खुशहाली बढ़ती है, बीमार और बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक बनाये रखने के लिए दूध परम आवश्यक है। दूध का उत्पादन जहां 1986–87 में 26.24 लाख टन था, वहां 1988–89 में 28.80 लाख टन उत्पादन रहा है। इसमें 10 परसैन्ट की बढ़ौतरी है। इसी प्रकर से पशु अस्पताल पशुओं की सुरक्षा के लिए और उनकी बीमारी की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी हैं। 1986–87 में 815 अस्पताल थे, परन्तु 1988–89 में बढ़कर 926 हो गये हैं। इनमें 14 परसैन्ट की वृद्धि हुई है। जन स्वास्थ्य विभाग ने पीने के स्वच्छ पानी की 198687 में 4676 विलेजिज में सुविधा उपलब्ध कराठ थी। अब यह बढ़कर 5475 विलेजिज तक पहुंच गयी है। अध्यक्ष महोदय, नये मुख्यमंत्री आने के बाद इस नयी सरकार की ओर से अब एक घोशणा हुई है। एक टारगैट फिक्स किया गया है कि इसी साल 31 दिसम्बर तक प्रत्येक गंव में पाईप्ड वाटर यानी पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाया जायेगा। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है स्कूल भवनों की मुरम्मत के लिये नौन प्लान साईड पर 102.50 लाख रूपये का प्रोवीजन किया गया है। स्कूलों की मुरम्म के लिये प्लान साईड पर 230 लाख रूपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल भवनों की मुरम्मत के लिये इस प्रकार से कुल 332.50 लाख रूपये का प्रावधान करने का प्रबन्ध किया गया है। इन सब बतों के बावजूद अध्यक्ष महोदय हमारे कांग्रेसी भाई

यह इलमाज लगा रहे थे कि यह विकासशील बजट नहीं है, इन बजट के अन्दर कोई विकास की बात नहीं है और जब से यह सरकार बनी है तब से विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। विपक्ष की सरकार आने के बाद कितना विकास हुआ है उसकी जीती जागती तस्वीर के आंकड़े मैंने आपके माध्यम से हाउस में प्रस्तुत किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ साथियों ने, हमारे जो वरिश्ठ साथी है, जैसे श्री हीरा नन्द आर्य ने इस बजट का समर्थन करते हुए अपने कुछ उदगार व्यक्त किये हैं। उन्होंने यह कहा कि करों की चोरी को रोका जाये। उन्होंने यह बिल्कुल सही बात कहीं है कि नये टैक्स लगाने की बजाये यह रेट औफ टैक्स बढ़ाने की बजाये अगर टैक्सों की चोरी को रोका जाये तो अध्यक्ष महोदय, नये टैक्स लगाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह बात मैं समझता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही कही है। मैं इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। सप्लीमैंटरी ग्रांटस की बहस का जवाब देते हुए भी मैंने एक बात की मिसाल दी थी कि किस प्रकार से हमने बर्तनों पर टैक्स 12 परसैन्अ से घटाकर 3 परसैन्ट किया लेकिन फिर भी हमारी आमदनी नहीं घटी। हमने गुड़ बारदाने दाल, खली आदि 65 आईटम्ज पर रेट औफ टैक्स कम किया है। चोरी भी टैक्सिज की तभी घटेगी जब रेट औफ टैक्स कम किया जायेगा और टैक्स का रेट तुलनात्मक दृश्टि से ठीक होगा तो आमदनी बढ़ेगी। सिगला साहब की यह बात बिल्कुल सही

है कि हरियाणा के तीनों तरफ दिल्ली लगता है। हमें दिल्ली के तीन तरफ होने के कई लाभ हैं और कई नुक्सान भी हैं। दिल्ली में रेट औफ टैक्स बहुत कम हैं। एक दो वस्तुओं पर तो टैक्स है ही नहीं। जैसे सिंगला साहब ने कहा कि दिल्ली में फूड ग्रेन्ज पर कोई टैक्स ही नहीं है। उसका परिणाम यह हुआ है कि हरियाणा की फरीदाबद बहादुरगढ़ सोनीपत, बल्लभगढ़ आदि की मंडियां उजड़ गयी है। दिलली के अन्दर जो पहले छोटे छोटे गांव होते थे, जैसे नजफगढ़, नरेला और नागंलोई, वहां शानदर मंडिया बन गयी हैं। हमने इसके विरूद्ध आवाज उठायी है। जब पिछले दिनों राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो मुख्य मन्त्रियों की, कन्सर्ड मन्त्रियों और वित्त मन्त्रियों की एक बैठक बुलाढ गई थी। उसमें भी हमने जोर के साथ यह बात उठाई थी कि यूनिफार्मिटी औफ टैक्स रेट सारे देश में होना चाहिये ताकि सारी बीमारी खत्म हो सके। अगर सारे प्रदेशों में और दिल्ली में करो की समान दर हो तो चारी, समगलिंग और भ्रश्टाचार जैसी बुराईयां कम हो सकती है। अब केन्द्र में हमारी नई सरकार आई है। अीाी हम प्लानिंग कमिशन के साथ डिस्कशन करने के लिए गए थे। तक हमने यह प्रश्न उठाया था और मैं आशा करता हूं कि वह बात सारे देश में लागू होगी और हर प्रदेश में बिक्री कर की दर एक समान होगी। श्री हीरा नन्द आर्य और एक दो अन्य सदस्यों ने कहा कि गाडगिल फार्मूलें का विकल्प होना चाहिए। जैसा मैंने बताया था कि हमने एक वैकल्पिक फार्मूला योजना आयोग के सामने पेश किया है। योजना आयोग के सामने वह वैकल्पिक फार्मूला पहले भी पेश किया था

और अब भी किया है और जहां तक हमारा प्रयत्न होगा इस फार्मूले में परिवर्तन कराएंगे ताकि विकासशील प्रदेश जो अपनी मेहनत से, जनता के परिश्रम से और अपना पसीना बहाकर डिवैल्पमैंट करना चाहते हैं उनको इनाम मिले उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बात आर्य जी ने और कही कि प्रशासनिक अधिकारियों की बढ़ती हुई संख्या पर रोक लगाई जाए। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि यू.पी. और हरियाणा में आई.ए.एस. अफसरों की संख्या बराबर है जिसे कम किया जाए। मुझे उत्तर प्रदेश की संख्या के बारे में तो पता नहीं है लेकिन हरियाणा के अन्दर 233 आई.ए.एस. अधिकारियों की संख्या नियत की गई है और यह जो संख्या नियत होती है वह प्रादेशिक सरकार केन्द्रीय सरकार के साथ बैठकर तय करती है। हमने कुछ कमिश्नर और आई.ए.एस. अफसर बढ़ाए हैं क्योंकि चार जिले नए बनाए गए हैं। दो कमिश्नर की पोस्टस बढ़ाई हैं, चार डिप्टी कमिश्नर्ज की पोस्टस बढ़ाई हैं ओर चार ए.डी.सी. की पोस्टस बढ़ाई हैं। इस तरह चार जिले नये बन जाने से दस पोस्टस बढ़ाई हैं। फिर भी नके सुझाव पर विचार किया जाएगा। जहां तक संख्या कम हो सकेगी, कम की जाएगी।

सुशमा जी ने बहुत अच्छे सुझाव बजट के बरे में दिए है और हमारी कुछ कमियां बताई हैं। मैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। उन्होंने एक तो शब्द के प्रयोग के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि उद्विग्नता शब्द नहीं होना चाहिए था। मैं उनकी, बत को

मानता हूं। वह शब्द उपयुक्त नहीं है। यह गल्ती हुई है। भाशण बनाने वालों से और हमसे यह गल्ती हुई है। भविश्य में इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि उपयुक्त शब्द ही आने चाहिएं। एक बात उन्होंने यह कही कि बजट पेश हेने के दो तीन दिन बाद बहस का समय रखना चाहिए। बात उनकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं हरियाणा में ऐसा देखता रहा हूं कि बजट पेश होने के अगले दिन ही बहस शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाशण और बजट एक ही अधिवेशन में आये हैं। ऐसे हालात में पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर एक दो दिन बहस होती है और फिर बहस खत्म होने के बाद बजट पर बहस शुरू हो जाती है। इस प्रकार कुछ समय माननीय सदस्यों को सारे आंकड़े देखने के लिए मिल जाता है। अध्यक्ष महोदय, भविश्य में हम समय जरूर देंगे। यह जरूरी बात है लेकिन मैं औनरेबल मैम्बर्ज से एक रिक्वैस्ट करूंगा कि समय तो हम दे दिया करेंगे लेकिन सभी सदस्य बहन सुशमा स्वराज की तरह बजट पढ़ने का कश्ट भी किया करेंगे। सुशमा जी ने आगे कहा कि बजट भाशण को देखने से जाहिर होता है कि सातवीं पंचवर्शीय योजना में 2900 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था लेकिन 2900 करोड़ के मुकाबले 2567 करोड़ रूपए खर्च होना सम्भावित हैं। योजनागत खर्च में कमी केवल पूरे योजनाकाल में ही नहीं हुई हैं बल्कि चालू साल में भी यही हालत है। इससे यह आभास होता है कि खर्च में कमी की वजह से विकास कार्यो में कमी आयी है। अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है। इसमें कोई संदेह

की बात नहीं है कि अगर खर्च में कमी होगी तो विकास कार्य प्रभावित होंगे ही लेकिन मैंने बजट स्पीच के अन्दर वे कारण बताए है कि किन मजबूरियों के कारण हमें दो साल लगातार वार्शिक योजना पर कट लगाना पड़ा, और उसका असर यह हुआ कि सातवीं पंचवर्शीय योजना कम हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी बता देना चाहता हूं कि किस लिए ऐसा हुआ। फोर्थ पे कमीशन की सिफारिशों को हमने इम्पलीमैंट किया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश था जिसने इसको सबसे पहले लागू किया और इससे 516 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार हम पर पड़ा जबकि 1987–88 के अन्दर हमारा प्लान 585.75 करोड़ रूपये का था। इसी प्रकार से तेल, पैट्रोल, कोयले की कीमतें बढ़ जाने से हमारा खर्चा 170 करोड़ रूपया बढ गया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी। इसी तरह प्रति वर्श ऐसे असम्भावित खर्चे हुए जिनकी वजह से हमारा नौन प्लान का खर्चा बढ़ा और योजना में कटौती करनी पड़ी। मौजूदा साल में खर्चों में कमी न होने के कारण भभी हमने बता दिए हैं। इस साल लगभग 33 करोड़ रूपये की राशि महंगाई भत्ते के तौर पर दी गई और 20 करोड़ रूपया न्यायालयों के आदेशानुसार अध्यापकों के देना पड़ा जिसका बहन सुशमा जी को भी पूरा ज्ञान है। इन्होंने बोलते हुए यह इशारा किया था कि इसके लिए इनको भी दोशी ठहराया जाएगा। बहन जी यह दोश न हमारा है न आपका। जो जुडीशियरी का फैसला होता है, वह सब को मान्य होता है। हमने माना और मानना भी था कानून व्यवस्था को सुधारने के लिये 13

करोड़ रूपये और 9 करोड़ रूपये के अतिरिक्त खर्चे के रूप में नालों व जल पूर्ति की स्कीमों में रख रखाव के लिये खर्च किया गया। इसलिये जिन खर्चो का हमें अन्दाजा तक नहीं था, जो अनसीन खर्चे थे उन खर्चो को करने के लिये योजना में कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं सदन को एक बात का और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो विकास की गति थी उसमें बहुत कमी नहीं आयी है। यह ठीक है कि जो हम विकास के कार्य करना चाहते थे, जो टारगेट पूरे नहीं हुए, वे टारगैटस हमने बड़ी आशा के साथ, संभावना के साथ रखे थे कि हम उनको पूरा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब भी टारगैटस फिक्स किये जाते है वे ऐम्वीशियस होते है और उनको अच्छी तरह से देखभाल कर रखा जाता है ताकि प्रदेश का विकास तेजी से हो सके। वे पूरे नहीं हो सके जिसके लिये हमें खेद है।

अध्यक्ष महोदय, उदाहरण्या के तौर पर मैं एक ओर बात कहना चाहूंगा कि हमारा 1989–90 के बजट का जो आउट–ले था, उसमें नहरों की लाईनिंग के लिये व खालों की लाईनिंग के लिये 33.73 करोड़ रूपये का प्रावधान था, लेकिन उस पर हमारा लगभग 72 करोड़ रूपये का खर्चा आया। अगर यह खर्चा न करते, नहरों की लाईनिंग व वाटर कोर्सिज की मुरम्मत का कमा वार लैवल पर न करते तो स्टेट को बड़ा भारी नुक्सान होता। बहन सुशमा जी ने एक बात और कही कि आठवीं पंचवर्शीय योजना के दृश्टिगत कार्य नीति को स्पश्ट रूप नहीं दियागया जबकि हमारी नीति पार्टी के

सत्ता में आने से पहले तैयान की गयी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बहिन जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार की नीति की बात नहीं है। हमारा अभिप्राय यह था कि अगले साल में किस विभाग के किस हैंड पर कितना खर्च कर पाएंगे, उसका पूरा कार्यक्रम और नीति तब तक निर्धारित नहीं की जा सकती जब तक हमें योजना आयोग से अगले साल के लिये मिलने वाली राशि का पता न चल सके। उसके बगैर कैसे बता सकते हैं कि आगामी योजना का स्परूप क्या होगा। तो इस शक्ल में नीति शब्द का प्रयोग यिका गया है वरना जो नीति हमारी सरकार की है या राश्ट्रीय मोर्च की है वह घोशित है और उस नीति पर अमल करने के लिये हम काफी प्रयत्नशील हैं। यहां पर पेय जल की बात आई कि उसके टारगैट पूरे नहीं हुए। हमने इस साल 31 दिसम्बर तक सारे गांवों में पानी पहुंचा देना है। इसलिये पिछला सारा घाटा इस साल में पूरा हो जाएगा। एक बात बहिन जी ने, हमने जो घोशणा की थी कि किसान के खेत और सड़क अथवा नहर, के बीच में जो दरख्त लगे हुए हैं उनका आधा हिस्सा हम किसानों को देते हैं, उसके बारे में कही। वे जानना चाहती थी कि किसानों को कितना पैसा दिया गया है? सरकार की इस नीति के तहत किसानों के 6282 वृक्ष दिए गए है और 45835 रूपए नकद दिए गए हैं। बद मैं किसानों को वृक्ष हमने इसलिये देने शुरू किए हैं क्योंकि किसानों की यह शिकायत थी कि अधिकारियों द्वारा नीलामी में वृक्ष सस्ते बेचे जाते हैं।

जहां तक स्कूलों को अप ग्रेड करने की बात है, जो नीति बहिन जी ने अपनाई थी उसको इस साल भी ध्यान में रखा जाएगा।

एक बात यहां पर यह आई कि सभी विधायकों को मौके पर ले जाकर एस.वाई.एल. नहर दिखाई जाए। बंसी लाल ने तो पंचों और सरपंचों को दिखाई थी मैं सदस्यों से कहूंगा कि वे कोई तारीख तय कर लें हम मुख्यमंत्री जी से बात करके सब को वहां ले चलेंगे ताकि वे देख सकें कि वहां अब तक क्या प्रगति हुई है।

प्रौढ शिक्षा के बारे में कई साथियों ने प्रश्न उठाया। सुशमा जी पूरी तरह से इस बात को जानती है कि हमको किस तरह प्रौढ़ शिक्षा की योजना को बन्द करने पर मजबूर होना पड़ा। इस बारे में कल ही शिक्षा मंत्री जी ने हय आश्वासन दिया था कि जो उनमें ट्रेड और अच्छे पढ़े लिखे आदमी है उनको हम ऐकमोडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंअ औफ और्डर है। यह बहुत अच्छी बात है कि ये ट्रेंड आदमियों को एकोमोडेट करेंगे लेकिन जिनकी 15–15 साल की सर्विस हो गई है क्या उनको भी एकोमोडेट करेंगे?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया है कि ट्रेंड और पढ़े लिखे लोगों को एकोमोडेट करने की पूरी

कोशिश करेंगे। कंज्यूमर्ज के बारे में भी बहिन जी ने कहा था। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए एक सीनियर जज की नियुक्ति हो चुकी है, डी.सीज. को अख्तियार दिए गए हैं और फील्ड मशीनरी को पूरी तरह से यह काम दे दिया गया है। अब हम 15 मार्च से 31 मार्च तक उपभोक्ता पखवाड़ा भी मनाने जा रहे हैं।

वृद्धावस्था पैशन के बारे में बहन सुशमा स्वराज ने आर्य साहब ने और डाक्अर हरनाम सिंह जी ने जिक्र किया कि वह चूंकि मनीआर्डर द्वारा दी जाती है इसलिये उस पर 5 करोड़ रूपए कमीशन पर खर्च हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब तो हमारे नेता ही नहीं बल्कि सारे राश्ट्र के नेता चौ. देवी लाल जी की यह ख्वाहिश थी और उन्होंने यह कहा था कि मैं चाहता हूं बूढ़ों को चारपाई पर लेटे हुए ही 100 का नोट दिया जाए। उनको बैंक में न जाना पड़े या किसी और जगह पर न जाना पड़े। इसके लिए कई सुझाव और विकल्प हमारे सामने आए एक बार डी.सीज. को मीटिंग बुलाई गई थी और शायद उसमें बहन सुशमा स्वराज भी मौजूद थी। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि जो बेरोजगार ग्रेजुएटस है उनके थ्रू यह पैंशन बंटवाने का काम करवाया जाए। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अगर यह काम बेरोजगार ग्रेजुएटस से करवाना है तो उनसे पहलें गारंटी लेनी पड़ेगी, सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि यह रकम का मामला है। इस बारे में डी.सीज. विचार कर रहे हैं

और सरकार भी विचार कर रही है कि किस तरह से यह काम बेरोजगार ग्रेजुएटस के माध्यम से करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, पुनिया साहब ने बजट के सम्बन्ध में एक ही बात कही बाकी तो वे मेहम के उप चुनाव के बारे में ही बोले हैं। उन्होंने कह कि जहां सरकार एस.वाई.एल. कैनाल को मुकम्मल करवाने के लिए बहुत उत्सुक है और इसी साल में उसको मुकम्मल करवाना चाहती है वहां उसके लिये केवल 15 करोड़ रूपए का प्रोवीजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पुनिया साहब और सदन को सूचित करना चाहता हूं कि उसके लिये पैसे का प्रावधान चाहे कितना ही किया गया हो, इस काम के लिए पैसे का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार करती है। लेकिन इस मामले में खर्चा करने के लिये यदि हमें 50 करोड़ रूपये की जरूरत हुई तो वह भी खर्च किया जाएगा क्योंकि यह पैसा तो केन्द्रीय सरकार देती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी स्पीकार करता हूं कि पिछली केन्द्रीय सरकार ने भी एस.वाई.एल. कैनाल के निर्माण के लिए पैसा देने में कोई देरी नहीं की लेकिन उस सरकार को यी नीयम नहीं थी कि इस सरकार के रहते यह नहर पूरी हो। अब उसके निर्माण की गति भी तेज हुई है। हमारे आदरणी मुख्यमंत्री जी और चौ. वीरेन्द्र सिंह जो एस.वाई.एल. नहर को देख आए हैं और दोनों महानुभाव केन्द्रीय नेताओं से मिल चुके है। इस बारे में प्रधान मंत्री जी से भी बात हुई है कि इस साल में इस नहर को पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आतमा

राम गोदारा जी ने बजट का समर्थन किया है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने हल्के की कुछ बातें कही हैं। वे सारी मैंने नोट कर ली है। उन पर ध्यान दिया जाएगा और पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मास्टर शिव प्रसाद जी ने कुछ बातें रखी हैं वे भी मैंने नोट की हैं। उन्होंने एक बात खास तौर से कही है कि हुड्डा के प्लाटस और हाउसिंग बोर्ड के मकानों की कीमतें बार बार ऐनहास की जाती है और वे लोगों को देनी पड़ती हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि जब भी हुड्डा द्वारा प्लौटस या हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाकर दिए जाते हैं तो ऐग्रीमेंट में यह लिखा होता है कि अगर कोर्ट जमीन की कीमत बढ़ा देती है तो वह प्लौट होल्डर्ज से वसूल की जाएगी। स्पीकर साहब जमीन के मालिक कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट उनका जनरली पैसा बढ़ा, देती है जिसकी वजह से ये कीमतें प्लौट होल्डर्ज से वसूल करनी पड़ती हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पांच मिनट बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक हैं जी, पांच मिनट बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय पांच मिनट बढ़ाया जाहात है।

वर्श 1990–91 के बजट पर सामानय चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी कही गई है कि विधवाओं और विकलांगों को भी 100 रूपए पैंशन दी जाए। हमने पिछले दिनों ही विधवाओं और विकलांगों की पैंशन 50 रूपए से बढ़ा कर 75 रूपये की की है। इसके अलावा श्री कैलाश चन्द शर्मा ने भी कुछ बातें कहीं। उनकी कुछ बातें तथा–कथित डिजनीलैंड से संबंध रखती है। गुड़गांव में जो मनोरंजब पार्क बनाया जाना है उसके बारे में आपने आधे घंटे की डिस्कशन के लिए समय दे दिया है, इसलिये इस बारे में सारी बाते उस समय की जाएगी। इसके अलावा श्री जय सिंह राणा ने तरावड़ी में एक कालेज खोलने की बात कही। मैं उनके बताना चाहूंगा कि अगले साल कालेज खोजने का सरकार का विचार है। जहां भी वह खोलना होगा उसके बारे में सोच विचार करके फैसला किया जाएगा। इन्होंने करनाल डिपों में बसों की कमी का भी जिक्र यिका है। इसी प्रकार से दूसरे साथियों ने भी बताया कि उनके एरियाज में बसों की बहुत कमी है। इस कमी के बारे में मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि इस कमी को दूर करने के लिए 500 नई मिनी बसें खरीदी जा रही हैं और मैं आशा करता हूं कि इन बसों के आ जाने की कमी पूरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, डाक्टर हरनाम सिं हजी ने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं। उन पर गौर किया जायेगा। इसी प्रकार से श्री हजार चन्द कम्बोज और चौ. जगपाल सिंह जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं। चौ. जगपाल सिंह जी ने बताया कि बरसात के दिनों में मारकण्डा का पानी बेकार जाता है और तबाही मचाता है। उन्होंने सुझाव दिया

है कि इसके लिए कोई स्कीम बनाई जाये जिससे इस पानी को किसानों के लिए युटिलाईज किया जा सके। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सरकार का इस तरफ पूरा ध्यान है कि कोई ऐसी स्कीम बनाई जाये जिससे इस पानी को यूटिलाईज किया जा सके। सरदार सरदूल सिंह जी ने सुझाव दिए हैं उन पर भी गौर किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक नगरपालिकाओं का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हरियाणा की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय है। वे अपने अपने ऐम्पलाईज को कई बार वेतन तक नहीं दे पातीं। जब उनकी ऐसी हालत हो तो वे विकास के क्या काम कर पाएंगी। इसके लिए मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार ने पहली बार एक म्यूनिसिपल ग्रांट कमीशन बनाया है। पहले इस कमीशन के चेयरमैन श्री राम लाल वधवा जी होते थे। वे इस विशय के ज्ञाता थे। अब इस कमीशन के चेयरमैन श्री कान्ति प्रकाश भल्ला जी हैं। मैं आशा करता हूं कि इस कमीशन की जल्दी ही रिपोर्ट आएगी। जो भी सुझाव इस कमीशन की तरफ से आएंगे सरकार उनको इम्पलीमैंट करेगी। (विघ्न)

आवाजें: वधवा साहब, ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी हे। यदि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है तो हामरे अधिकारी उस पर विचार कर रहे होंगे अब चूंकि श्री कान्ति प्रकाश भल्ला जी इस कमीशन के चेयरमैन हैं, हो सकता है

कि वे भी अपने कुछ और सुझाव सरकार के समाने रखें। इसलिये दोनों के सुझावों को कम्पाईल करके उन पर विचार करेंगे।

श्रीमती कमला वर्मा: कृपया शमशान घाट की सड़कों को ठीक करने के बारे में भी कह दीजिए।

श्री बनारसी दास गुप्ता: इनको भी दूसरी सड़कों की तरह ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे माहौल में दो दिन तक इस बजट की बहस में हिस्सा लिया, चाहे वे किसी भी पक्ष के थे। दो दिनों तक सभी साथियों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। इन सब सुझावों को तो मैं इस समय जिक्र नहीं कर सका लेकिन उनके सभी सुझावों पर गौर किया जायेगा। कुछ हमारे साथी बजट पर बोलने से रह गए हैं। अभी ऐप्रोप्रिएशन बिल और बजट की डिमांडज अनी हैं बचे हुए साथी उस समय बोल सकेंगे और अपने सुझाव हमारे सामने रख सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में सदन को यह यकीन दिलाता हूं कि जो साथियों के रचनात्मक सुझाव आए हैं या आएंगे उन सभी पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, में आपके द्वारा सदन के सभी सदस्यों को प्रार्थना करूंगा और आशा करता हूं कि इस शानदार बजट को वे सर्वसम्मपति से पास करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस सोमवार 19 मार्च 1990, बाद दोपहर 2.00 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

***13.33 बजे**

(तत्पश्चात सदन सोमवार दिनांक 19 मार्च 1990, बाद दोपहर 2.00 बजे तक *स्थगित हुआ)।